3 राजधानी
एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव व लिपिक को सजा

6 अभिमत
ग्रामीण आर्थिक विकास की रूपरेखा

11 विदेश
कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर विरूपित किया गया

12 स्पोर्ट्स
महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 271
लखनऊ, बुधवार, 24 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

बजट 2024-25

www.dailypioneer.com

रेलवे का बड़ा ध्यान सुरक्षा संबंधी कार्यों पर

राष्ट्रीय-10

मध्यम वर्ग को कर राहत, रोजगार सृजन पर जोर

फोटो: रंजन डिमरी

राहुल दत्ता। नई दिल्ली

मध्यम वर्ग तक पहुंचते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बड़ी आयकर राहत की घोषणा की और कहा कि चार करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को बदलावों से लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करते हुए, उन्होंने स्टार्टअप्स में निवेशकों के सभी वर्गों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त कर दिया, मोबाइल फोन और सोने पर सीमा शुल्क में कटौती की और पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा ने अगले पांच साल में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों- बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का भी ऐलान किया। भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के लिए ग्रामीण असंतोष और बेरोजगारी को जिम्मेदार माना गया है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है।

सीतारमण ने अपना सातवां और नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। जब कोई गैर-सूचीबद्ध या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका मूल्य कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर एंजल कर लगाया जाता है। हालांकि, वित्त मंत्री ने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को बढ़ा दिया। इस कदम से शेयर बाजारों में गिरावट आई। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए एक्सप्रेसवे, बिजलीघर, हेरिटेज कॉरिडोर और नए हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की। यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार को वित्तीय समर्थन पूंजीगत परियोजनाओं के रूप में है। यह सब्सिडी या नकद सहायता के रूप में नहीं है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू (जनता दल यूनाइटेड) राज्य के लिए आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता के रूप में (शेष पेज 9)

ग्राफिक : सतीश सी जखमोला

सरकार ने कुर्सी बचाओ बजट पेश किया है जिसमें सहयोगियों को खुश करने के लिए दूसरे राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए गए हैं। यह बजट कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट की नकल है -**राहुल गांधी,** नेता प्रतिपक्ष, का एक्स पर एक पोस्ट

भारत के युवाओं, नारी शक्ति और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए, बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर देश की गति को बढ़ाएगा - **अमित शाह,** केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा

युवाओं के लिए खोला खजाना

राजेश कुमार। नई दिल्ली

आलोचकों को चुप कराते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को रोजगार सृजन के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया और इसी तरह रोजगार के मुद्दे को हल करने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, जिसके लिए भाजपा सरकार को पिछले दो कार्यकाल के दौरान आलोचना का सामना करना पड़ा था। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रोजगार के लिए घोषणा की थी, दोनों योजनाएं ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर केंद्रित होंगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ा होगा। यह योजना कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महीने (शेष पेज 9)

सुनहरे भविष्य वाला बजट: मोदी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समाज के हर वर्ग के लिए किए गए उपायों के लिए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि इसने बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश करने के बाद उन्होंने टेलीविजन पर अपनी टिप्पणी में कहा, बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और विकसित भारत के लिए एक ठोस नींव रखेगा। मोदी ने बजट में युवाओं, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के साथ-साथ विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की सराहना की और कहा कि प्रस्तावित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं करोड़ों नई नौकरियां पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेहतर वृद्धि (ग्रोथ) और सुनहरा भविष्य लेकर आया है। (शेष पेज 9)

नई कर व्यवस्था में संशोधित दर

- 0-3 लाख रुपये — शून्य
- 3-7 लाख रुपये — 5 प्रतिशत
- 7-10 लाख रुपये — 10 प्रतिशत
- 10-12 लाख रुपये — 15 प्रतिशत
- 12-15 लाख रुपये — 20 प्रतिशत
- 15 लाख रुपये से अधिक — 30 प्रतिशत
- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500/- तक की बचत होगी।

होम बायर्स को फायदा, रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा जोश

रिंकू यादव। नोएडा

साल 2024-25 का आम बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ हद तक खुशी लेकर आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों को स्टांप ड्यूटी कम करने का सुझाव दिया। इसके बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट बाजार को सकारात्मक उम्मीद जगी है। डेवलपर्स का कहना है कि इससे घर खरीदारों को लाभ होगा और वे घरों की ओर निवेश की ओर उत्साहित होंगे। इसका सीधा लाभ सेक्टर को होगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व शहरी घरों को बनाने में सरकार दस लाख करोड़ से अधिक का फंड खर्च करेगी।

मनोज गौड़, अध्यक्ष, क्रेडाई एनसीआर और सीएमडी, गौड़ ग्रुप के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी घोषणा 10 लाख करोड़ रुपए का शहरी आवास के लिए निवेश है। यह देश में किफायती आवास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा। उच्च मांग के बावजूद, इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है क्योंकि बजटरी सपोर्ट की कमी थी। 30 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा।

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर, संजय शर्मा का कहना है कि सरकार ने 11.1 लाख करोड़ का आवंटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा, अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ रोजगार सृजन के लिए खर्च किए जाएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी घटाने की सलाह दी गई है, जिससे खरीदारों को रजिस्ट्रेशन की लागत कम होगी। अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप के अनुसार यह बजट भारत-केंद्रित है। सरकार की लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, युवाओं को कौशल प्रदान करने, एमएसएमई को सशक्त करने और शहरी आवास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना व्यापक विकास की ओर इशारा करती है। वित्त मंत्री का राज्यों से स्टांप ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव एक प्रोत्साहक कदम है जो आवास की मांग और विकास को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाओं पर ध्यान देना शहरी विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है। स्पेक्ट्रम मेट्रो के वाइस प्रैजिडेंट सेल्स व मार्केटिंग अजेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे, रोजगार, युवाओं की स्किल, छोटे और मध्यम उद्योगों और शहरी आवास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें स्टांप शुल्क घटाने और टीओडी और औद्योगिक पार्क बनाने पर जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचे के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे रोजगार और स्किल के विकास के साथ वाणिज्यिक संपत्तियों की वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग व बिजनेस मैनेजमेंट सलिल कुमार के अनुसार प्रदेश सरकारों को स्टांप ड्यूटी कम करने का जो सुझाव दिया गया है वह बेहद सकारात्मक कदम हैं। इससे लाखों फ्लैटधारकों को लाभ होगा और रजिस्ट्री में उनका खर्च कम होगा। लंबे समय से कई संगठन यह मांग उठा रहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसके अलावा शहरों में घरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का का निवेश एक बड़ा कदम है जिसके दूरगामी प्रभाव बेहद सकारात्मक होंगे।

बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य

- इसमें माता-पिता और अभिभावक करेंगे योगदान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की। सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक योगदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के उपायों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत नियोक्ताओं द्वारा खर्च की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में समाधान विकसित किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का हल करेगा और राजकोषीय सूझबूझ सुनिश्चित करेगा।

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में जरूरत होने पर किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटने का फैसला किया था और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है। लोकसभा में अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में समाधान निकाला जाएगा। इसके तहत राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती रहती है।

अदालत ने जीएम सरसों पर दिया खंडित फैसला

- पर्यावरण में उत्पादन और परीक्षण के लिए छोड़ने पर केंद्र के फैसले को चुनौती

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सरसों की संकर (हाइब्रिड) किस्म डीएमएच-11 को बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण में छोड़ने के केंद्र सरकार के वर्ष 2022 के फैसलों की वैधता पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़े जाने की सिफारिश करने के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 18 अक्टूबर, 2022 के फैसले और उसके बाद 25 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11 को पर्यावरण में छोड़े जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।

जीईएसी आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों के लिए देश की नियामक संस्था है। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अलग-अलग राय दी। पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया, ताकि कोई दूसरी पीठ इस पर फैसला दे सके। हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का केंद्र को एकमत से निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से पहले सभी हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श करे और यदि इस प्रक्रिया को चार महीने में पूरा कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जीएम फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर, 2022 को दिए गए जीईएसी के निर्णय दोषपूर्ण थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे।

बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज की सौगात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू *फाइल फोटो*

- बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रहस्यमय प्रतिक्रिया व्यक्त की

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी शासित बिहार और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई, लेकिन केंद्र द्वारा 'विशेष श्रेणी का दर्जा' देने से इनकार करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रहस्यमय प्रतिक्रिया व्यक्त की। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ जदयू नेता की राजनीतिक पैंतरेबाजी को देखते हुए दिन के दौरान राजनीतिक भाषाएं लड़खड़ाती रहीं। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन द्वारा विशेष दर्जा की उनकी मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिए जाने के एक दिन बाद पटना में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, आपको धीरे-धीरे सभी चीजें पता चल जाएंगी। नीतीश ने हाल ही में अपनी पार्टी के एक प्रस्ताव का पेश किया था, जिसमें विशेष दर्जे की मांग और इस मुद्दे पर भाजपा को सशर्त समर्थन की बात दोहराई गई। हालाँकि, शाम तक नीतीश ने दावा किया कि बजट 'विशेष सहायता की हमारी मांग को पूरा करता है, यदि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विशेष दर्जा देना संभव नहीं था।'

जेडीयू ने विशेष दर्जे की मांग पर हंगामा करने के लिए विपक्षी राजद-कांग्रेस-वाम गठबंधन पर हमला बोला, 'यह भूलकर कि यूपीए, जिसका वे हिस्सा थे, ने केंद्र में शासन करते समय हमारी मांग को खारिज कर दिया था।' नीतीश ने कहा, हम विशेष दर्जे की बात कर रहे थे और बहुत से लोगों ने कहा कि विशेष दर्जे का प्रावधान बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इसके बदले बिहार में विकास में मदद के लिए सहायता दी जानी चाहिए. अब, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। गठबंधन की राजनीति और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सहयोगियों - टीडीपी और जेडी (यू) की प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। जहां 16 सांसदों के साथ टीडीपी एनडीए में भाजपा की सबसे बड़ी सहयोगी है, (शेष पेज 9)

सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने से इनकार

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें विवादों से घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। न्यायालय का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित विभिन्न वकीलों की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं। पीठ फैसला सुरक्षित रखने के बजाय शाम करीब 4:50 बजे फिर बैठी और आदेश सुनाना शुरू किया। पीठ ने कहा, इस तरह के मामले में अदालत के अंतिम निष्कर्ष वर्तमान चरण में दर्ज किए जाने चाहिए क्योंकि इस विवाद को निश्चितता और अंतिम रूप प्रदान करने की तत्काल

आवश्यकता है, जो 20 लाख से अधिक छात्रों के करियर को प्रभावित करता है। एनटीए और अन्य द्वारा पेश सामग्री की स्वतंत्र जांच का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "वर्तमान चरण में, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी हुई या इसमें प्रणालीगत उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश देने से पिछली परीक्षा में शामिल हुए 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। उसने कहा कि इससे नामांकन कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और वंचित समूहों को गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए, कदाचार व्यापक स्तर पर और व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हो। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया कि व्यवस्थित तरीके से प्रश्नप्रत्र लीक हुआ था और अदालत के पास फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी- यह तथ्य विवाद का विषय नहीं है। पीठ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केन्द्रों के 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। उसने कहा कि चूंकि दागी छात्रों को अन्य छात्रों से अलग पहचाना जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि दोबारा परीक्षा ही एकमात्र विकल्प है। पीठ ने इसके साथ ही विभिन्न वजहों से 1,563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के एनटीए के निर्णय को भी बरकरार रखा।

आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजटः मुख्यमंत्री

● टैक्स स्लैब में नई रियायत को मुख्यमंत्री ने बताया स्वागत योग्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।

यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत होने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहीं। सीएम योगी ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम का अभिनंदन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है। खास तौर पर तब, जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही 'मिशन शक्ति' के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ-साथ मध्यमवर्गीय

आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहमः आनंदीबेन पटेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम बजट अमृत काल के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि यह देश के 140 करोड़ लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक न्याय दिलाने वाला है। राज्यपाल ने कहा कि बजट में किसान, गरीब, युवा तथा महिला सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि आज प्रस्तुत बजट देश को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने वाला है, जिसमें मध्यम वर्ग को न्याय,औद्योगीकरण को बढ़ावा, बेरोजगारों को रोजगार तथा गरीब आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों को न्याय देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं युवाओं के कौशल विकास पर बल देने से अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्यपाल ने कहा कि बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, शोध और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार हेतु अनेक कारकों का प्राथमिकता दिया जाना शामिल है।

एक्शन में सीएम योगी, लापरवाह पांच एडीएम और तीन एसडीएम से जवाब तलब

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न आपदाओं में हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जवाब तलब किया है। इसमें पांच जिलों के एडीएम एफआर को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है, जबकि तीन एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया। सीएम ने सभी लापरवाह अधिकारियों को दो दिनों में अपना स्पष्टीकरण शासन के सौंपने के निर्देश दिये हैं। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी

● आपदा से हुई जनहानि एवं क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही पर की कार्रवाई

● बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को किया निलंबित

आदित्यनाथ का अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि आपदा से हुई जनहानि का मुआवजा 24 घंटे के अंदर प्रदान किया जाए।

राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में आपदा से हुई जनहानि का सर्वे पूरा कर 24 घंटे में मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुई जनहानि और क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इनमें बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फनगर के एडीएम एफआर क्रमशः संतोष सिंह, उमेश चंद्र निगम, उमा शंकर, एस सुधाकरन और गजेंद्र कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि सौंपी गयी है। इसके साथ ही लापरवाही पर सिद्धार्थनगर की सदर तहसील के एसडीएम ललित कुमार मिश्रा, हाथरस की शादाबाद तहसील के एसडीएम संजय कुमार सिंह और अलीगढ़ की अतरौली तहसील के एसडीएम अनिल कुमार कटियार से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। वहीं बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्विनी कुमार को निलंबित कर दिया है।

बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिलाः केशव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट गाँव-गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को प्रोत्साहन और किसानों की आय में वृद्धि को धरातल पर उतारने वाला बजट है। यह गरीबों, महिलाओं, उत्तम स्वास्थ्य, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित बजट है। जिसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का रोड मैप और गरीब कल्याण तथा समग्र विकास पर केंद्रित बजट है, सर्व समावेशी बजट है। महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों, किसानों और सर्व समाज के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाला यह बजट है। मौर्य ने कहा कि गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों व नारीशक्ति को समर्पित बजट है। किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मिडिल क्लास के घर के सपने पूरे होंगे बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया गया है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला है। बजट में रोजगार का पिटारा खोला गया है। किसानों व युवाओं के लिए बड़े ऐलान किये गए हैं। नौकरी पेशा व पेंशनरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे चरण का शुभारम्भ होगा, बजट विकसित भारत का रोड मैप है। गरीब कल्याण व समग्र विकास पर केंद्रित बजट है।

सबका साथ, सबका विकास वाला बजटः ब्रजेश पाठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है।

कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजटः सुरेश खन्ना

● केन्द्रीय करों में यूपी का अंश 218816.84 करोड़ से बढ़कर हुआ 223737.23 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3.0 सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को एक शानदार बजट बताया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत सातवें बजट को हिंदुस्तान के लिए लघु एवं दीर्घ अवधि की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फायदा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, अन्नदाता गरीब वंचित सभी का बजट में ध्यान रखा गया है। बजट में नौ सूत्र दिए गए हैं। कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी को बढ़ावा देने वाला बजट है।

मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अन्तरिम बजट में केन्द्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश रू. 218816.84 करोड़ था जोकि इस बजट में बढ़कर 223737.23 करोड़ हो गया है। बजट में सोलर पैनल, सोलर सेल, कैंसर की दवायें, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, चार्जर, इलेक्ट्रिक वाहन, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स आदि सस्ते होंगे, जिससे आमजन को सीधा फायदा होगा। आयकर अधिनियम, 1961 को सुगम बनाने के लिये छह माह में इसकी समीक्षा की जायेगी। व्यक्तिगत आयकर में स्टेंटर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी।

सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये प्रस्तुत किये गये अन्तरिम बजट में 4 वर्गों गरीब, युवा, महिला एवं अन्न दाता पर फोकस किया गया था। इन्ही वर्गों पर मुख्य बजट में भी फोकस है। पी.एम. गरीब कल्याण योजना 5 वर्षों के लिये बढ़ायी गई। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 9 प्राथमिकतायें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवायें (मैनुफैक्चरिंग एवं सर्विसेस), शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा (एनर्जी सिक्योरिटी), अवसंरचना/ अवस्थापना सुविधा, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार बतायी हैं। खन्ना ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं लचीलापन लाने के लिये 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। दलहन-तिलहन की उत्पादकता एवं भण्डारण क्षमता बढ़ायी जायेगी एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र एवं सहायक गतिविधियों के लिय 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास किया जायेगा। समावेशी मानव विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला केन्द्रित विकास के लिये रू. 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिये 2.66 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे । 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिये तैयार प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जायेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का चौथा चरण प्रारम्भ किया जयेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिये ब्याज मुक्त ऋण योजना हेतु 1.50 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के लिये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जायेगा। यह योजना आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिये होगी। इसमें 63 हजार गांवों को आच्छादित किया जायेगा जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे।

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

मैने अपना नाम राजेश कुमार कैथल से बदलकर राजेश पुत्र राम सुमेर पासी पता कसरहा पुरवा, सुलेमाबाद, फतेहपुर भविष्य के लिए कर लिया है

सूचना

मैंने अपनी पुत्री लाइबा आलम सिद्दीकी (Laiba Alam Siddiqui) का नाम बदल कर अब हानिया आलम सिद्दीकी (Hania Alam Siddiqui) रख दिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को हानिया आलम सिद्दीकी (Hania Alam Siddiqui) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये। शाह आलम, पुत्र स्व० मोहम्मद नईम, निवासी–69/71, लाल कुआँ, भेड़ी मण्डी, थाना हुसैनगंज,लखनऊ

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पासपोर्ट संख्या – G7207585 में मेरे पति का नाम Mohammad Zubair Siddiqui अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि उनका सही नाम mohammad zubair manzoor है Mohammd Zubair siddiqui ओर mohammad zubair manzoor दोनों एक ही व्यक्ति है भविष्य में उन्हें Mohammad Zubair Manzoor के नाम से जाना पहचाना जाए शीबा परवीन पत्नी मोहम्मद जुबैर मंजूर निवासी –488/59 हसनगंज कोतवाली डालीगंज लखनऊ

सूचना

सूचित किया जाता है कि अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 शिव नाथ गुप्ता की सम्पत्ति संख्याः 10 ए/84 स्थित वृन्दावन योजना संख्या 2, सेक्टर 10, लखनऊ से संबंधित मूल बैनामा, जो क्रमांक संख्या 281, दिनांकः 09.01.2008 पर उपनिबंधक कार्यालय, लखनऊ में पंजीकृत है, जो कि दिनांक 26.08.2019 से 30.06.2024 के बीच ICICI Bank Ltd के द्वारा गायब हो गया है। जिस किसी को उक्त सम्पत्ति से संबंधित दस्तावेज पर कोई आपत्ति/क्लेम है तो नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। उपरोक्त समय अवधि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा विचार योग्य नहीं माना जाएगा। आपत्ति हेतु सम्पर्क करें।
बी0एन0 त्रिपाठी एडवोकेट, पता– सी–15, नेहरू विहार, कल्याणपुर, लखनऊ, मो0 9336127853

बजट में गरीबों व महिलाओं के विकास के लिए कोई योजना नहीं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बजट से जनता निराश हुई है। इस सरकार ने दस साल में बेरोजगारी बढ़ायी है।

नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। यह सरकार आधी अधूरी नौकरी का सपना दिखा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के ग्यारहवें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा नौ दो ग्यारह हो गया है। किसान की आय दोगुनी करने के लिए कोई योजना नही। मंडियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। खाने-पीने की चीजों से लेकर सब चीजों की महंगाई आसमान पर है। सरकार महंगाई नहीं कम करना चाहती है। बजट में गरीबों और महिलाओं के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। मंडी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए बिना किसानों को लाभ नहीं मिल सकता है। 'ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है कि इंसान इन हालातों में भी जिंदा है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कुछ नहीं: डिम्पल यादव

लखनऊ। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है। क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है।

बजट सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं: अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार का भी बजट सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं। देश की सभी बड़ी समस्याओं फिर चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, य फिर महंगाई की बात हो किसी भी समस्या के निवारण का स्पष्ट रोड मैप नहीं है। पिछले बजट में जो वादे किय गये थे, जो योजनाएं घोषित हुई थी, उनकी कोई चर्चा न करते हुए फिर से नये वादे नई घोषणाएं। राय ने कहा कि 2023 और 2024 का बजट भाषण ध्यान से देखते हुए कई झूठ यूहीं पकड़ में आ जाते हैं जैसे पिछले बजट में भी यह वादा किया गया था कि प्राकृतिक खेती की जद में एक करोड़ किसान लाये जायेंगे अगले तीन वर्षों में और इस बार उसी वादे को फिर से दोहराया गया है, यह कहते हुए कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की जद में लाया जायेगा तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि पिछले 1 वर्ष में इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से पिछले बजट में 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोलने की बात कही गई थी जो इस बार के बजट में भी दोहराई गई है। स्पष्ट है कि 1 साल में कोई भी रिसोर्स सेंटर नहीं खोला गया है। पिछले 10 सालों में मोदी जी की बहुचर्चित स्मार्ट सिटी परियोजना की चर्चा बंद हो चुकी है क्योंकि इनकी लगभग सभी स्मार्ट सिटी की हालत यह है कि पहली ही बारिश के बाद वहां नाव चलने की नौबत आ जा रही है। इसीलिए इस बजट में स्मार्ट सिटी की बात न करके शहरों को विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने के नए वादे की बात की जा रही है।

कृषि क्षेत्र में बढ़े निवेश व नीतियों में हो बदलावः रालोद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने मंगलवार को जारी एक बयान में केंद्र सरकार से बजट सत्र में कृषि पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि बजट सत्र से पूर्व केंद्र सरकार ने कृषि व किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें प्राथमिकता पर लिया है। पर, सरकार को यह भी समझना पड़ेगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों की आय बढ़े साथ ही बदलते समय के साथ परंपरागत कृषि के तरीक़ों के साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी पिछले दस वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सशक्त आधार तो तैयार कर ही लिया है बस अब आवश्यकता उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूलभूत सुधारों की है।

बजट अच्छे दिनों की उम्मीद वाला कम मायूस करने वाला ज्यादाः मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश किया है। हालांकि उनके इस बजट से विपक्षी दल के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में आज पेश केन्द्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव. बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आँकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे/आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति-जरूरी. सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे।

नई क्रेडिट गारंटी स्कीम से प्रदेश की छोटी इकाइयों को मिलेगी बड़ी राहत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● आम बजट 2024-25 में एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान

आम बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे प्रमुख घोषणा एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की है, जिसके तहत एमएसएमई इकाइयों को कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक स्व-वित्तपोषित गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जो प्रत्येक उधारकर्ता को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। इस पहल से प्रदेश की उन छोटी इकाइयों को भी लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं और इससे उनके खातों को एनपीए होने से भी बचाया जा सकेगा। मालूम हो कि योगी सरकार प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। बजट में नए प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आम बजट 2024-25 को सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋ ण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से असेट्स और टर्नओवर के आधार पर ऋण देती रही हैं। बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए होगी जिन्होंने पूर्व में लिए गए ऋण को तय समय सीमा में चुकाया है। एमएसएमई क्लस्टर्स में अगले तीन वर्षों में सिडबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिससे एमएसएमई इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।

ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की सीमा को वर्तमान 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे अधिक एमएसएमई इकाइयां इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो सकेंगी और आसानी से क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगी।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे प्रदेश के लाखों युवा

● अधिक संख्या में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे प्रदेश के युवा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

आम बजट 2024-25 में युवाओं के कौशल विकास को लेकर की गईं महत्वपूर्ण घोषणाएं

आम बजट 2024-25 में किए गए प्राविधानों से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। यही नहीं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वो रोजगार से जुड़ सकेंगे।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋ ण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है। यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओ को सेवायोजन प्रदान किए जाने के लिए नियुक्ति प्रदान कराई हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। निर्मला सीतारमण ने जो प्रमुख घोषणाएं कीं, उनमें प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा।

जानकीपुरम योजना में भूखंडों के आवंटन में हेराफेरी का मामला

एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव व लिपिक को सजा

● दो अन्य अभियुक्तों को भी सजा, एक को किया बरी

विधि संवाददाता। लखनऊ

वर्ष 1987 से वर्ष 1999 के दौरान एलडीए की जानकीपुरम योजना में भूखंडों के आवंटन में हेराफेरी कर सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एलडीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव आरएन सिंह को तीन वर्ष की सजा व 35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है जबकि लिपिक राज नारायण द्विवेदी को चार वर्ष की सजा सुनाई है। इस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। विशेष जज राहुल प्रकाश ने दो अन्य अभियुक्त महेंद्र सिंह सेंगर व दिवाकर सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इन पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

21 फरवरी 2006 को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। 28 फरवरी 2006 को सीबीआई ने संयुक्त सचिव आरएन सिंह सहित सात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। वर्ष 1987 से 1999 के बीच एलडीए की जानकीपुरम योजना के अंतर्गत 123 भूखंडों को संयुक्त सचिव एवं उपसचिव स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा तत्कालीन प्रधान लिपिक एवं अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से उन लोगों को आवंटित कर दिया गया जिनका पंजीकरण फार्म तक नहीं भरा गया था। इसके अलावा भूखंड वितरण के लिए अपेक्षित रकम भी जमा नहीं की गई थी। 26 फरवरी 2010 को सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान दो अभियुक्तों की मौत होने के कारण उनका मामला समाप्त कर दिया गया। जबकि अदालत ने एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग की जरूरत: हाईकोर्ट

● बिना जांच रिपोर्ट दिए कर्मचारी के खिलाफ आदेश पारित करने वाले एसओसी के विरुद्ध उचित कार्यवाही का आदेश

विधि संवाददाता। लखनऊ

अपर मुख्य सचिव, राजस्व स्वयं देखें कैसे की जा रही है अनुशासनात्मक कार्यवाहियां

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विभागीय जांच की कार्यवाहियों में घोर अनियमितता बरते जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। पीठ ने कहा है कि विभागीय जांच करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। पीठ ने अपने आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव, राजस्व को भेजने का आदेश देते हुए कहा है कि वह स्वयं देखें कि किस प्रकार से अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं। पीठ ने इसके साथ ही बिना जांच रिपोर्ट प्रदान किए चकबंदी कर्मचारी के खिलाफ आदेश पारित करने वाले बाराबंकी के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (एसओसी) व मामले के जांच अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई का आदेश दिया है।

जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश उमा शंकर प्रसाद की सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सात मार्च 2024 को उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी (एसओसी, बाराबंकी) ने दंडादेश पारित किया। जिसके तहत उसके दो वेतन वृद्धियों पर स्थाई तौर पर रोक लगा दी गई। साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि का भी आदेश दिया गया। कहा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना उसे जांच रिपोर्ट दिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं जांच अधिकारी ने भी बिना जांच के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जांच अधिकारी ने जांच के लिए समय, तिथि और स्थान तक नियत नहीं किया। एकल पीठ ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्थापित कानून है कि विभागीय जांच में जांच अधिकारी समय, तिथि और स्थान नियत करके मौखिक जांच करेगा। जबकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच रिपोर्ट की प्रति कर्मचारी को प्रदान करते हुए उसका स्पष्टीकरण तलब करेगा। पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि इस मामले में न तो समय, तिथि और स्थान नियत क्या गया और न ही जांच रिपोर्ट की प्रति दी गई।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

शादी का झांसा देकर एक नाबालिग युवती से यौन संबंध बनाने व बाद में शादी से इनकार करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी धीरेंद्र को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष जज नीरज कुमार उपाध्याय ने इस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। 23 जनवरी 2017 को इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना काकोरी में दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक पिछले छह माह से आरोपी धीरेंद्र प्रेम संबंध बनाकर पीड़िता का यौन शोषण कर रहा था। लेकिन जब पीड़िता ने शादी की बात की तो इनकार करते हुए गंदी-गंदी गालियां व जानमाल की धमकी देकर मारपीट की।

अकबरनगर से बसंत कुंज योजना में विस्थापित लोगों से वार्ता कर मंडलायुक्त ने जाना उनका हाल-चाल

● मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित कराने का दिया आश्वासन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसंतकुंज में मंडलायुक्त द्वारा अकबरनगर से विस्थापितों से वार्ता कर मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की गयी। वार्ता के दौरान मंडलायुक्त द्वारा विस्थापित लोगों को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संपूर्ण संसाधन मुहैया कराये जाएंगे। मंडलायुक्त द्वारा जिला प्रशासन से विस्थापित प्रत्येक बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया।

प्रेरणास्थल की मेडिटेशन हाल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बसंत कुंज योजना में शिफ्ट किए गए परिवारों की मूलभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजमर्रा की आवश्यकता, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, खाद्यान व्यवस्था, पुलिस चौकी, वेंडिग जोन आदि व्यवस्थाओं को प्राथमिकता पर ध्यान रखते हुए मूलभूत सुविधा मुहैय्या कराना हमारी जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि कि बसंतपुर योजना में मैन पावर की व्यवस्था कर दी गई है, जो की साफ-सफाई नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर दी गई है उसमें विस्थापित लोगों को आजीविका चलाने के लिए दुकाने लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से भी वेंडिंग जोन वालों को लाभान्वित किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि उक्त स्थान पर चौकी बनाते हुए चौकी इंचार्ज की तत्काल ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कमिश्नर ने की मंडलीय समीक्षा

धीमी प्रगति वाले जिलों को ग्रेडिंग में सुधार लाने के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मंडलायुक्त द्वारा सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य सें विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक की गयी। मंडलायुक्त द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता परक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंडलायुक्त द्वारा मंडल में जिन जनपदों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष धीमी व खराब है, उन्हें अपने ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए।

डॉ रोशन जैकब ने कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह विभागीय कार्यक्रमों में अपने-अपने विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके। समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने जनपद सीतापुर में मुख्यमंत्री आवास योजना की ग्रेडिंग खराब मिलने पर ग्रेडिंग में सुधार करने के निर्देश दिये। आर एस विभाग द्वारा सड़क व भवन निर्माण कार्य मे तेजी लाये। कायाकल्प योजना, मध्यान्ह भोजन, कन्या विवाह योजना, स्वरोजगार योजना, कृषक दुर्घटना, किसान सम्मान निधि, कुसुम योजना, ऊर्जा, कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों की ग्रेडिंग खराब है वो जनपद अपनी ग्रेडिंग में सुधार लाये। शासन के प्राथमिकता वाले योजनाओं में विशेष ध्यान दिया जाये। सड़कों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाए। निर्माणधींन समस्त कार्य निर्धारित समयावधि पूर्ण करा लिया जाये।

सिख प्रतिनिधि मंडल ने की महापौर से मुलाकात, जताया आभार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

महापौर से सिख प्रतिनिधि मंडल मिला। एलडीए कॉलोनी का नाम साहिब गुरु तेग बहादुर जी नगर किए जाने पर आभार जताया। लंबे अर्से से मांग नाम रखने की मांग की जा रही थी, जिसे महापौर द्वारा पूरा किया गया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह के नेतृत्व में सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल से भेंट की। सिख प्रतिनिधिमंडल ने एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ का नाम परिवर्तित कर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी नगर किए जाने पर महापौर और नगर निगम कार्यकारिणी के पदाधिकारी गणों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने भेंट वार्ता में बताया कि यह सिख समाज की वर्षों पुरानी बहू प्रतिक्षित मांग थी। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा लघु उद्योग के महानगर संयोजक रणबीर सिंह भसीन, सिख एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जसवंत सिंह कंधारी, देवेंद्र सिंह सहोता, मनमोहन सिंह लाली, जगदीश सिंह उपस्थित रहें।

नेशनल टीम ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का जाना हाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में अभियान की हकीकत जानने के लिए मंगलवार को नेशनल टीम ने मोहनलालगंज ब्लाक के बिंदौआ गाँव का भ्रमण किया और घर-घर में जाकर लोगों से अभियान की जानकरी ली। इसी के साथ उन्होंने मोहनलालगंज सीएचसी का भ्रमण कर इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर (ईटीसी) का निरीक्षण किया। वहां की स्वास्थ्य सेवाओं से वह संतुष्ट दिखे। इसके साथ ही सीएचसी पर जबरौली, बिंदौआ और लालपुर के 30 फ़ाइलेरिया रोगियों को रुग्णता प्रबन्धन एवं दिव्यांगता उपचार (एमएमडीपी) किट का वितरण किया। जिला मलेरिया अधिकारी डा. रितु ने बताया कि टीम में जीन डिलेग सी, भावना पोपली, कनिका दादू, और मानवी बर्मन थे। टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों से मच्छर से बचाव को लेकर की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मच्छर जनित कौन से रोग होते हैं इसकी जानकारी ली। यह जानकरी उन्हें कहाँ से मिली। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आशा,एएनएम और आंगनबाड़ी सभी आकर बताती हैं। इसके साथ ही दस्तक अभियान में आशा कार्यकर्ता क्या बता रही हैं उनके बारे में भी पूछा। टीम ने ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा एएनएम से अभियान में उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। गाँव में संचारी अभियान और दस्तक अभियान को लेकर बैनर लगे हुए थे। बता दें कि दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता खांसी, बुखार, इन्फ्ल्यूएन्जा के मरीजों के साथ टीबी , कुष्ठ और फ़ाइलेरिया के लक्षण वाले रोगियों के को भी घर जाकर ढूँढ़ रही हैं।

शहरी पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर छितवापुर को मिला एन्क्वास सर्टिफिकेट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)-आयुष्मान आरोग्य मंदिर छितवापुर ने साल 2024-25 का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टेंडर्ड (एन्क्वास) सर्टिफिकेट हासिल किया है। मंगलवार को यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि यह लखनऊ मंडल का पहला शहरी पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसे एन्क्वास मिला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। एन्क्वास प्राप्त पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर को तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलती है।

12 और 13 जून को स्वास्थ्य इकाई का केंद्र सरकार की टीम ने आकर असेस्मेंट किया था। स्वास्थ्य इकाई ने सभी 12 विभागों में 75 फीसद से ज्यादा अंक हासिल किये हैं। इससे पहले छितवापुर पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर को साल 2022-23 का कायाकल्प पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा राज्यपाल, नीति आयोग और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की टीम ने पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भ्रमण कर सराहना की है। पीएचसी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर की चिकित्सा प्रभारी डा. गीतांजली एवं पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि साल 2026 दिसम्बर तक सौ फीसद स्वास्थ्य इकाइयों को एन्क्वास मिले। जमीनी स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों को इस दिशा में अथक प्रयास करना है।

स्थानांतरित होकर आए फार्मासिस्ट का हुआ स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बलरामपुर चिकित्सालय के इमरजेंसी सभागार में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला शाखा लखनऊ की कार्यकारिणी द्वारा मंगलवार जनपद लखनऊ में अन्य जिलो से स्थानांतरित होकर आए चीफ फार्मासिस्ट / फार्मासिस्ट का स्वागत / परिचय समारोह आयोजित किया गया। जिसमें जिला शाखा लखनऊ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बड़ी संख्या में चीफ फार्मासिस्ट/ फार्मासिस्ट उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरूण अवस्थी ने की, मंच का संचालन रजत यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रुप से कार्यकारी अध्यक्ष कपिल वर्मा, आर बी मौर्या वरि उपाध्यक्ष ,संगठन मंत्री अविनाश सिंह, कोषाध्यक्ष चन्द्रशेखर श्रीवास्तव, राजेश वरुण,अरविन्द सिंह, राज कुमार,जसवंत, रंजीत गुप्ता,अरविन्द त्रिपाठी, रामेश चन्द्र चौधरी सही कई सदस्य उपस्थित रहे।

फर्जी आईडी से सिम लेकर दूसरे देशों में सप्लाई करने वाला कोलकाता से गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने फर्जी आईडी से सिम लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके भारी संख्या में सिम एक्टिवेट कर भारत के बाहर (थाईलैण्ड, नेपाल कम्बोडिया, हॉगकॉग देशों में स्थापित कॉल सेन्टरों को) सप्लाई करने वाले गैंग के सदस्य राहुल सिन्हा निवासी पश्चिम गंगाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ यूनिट, गौतमबुद्ध नगर को ज्ञात हुआ कि वांछित अभियुक्त राहुल सिन्हा, थाना राजारहाट पुलिस कमिश्ररेट विधाननगर, पश्चिमी बंगाल में है। इस सूचना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम वहां रवाना की गई। जिसने संयुक्त कार्रवाई के दौरान 19 जुलाई को राहुल सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रांजिट रिमांड पर उसे मंगलवार को गौतमबुद्धनगर के थाना बिसरख लाकर दाखिल किया गया। अभियुक्त राहुल सिन्हा ने पूछताछ पर बताया कि उसने स्नातक करने के बाद वर्ष 2014 तक विभिन्न टेलीकॉम कम्पनी जैसे बीएसएनएल, टाटा टेलीकॉम सर्विसेस आदि में सैल्स एग्ज्यूकेटिव के पद पर काम किया था। उसके बाद वर्ष 2014 में वह जमशेदपुर से कोलकाता आ गया था। अभियुक्त राहुल सिन्हा कोलकाता में विभिन्न टेलीकॉम वैण्डर के साथ सैल्स एग्ज्यूकेटिव के पद पर काम किया था। राहुल सिन्हा, वर्ष 2022 में सुनील खडका पुत्र खडका बहादुर निवासी महकुलूग जनपद सोलुखुम्ब नेपाल के सम्पर्क में आया था, सुनील खडका थाईलैण्ड, कम्बोड़िया में कॉल सेन्टर चलाता था जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड का डेटा डार्कबेव एवं अन्य सूत्रों से खरीदकर नेपाल एवं कम्बोडिया स्थित कॉल सेन्टर से कॉल करके धोखाधड़ी से पैसा ट्रान्सफर कराना होता था। राहुल सिन्हा भी सुनील खडका के काम में शामिल हो गया तथा यहाँ से भारतीय सिम व कमीशन बेस पर बैक एकाउन्ट उपलब्ध कराने लगा था। सुनील खडका हॉगकॉग एवं कम्बोडियों में कॉल सेन्टर स्थापित करना चाहता था, जिसका उद्देश्य भारतीयों के साथ धोखाधडी करने के अलावा चायनीज नागरिकों के साथ मिलकर गेमिग एवं लोन ऐप के जरिये धोखाधडी से पैसा ठगना भी था। इस उद्देश्य के लिए अभियुक्त राहुल सिन्हा का काम भारत से 10 हजार सिम सुनील खडका को थाइलैण्ड भेजने का था जिसमें लगभग 500 सिम अभियुक्त राहुल सिन्हा ने भेजे थे, जो थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर की पुलिस द्वारा पकडे गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर पर अभियोग दर्ज है।

बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन कल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से प्रदेश में बाढ़ आपदा के प्रति 44 अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील जनपदों में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन 25 जुलाई, 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। मॉक एक्सरसाइज़ के द्वितीय चरण में आज टेबल टॉप एक्सरसाइज बैठक का आयोजन योजना भवन के सभागार में किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, ले. जनरल सय्यद अता हसनैन ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदो में बाढ़ की स्थिति है। इसके लिए किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों को मॉक एक्सरसाइज़ के आयोजन के समय एनडीएम द्वारा समीक्षा की जाएगी। जिन जनपदों में अभी बाढ़ कि स्थिति नहीं है, वहाँ सम्बन्धित जिलों को अपने आपदा प्रबंधन योजना एवं बाढ़ योजना की समीक्षा में सहायता मिलेगी। सभी विभाग, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बनाने में सहायक होंगे। बैठक को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष, ले. जनरल योगेन्द्र डिमरी ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों से बाढ़ आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु जनपदों के साथ मॉक एक्सरसाइज कराया जाता है जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर प्रत्येक विभाग और उसके जिलों की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की जाती है तथा जिले में आपातकालीन सहायता कार्यों के बीच समन्वय का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि एनजीओ, समुदाय और मीडिया को शामिल करके व्यापक रूप से आम जनमानस में जनजागरूकता की कार्यवाही की जाती है तथा यदि संसाधनों, जनशक्ति, संचार, प्रतिक्रिया क्षमताओं आदि में कोई अंतराल हो तो उसकी पहचान कर उसे मजबूत करने में इस प्रकार के मॉक एक्सरसाइज से सहायता भी मिलती है। सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त जी एस नवीन कुमार ने कहा कि इस वर्ष पूर्व से ही संवेदनशील जनपदों में राहत एवं बचाव कार्य हेतु एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं पीएसी की टीमें तैनात कर दी गयी थीं।

मैक्स में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम द विंची एक्सआई का हुआ शुभारंभ

लखनऊ। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने मंगलवार को अत्याधुनिक द विंची शी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के शुभारंभ के साथ अपनी सर्जरी सुविधा के विस्तार की घोषणा की है। यह नई टेक्नोलॉजी लखनऊ के लोगों के लिए कम से कम चीरों वाली सर्जरी को और सुलभ बनाकर सर्जरी की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी। इस मौके पर डॉ. गौरव अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हॉस्पिटल ऑपरेशन्स एवं जोनल हेड (वैशाली और लखनऊ), मैक्स हेल्थकेयर ने कहा कि हम लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में नवीनतम दा विंची एक्सआई रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च करके बहुत उत्साहित हैं। यह हमारे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार और चिकित्सा उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह तकनीक ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट मिनिमल एक्सेस, बेरियाट्रिक, गायनेकोलॉजी और सामान्य सर्जरी सहित विभिन्न चिकित्सा विभागों में सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रोबोटिक सर्जरी के फायदों के बारे में बात करते हुए, डॉ. राहुल यादव, डायरेक्टर - यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरो-ऑन्कोलॉजी ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक कम दर्द, कम रक्तस्राव, अस्पताल में रहने की कम अवधि, अपनी दैनिक जीवनचर्या और काम पर जल्दी लौटने और न्यूनतम जटिलताओं के साथ बेहतर रोगी परिणाम प्रदान करती है। डॉ. शशांक चौधरी ने बताया कि द विंची सिस्टम सर्जरी वाली जगह का अत्यधिक विस्तारित, 3डी हाई-डेफिनिशन दृश्य प्रदान करता है।

लविवि की एनसीसी बटालियन का रैंक वितरण समारोह आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

64वीं यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 का रैंक वितरण समारोह आयोजित किया गया। एनसीसी में रैंक के अनुसार सीनियर अंडर ऑफिसर, अंडर ऑफिसर , कंपनी सार्जेंट मेजर, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट के बाद सार्जेंट, कॉर्पोरल और लांस कॉर्पोरल शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर जो एनसीसी में सर्वोच्च रैंक है, रत्नाकर राय को दी गयी, उसके बाद अंडर ऑफिसर विनय वर्मा, अंडर ऑफिसर प्रेरणा शर्मा एवं अंडर ऑफिसर गौरव यादव को प्रदान की गई। कंपनी सार्जेंट मेजर माही सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट अर्पित वर्मा, सार्जेंट भूमिका गुप्ता, अंशिका सिंह एवं राज को प्रदान की गई। साथ ही 5 कॉर्पोरल और 12 लांस कॉर्पोरल की रैंक वितरित की गई। रैंक के साथ कई जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, रैंक प्राप्त करने के बाद कैडेटों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया। रैंक वितरण 64 यूपी बीएन एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉ. रजनीश कुमार यादव ने किया और इस अवसर पर सूबेदार मेजर भूपेन्द्र सिंह धामी, नायब सूबेदार राम किशन और अन्य ट्रेनिंग स्टॉफ उपस्थित रहा। साथ ही इस आयोजन पर कैडेटों ने आशावादी जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

परिषदीय शिक्षकों ने ली शपथ यूपी को बनाएंगे निपुण प्रदेश

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा का अनुकरणीय वातावरण बनाकर उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में मंगलवार को सभी परिषदीय स्कूलों में शिक्षा सप्ताह के दूसरे दिन दूसरे दिन एफएनएल दिवस मनाया गया। इस दौरान हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बीच परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों में 22 से 28/29 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह का मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। शिक्षा सप्ताह के दूसरे दिन आज सभी विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों ने शपथ लेते हुए कहा कि बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए हम, विद्यालय और उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने की शपथ लेते हैं। उन्होंने ने न सिर्फ निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने सभी सहभागियों को निरंतर प्रेरित करने का संकल्प लिया, बल्कि अपने ब्लॉक व जनपद को निपुणता हासिल कराने की भी शपथ ली।

दो सप्ताह के विशेष चेकिंग अभियान में 5913 स्कूली वाहन पाए गए अनफिट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने वसूला 60.84 लाख रुपए शमन शुल्क

परिवहन विभाग द्वारा 8 जुलाई से 22 जुलाई तक स्कूल वाहनों के विरूद्ध चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत 5913 स्कूली वाहन अनफिट पाये गये। उक्त अभियान में स्कूली वाहनों के फिटनेस संबंधी जांच प्रवर्तन दल द्वारा किया गया। जांच के दौरान पूरे प्रदेश में कुल रजिस्टर्ड 61921 स्कूली वाहनों में से 47624 वाहनों के फिटनेस संबंधी जांच किये गये, जिसमें से कुल 41675 स्कूली वाहन फिट पाये गये एवं 5913 स्कूली वाहन अनफिट पाये गये। यह जानकारी परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान में अनफिट पाये गये 2076 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 456 स्कूली वाहनों को बंद किया गया। उक्त कार्यवाही से 60.84 लाख रूपये प्रशमन शुल्क वसूला गया और 552 स्कूली वाहनों को नोटिस भेजी गयी। लखनऊ संभाग में 6775 स्कूली वाहन चेक किये गये, जिसमें से 5763 स्कूली वाहन फिट पाये गये एवं 1012 अनफिट पाये गये। इसी प्रकार अयोध्या संभाग में 3050 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 151 वाहन अनफिट पाये गये, गोण्डा संभाग में 1744 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 600 वाहन अनफिट पाये गये, बस्ती संभाग में 2052 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 400 वाहन अनफिट पाये गये। कानपुर संभाग में 2294 वाहन चेक किये गये, जिसमें से 211 वाहन अनफिट पाये गये, प्रयागराज संभाग में 2384 वाहन चेक किये गये, 280 वाहन अनफिट वाहन पाये गये, बांदा संभाग में 663 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 39 वाहन अनफिट पाये गये, बरेली संभाग में 1987 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 184 वाहन अनफिट पाये गये, मुरादाबाद संभाग में 2702 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 327 वाहन अनफिट पाये गये, वाराणसी संभाग में 5159 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 297 वाहन अनफिट पाये गये, गोरखपुर संभाग में 4384 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 985 वाहन अनफिट पाये गये, आजमगढ़ संभाग में 1840 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 236 वाहन अनफिट पाये गये, मिर्जापुर संभाग में 1202 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 10 वाहन अनफिट पाये गये, मेरठ संभाग में 1554 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 281 वाहन अनफिट पाये गये, गाजियाबाद संभाग में 2013 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 119 वाहन अनफिट पाये गये, सहारनपुर संभाग में 1736 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 468 वाहन अनफिट पाये गये, आगरा संभाग में 3810 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 1208 वाहन अनफिट पाये गये, अलीगढ़ संभाग में 1258 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 86 वाहन अनफिट पाये गये एवं झांसी संभाग में 1017 वाहनों की चेकिंग की गयी, जिसमें 139 वाहन अनफिट पाये गये।

निर्धन परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं से किया जाए लाभान्वित: मुख्य सचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में निर्धनतम परिवारों को आवास सहित जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायतीराज विभाग द्वारा सर्वे कराकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 निर्धनतम परिवारों का डाटाबेस तैयार कराया गया है। यह डाटा ग्राम पंचायत से अनुमोदित है। इसमें लगभग 6 लाख परिवार के सभी सदस्यों का विवरण है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से लेकर जनपद स्तर के अधिकारियों को इस डाटा का एक्सेस यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से दिया जाये। सभी सम्बन्धित विभाग अपने जनपदस्तरीय अधिकारियों के माध्यम से इन परिवारों को आवास सहित ऐसी योजनाओं जिसके लिये वह पात्र है, उससे संतृप्त कराया जाये। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव बेसिक डॉ. शंमुगा सुंदरम, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार वीना कुमारी मीना, सचिव कृषि अनुराग यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दृढ इच्छाशक्ति, सतत परिश्रम और उद्देश्य निर्धारित कर कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं युवा: डॉ. राजेश्वर सिंह

● सुशांत गोल्फ सिटी में सरोजनीनगर विधायक ने स्थापित की लाइब्रेरी, कहा, कम्युनिटी सेंटीमेंट बढ़ाती है लाइब्रेरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित चंद्रा पैरोनोमा में बच्चों और सभी रेजिडेंट सदस्यों के लिए विभिन्न लेखकों, महापुरुषों द्वारा लिखी गयी 170 से अधिक किताबें प्रदान कर लाइब्रेरी की स्थापना की। इसके साथ ही विधायक ने सोसाइटी स्थित हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 2 लाख रुपए प्रदान करने और आरडब्लूए में 10 बेंच उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया और बच्चों को क्रिकेट किट प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि लाइब्रेरी लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से बौद्धिक विकास और ज्ञान विस्तार सुनिश्चित होता है। आरडब्लूए में कम्युनिटी सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए मैंने लाइब्रेरी की स्थापना की पहल शुरू की है। इस दौरान डॉ. सिंह ने आरडब्लूए रेजिडेंट्स को क्लीन, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और सतत विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि सोलर को बढ़ावा देकर हाउसिंग सोसाइटी एक मॉडल प्रस्तुत करें जहां अपना सोलर प्लांट स्थापित कर बिजली बिल शून्य करने का प्रयास करें। विधायक ने बताया कि सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में सोलर अभियान संचालित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लखनऊ में सर्वाधिक सोलर पैनल स्थापित हुए हैं। सरोजनीनगर विधायक ने बताया कि मेरा लक्ष्य विधानसभा क्षेत्र के सभी 104 आरडब्लूए में लाइब्रेरी स्थापित करना है, अबतक 7 आरडब्लूए में लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं। कार्यक्रम में आरडब्लूए अध्यक्षा डिम्पी बाजपेई, सचिव सीमा जैन, कोषाध्यक्ष आशीष प्रकाश, आरके मिश्रा, ब्रिगेडियर सिशोदिया, आरके खरे, रीता, आरके बैद्य, एके सिंह, एस बी सिंह, आरके सक्सेना, एमएल सिंह, राय आर्यन, गौरव पाण्डेय, अनिल कुमार सिंह एके ओझा, आरके माहेश्वरी, के एस सेंगर, एसकेडी एकेडमी के निदेशक मनीष सिंह, भाजपा नेता शंकरी सिंह, रामशंकर त्रिपाठी, मोहित तिवारी, हिमांशु वर्मा, शैलेन्द्र सिंह, पार्षद के एन सिंह, मुकेश यादव, सुमन राठौर आदि मौजूद रहे।

क्षेत्र में सर्वे कर छूटे भवनों को गृहकर के दायरे में लाने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

महापौर की अध्यक्षता में गोमतीनगर जोन 4 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान महापौर द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों की समस्याएं सुनीं गयी। क्षेत्र में अधिकारियों को घरेलू और व्यवसायिक संपत्तियों को सर्वे कर चिन्हित कर टैक्स के दायरे में लाने के निर्देश दिए गए। महापौर द्वारा सख्ती से अधिकारियों को फाइल बनाकर वसूलने का निर्देश दिए गए।

मंगलवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर निगम के ज़ोन 4 की समीक्षा बैठक लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय की समीक्षा बैठक की। इसमें क्षेत्र के पार्षदों ने रखी गई समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में महापौर ने ज़ोन के समस्त वार्डों में सर्वे कर कॉमर्शियल व घरेलू समपत्तियों को टैक्स लिस्ट में शामिल कर कर वसूली की स्थिति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पार्षदों ने ज़ोन में सभी कॉमर्शियल प्रोपार्टियों के टैक्स लिस्ट में न होने की शिकायत पर महापौर ने क्षेत्र में ऐसी सभी घरेलू एवं कॉमर्शियल समपत्तियों को जो टैक्स लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उनका सर्वे कर टैक्स वसूल किये जाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही सर्वे से पूर्व इसकी सूचना क्षेत्रीय पार्षद को दिए जाने के लिए भी आदेशित किया। साथ ही कर वसूल की फाइल प्रत्येक वार्ड अंतर्गत बनाये जाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके अतिरिक्त ज़ोन अंतर्गत बनी ऐसी सड़कें जिनके बिल पास हो गए हैं लेकिन शिलापट्ट अभी तक नहीं लगाया गया है, इस मामले को लेकर महापौर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सिविल अभियंता की फ टकार भी लगाई।

साथ ही भविष्य में शिलापट्ट लगने से पहले पेमेंट होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफसीधे कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक में अपर नगर आयुक्त व जोन 4 के प्रभारी पंकज श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी संजय यादव सहित नगर निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दोबारा कब्जे के आरोप में अवैध कब्जेदार पर मुकदमा

संवाददाता। मोहनलालगंज

सदरपुर करोरा में खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण खाली करने के बाद अवैध कब्जेदार ने फिर से अतिक्रमण कर लिया। अधिकारियों के निर्देश पर लेखपाल ने अवैध कब्जेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।

मोहनलालगंज तहसील के सदरपुर करोरा गांव में एक बीघे से अधिक खेल मैदान की भूमि के कुछ हिस्से पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किया गया था। एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा के निर्देश पर राजस्व टीम 14 जून को अतिक्रमण खाली करा दिया था। लेकिन अवैध कब्जेदार ने फिर से मिट्टी पटाई कर अतिक्रमण कर लिया। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को भेजकर जांच कराई तो आरोप सही पाया गया। एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल मदन मोहन ने सरसवां अर्जुनगंज निवासी जितेन्द्र यादव पर अवैध कब्जे का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। एसडीएम ने बताया सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

कमिश्नर के आदेश की भी परवाह नही,पैमाइस और मेड़बंदी के लिए दौड़ रहे किसान

मोहनलालगंज। तहसील के राजस्वकर्मियों को कमिश्नर के आदेश की भी परवाह नहीं है। लिहाजा फरियादी कमिश्नर का आदेश लिखी अर्जी लेकर तहसील के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन राजस्वकर्मी उन्हें न्याय के बजाए तारीख पर तारीख देकर टरका रहे हैं। यही नही तहसील अधिकारियों को भी आदेश का अनुपालन कराने की फुरसत नही है। मोहनलालगंज में 6 जुलाई को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतें सुन रहीं कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब से सरथुआ की बीना ने 24 अगस्त 2022 को हदबरारी आदेश होने के बावजूद अब तक मेडबंदी नही कराए जाने की शिकायत की थी। नाराज कमिश्नर ने तहसीलदार को फौरन मेड़बंदी कराने का आदेश दिया था। लेकिन बीना के मुताबिक अब तक उनकी जमीन की मेड़बंदी नही हो सकी है। मंगलवार को कानूनगो मेडबंदी के लिए पहुंचे तो लेखपाल के नही पहुंचने से फिर मेड़बंदी टल गई। सदर बाजार निवासी किसान चंद्रपाल सिंह ने कमिश्नर से कानूनगो की रिपोर्ट नही आने से हदबरारी के मुकदमे में एक वर्ष बाद भी तारीख पर तारीख देकर दौड़ाए जाने की शिकायत की थी। नाराज कमिश्नर ने जमीन की पैमाइस कर दो दिन में रिपोर्ट दाखिल करने और नायब तहसीलदार से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए थे। लेकिन राजस्वकर्मियों ने पीड़ित का शिकायती पत्र ही गायब कर उसे रशीद तक नही लेने दी। पीड़ित चंद्रपाल के मुताबिक अब तक उनकी जमीन की पैमाइस नही की गई है। बार बार फोन करने पर मंगलवार को सारा दिन खेतों में बिठाए रखने के बाद भी कानूनगो पैमाइस करने नही आए। गौरा निवासी किसान ज्ञानचंद्र ने भी हदबरारी आदेश के बावजूद मेडबंदी नही कराए जाने की शिकायत की थी। लेकिन कानूनगो ने 12 जुलाई की तिथि निश्चित करने के बाद भी मेडबंदी नही कराई। पीड़ित ने तहसीलदार से शिकायत दर्ज कराई है। जिसपर कानूनगो से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

कमिश्नर की सख्ती के बाद किसान राजेश को मिला न्याय

मोहनलालगंज के भदुआ निवासी किसान राजेश ने कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब से हदबरारी आदेश के बावजूद जमीन की मेडबंदी नही कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेकर कमिश्नर ने मौजूदा कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि और रिटायर्ड कानूनगो के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राजस्व टीम ने 10 जुलाई को हो गांव पहुंचकर मेडबंदी करा दी। कमिश्नर का आभार जताते हुए किसान राजेश ने बताया उनकी जमीन की मेडबंदी करा दी गई है।

आर्यकुल कॉलेज के 172 मेधावियों को प्रदान की टैबलेट डिवाइस

सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मंगलवार को नटकुर स्थित आर्यकुल ग्रुप ऑफ़ कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना के 172 लाभार्थी मेधावी छात्र- छात्राओं को टैबलेट, स्मार्ट फोन डिवाइस प्रदान की। इस अवसर पर छात्र- छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए सरोजनीनगर विधायक ने कहा कि टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि डिजिटल डिवाइस अवसरों की दुनिया के द्वार खोलती हैं। सीएम योगी की दूरदर्शी पहल %स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना% के अंतर्गत प्रदेश के मेधावियों को डिजिटल डिवाइसेस प्रदान की जा रही हैं। डॉ. सिंह ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से आज विश्व का हर ज्ञान युवाओं की उंगलियों पर है, आने वाले समय में डिजिटल शिक्षा ही युवाओं का भविष्य है। युवा शक्ति को अपनी डिजिटल स्किल अपग्रेड करना होगा, अगले 3 साल में डिजिटल स्किल के अनुरूप 8.5 नौकरियों का स्वरुप बदलेगा जिससे करीब 10 करोड़ नए अवसर सृजित होंगे। सरोजनीनगर में मेधावियों को निरंतर सम्मानित किया जा रहा है, 25 कॉलेज में डिजिटल लैब स्थापित की गयी, 10 कॉलेज में स्मार्ट पैनल स्थापित किये गए, हर गांव में युवा सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किये जा रहे है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉ. सशक्त सिंह जी, स्वदेश तिवारी, आदित्य सिंह, अंकिता अग्रवाल, हर्ष नारायण, बी. के. सिंह, प्रणव पाण्डेय एवं पूरे आर्यकुल परिवार को बधाई दी। इस दौरान भाजपा नेता वीरेन्द्र तिवारी, शंकरी सिंह, भरत सिंह, पार्षद संजीव अवस्थी व केएन सिंह उपस्थित रहे।

बजट में दिखा सिर्फ एनडीए के चुनावी गठबंधन का असर: अमरनाथ मिश्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बजट चर्चा पर लखनऊ व्यापार मण्डल की कोर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें मुख्य रूप से चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, सचेतक अनिल विरामनी, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता, अनुराग मिश्र, जितेन्द्र सिंह चैहान, अजय पिपलानी, युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता, सुमित गुप्ता, प्रियांक गुप्ता आदि उपस्थिति रहे।

अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने जो आम बजट पेश किया उसमें की गईआंकड़ों की बाजीगरी जो शायद जनता को तो क्या ये कि सत्ता पक्ष में बैठे सांसदों को भी समझ में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एनडीए का चुनावी गठबंधन का असर दिखा। बिहार, ऑध्र प्रदेश और कुछ-हद तक ओडिशा, असम के लिए बाकी आम जनता से सम्बन्धित कुछ नहीं। अगर व्यापारी समाज की बात की जाय तो कुछ भी नहीं विचारणीय है कि अटल विहारी बाजपाई की जब सरकार नहीं आयी थी उसके पहले से भाजपा की मांग थी इनकम टैक्स में आय की सीमा ज्यादा होनी चाहिए बल्कि 2014 से पहले तो इनके घोषणा पत्र में 5 लाख तक कर मुक्त आय की घोषणा की थी जो कि आज तक नहीं कर पाये जबकि आर्थिक आधार आरक्षण या 8 लाख पर देते है तो फिर 10 लाख तक के करमुक्त आय क्यों न होनी चाहिए। अनिल विरमानी ने कहा कि सरकार का यह कहना है कि सब कुछ ऑन लाइन कर रही है और इस ऑल डूइंग बिजनेस कर रही है लेकिन इसके विपरीत यदि आप दवा की दुकान करते है तो आपको 1 ड्रग लाइसेन्स लेना है और यदि आप फूड सप्लीमेंट उसमें बेचते है जो कि डा. साथ-साथ दवा के लिखते है तो अपको अलग से फूड डिपार्टमेन्ट में पंजीकरण कराना है जबकि दोनो के कागज एक ही लगते है और प्रक्रिया भी एक है। ऐसे में एक ही दस्तावेजों से दोनों लाइसेन्स जारी होने चाहिए।

खेल मैदान पर बना लिया रास्ता, एसडीएम ने कराई एफआईआर

संवाददाता। मोहनलालगंज

सदरपुर करोरा में खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉटिंग के लिए चौड़ा रास्ता बना लिया। शिकायत पर राजस्व टीम ने अतिक्रमण खाली करा दिया। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने फिर से मिट्टी पाटकर रास्ता बना डाला। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने अवैध कब्जेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। उधर अतिक्रमण को लेकर तहसील प्रशासन की सख्ती से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया है।

मोहनलालगंज तहसील के सदरपुर करोरा गांव में एक बीघे से अधिक खेल मैदान की जमीन के कुछ हिस्से पर मिट्टी पाटकर प्लॉटिंग साइट के लिए चौड़ा रास्ता बनाया गया था। एसडीएम बृजेश कुमार वर्मा के निर्देश पर राजस्व टीम ने नापजोख के बाद 14 जून को अतिक्रमण खाली करा दिया था। लेकिन अवैध कब्जेदार ने फिर से खेल मैदान की जमीन पर मिट्टी डालकर प्लॉटिंग के लिए रास्ता बना डाला। जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को भेजकर जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल मदन मोहन ने अर्जुनगंज के सरसवां निवासी जितेन्द्र यादव पर अवैध कब्जे के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम ने बताया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। दोबारा अतिक्रमण के मामलों में एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने अवैध कब्जेदारों को कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं सरकारी जमीनों से अतिक्रमण खाली करने की चेतावनी दी।

निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राजधानी लखनऊ में टिकैत राय तालाब पर स्थित सुप्पा रौस पर समाजसेवी संगठन ऑलमाइटी शिवा एसोसियेशन, एन.जी.ओ द्वारा जरूरतमंद बच्चों, छात्रों के लिए निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ऑलमाइटी शिवा एसोसियेशन, एन.जी.ओ की अध्यक्षा अनीता चैधरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संस्था के सचिव आदित्य चैधरी ने कहा कि इस निशुल्क कम्प्यूटर सेंटर खुल जाने से जरूरतमंद स्टूडेंट्स व युवाओं को कंप्यूटर का ज्ञान मिलेगा और इससे उनका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। संस्था के सचिव आदित्य चौधरी ने बताया कि आलमाइटी शिवा एसोसिएशन अपने दायित्वों और समाज के प्रति कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

योगी सरकार के मंत्रियों ने की केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ

देश की 140 करोड़ जनता की आशाओं का प्रतिबिम्ब: जयवीर सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट देश की 140 करोड़ जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं का दर्पण है। यह बजट भारत को तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को साकार करने वाला दस्तावेज है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इसके साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक रोड मैप भी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यूपी को जनसंख्या के अनुरूप अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी है।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज: योगेंद्र उपाध्याय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आम बजट 2024-25 को विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है । उन्होंने कहा कि इस बजट में अंत्योदय की भावना, विकास की संभावनाएं और नवोन्मेष की दृष्टि को शामिल किया गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा समेत समाज के सभी तबकों का समग्र विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मंत्री उपाध्याय ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में नए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बजट को नए भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व के ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

किसानों के लिए लाया नई उम्मीदें: सूर्य प्रताप शाही

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आम बजट 2024-25 को 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। इस बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावनाएं और नवोन्मेष को प्रमुखता दी गई है। मंत्री शाही ने बताया कि बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में शामिल होंगी। अगले दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसके कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक संस्थाएं और इच्छुक ग्राम पंचायतें संलग्न होंगी।

एमएसएमई के लिए किए गए विशेष प्रावधान: राकेश सचान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बजट 2024-25 को एक सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। इस बजट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

सबसे प्रमुख घोषणा एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम की है, जिसके तहत एमएसएमई इकाइयों को कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक स्व-वित्तपोषित गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा, जो प्रत्येक उधारकर्ता को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान करेगा। इस पहल से उन छोटी इकाइयों को लाभ मिलेगा जो अपरिहार्य कारणों से समय पर ऋण चुकता नहीं कर पा रही हैं, और इससे उनके खातों को एनपीए होने से भी बचाया जा सकेगा। वर्तमान में, एमएसएमई इकाइयों को विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बजट में एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल पेश किया जाएगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

यह नई प्रणाली बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगी, जो अब तक परंपरागत रूप से असेट्स और टर्नओवर के आधार पर ऋण देती रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए होगी जिन्होंने पूर्व में लिए गए ऋण को तय समय सीमा में चुकाया है।

विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण होगा बजट: एके शर्मा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वर्तमान बजट विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार का यह आम बजट दूरदर्शी, सर्वस्पर्शी, सर्वोन्मुखी, सर्वसमावेशी बजट है, जो कि किसानों, मजदूरों, कामगारों, युवाओं व महिलाओं के साथ सर्व समाज के विकास को समर्पित है। बजट में विकास के 09 क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने से देश का समग्र विकास होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए तथा सभी को भरपूर अवसर देने के लिए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकास के 09 क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।

विकसित भारत बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण: भूपेन्द्र सिंह चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आम बजट को भारत और भारतवासियों की आत्मनिर्भरता के लिए संकल्पित बजट बताते हुए कहा कि 2024-25 का केंद्रीय आम बजट भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत्योदय को समर्पित एवं चौतरफा विकास से समावेषित विकसित भारत के लिए बजट नि:संदेह गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा समेत समाज के समस्त वर्गों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है।

चौधरी ने कहा कि अंत्योदय के प्रण व समग्र विकास के संकल्प को आकार देता यह बजट नए भारत के स्वर्णिम युग को और उत्तम मजबूती प्रदान करेगा। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों, करदाताओं सहित सभी वर्गों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट से भारत आर्थिक व सामरिक रूप से सशक्त होगा और देश वैभवशाली व आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करेगा। प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के संकल्प को समाहित किए हुए बजट देशवासियों की आर्थिक उन्नति तथा गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान के सपनों को साकार करने बाला है। मैं हर गांव, हर घर को उद्यमी बनाने के लिए संकल्पित इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों की तरफ से हृदयतल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

बिना पंजीयन चल रहे अस्पताल तत्काल बंद हों: डीएम

● स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक सम्पन्न

संवाददाता। सोनभद्र

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी व सम्बन्धित नोडल अधिकारी पंजीयन निजी चिकित्सालय को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी चिकित्सालय में चिकित्सकों के उपलब्धता से सम्बन्धित चिकित्सालय के बोर्ड पर उनके उपस्थिति सहित अन्य बिन्दुओं की सूचना अनिवार्य रूप से अंकित की जाये, यदि इस प्रकार के कोई सूचना प्राईवेट चिकित्सालय द्वारा अंकित नहीं की जाती तो उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने कहा कि बिना पंजीयन के जनपद में यदि कोई भी चिकित्सालय संचालित हो रहे हों, तो वह तत्काल बन्द कर दिये जाये, उन्होंने कहा कि प्राईवेट चिकित्सालयों की संघन जॉच नियमित रूप से सम्बन्धित टीम द्वारा सुनिश्चित की जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, इस दौरान उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत अल्ट्रासाउण्ड कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाये और यह भी सुनिश्चित की जाये कि गर्भवती महिलाओं का प्रसव चिकित्सालयों में ही कराया जाये, इस दौरान जिलाधिकारी ने यूपीआरएनएस द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तो निर्माण कार्यो की प्रगति धीमी पायी गयी।

जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूता महिलाओं के खाते में भेजे जाने वाली धनराशि के भुगतान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के नोडल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रसुता महिलाओं के खाते में धनराशि का भुगतान निर्धारित समय के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण दवा की उपलब्धता टीकाकरण अल्ट्रासाउण्ड आदि कार्यों की प्रगति समीक्षा की, समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य रहने हेतु समय समय पर टीककरण के साथ ही दवाएं आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी नियमित रूप से किया जाये।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अश्वनी कुमार, एसीएमओ डॉ0 आर0जी0 यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनित सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित रहे।

बड़ी घटना का कारण बनेगा लटकते तारों का जंजाल

सोनभद्र। मंगलवार को जनपद मुख्यालय स्थित शीतला मंदिर चौक के पास बिजली के खंभे पर मकड़जाल की तरह लटके हुए तारों का जंजाल दोपहर में दिवाली के पटाखे की तरह जलने लगा खंबे पर भयावह आग भी लग गई सारे तार टूट के नीचे की ओर गिरने लगे ऐसा लगा कि आसपास स्थित मकान में आग लग जाएगी। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य आशुतोष कुमार दुबे आशु ने कहा कि राबर्ट्सगंज में दर्जनों खम्बो पर इस तरह का मकड़ जंजाल लगा हुआ है। बरसात का समय चल रहा है पानी के संपर्क से खम्बो में करंट भी आ सकता है एक डेढ़ साल पहले इसी चौराहे के पहले खंबे पर एक पशु भी खंबे के टच में आने पर करंट से मर गया था। उस घटना को भी देखकर बिजली विभाग के लोगों ने सबक नहीं लिया, आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि तारों का मकर जंजाल हटाया नहीं जा रहा। अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।

एनएसीए टेक्नोलॉजी आधारित पेवर ब्लॉक्स व टाइल्स के निर्माण का हुआ शुभारंभ

संवाददाता। बीजपुर, सोनभद्र

एनटीपीसी रिहंद, भारत सरकार की अग्रणी विद्युत उत्पादक कंपनी, अपनी एनएसीए टेक्नोलॉजी आधारित पेवर ब्लॉक्स और टाइल्स विनिर्माण के सफल शुभारंभ की घोषणा करते हुए गर्वित है। एनटीपीसी की सभी परियोजनाओं में, एनटीपीसी रिहंद ऐसा करने वाली दूसरी इकाई है और जो की एनटीपीसी समूह के नवाचार और राख उपयोगिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें एनएसीए नैनों कंक्रीट एग्रीगेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले पेवर ब्लॉक्स और टाइल्स का उत्पादन किया जाएगा, जिससे विद्युत संयंत्र से उत्पन्न फाइन राख का उपयोग किया जाएगा।

इस पहल से न केवल राख के उपयोग में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बनाने में बढ़ावा मिलेगा, जो की कंपनी के सतत् विकास के मिशन के अनुरूप है। एनटीपीसी रिहंद के मुख्य महाप्रबंधक, परियोजना प्रमुख, पंकज मेदीरत्ता ने अपने सम्बोधन में कहा कि, हमें इस अत्याधुनिक सुविधा द्वारा विनिर्मित पेवर ब्लॉक्स और टाइल्स निर्माण कार्यक्रम के शुभारंभ पर गर्व हैं, जो न केवल हमारी राख उपयोगिता को बढ़ाएगा बल्कि 100 प्रतिशत राख उपयोगिता के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देगा, हमारा लक्ष्य हमेशा से ही सयंत्र में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाते हुए सतत् विकास को हासिल करना रहा है। और इस दिशा में आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नवनिर्मित उद्योग की उत्पादन क्षमता वर्तमान में 2000 ब्लॉक्स प्रतिदिन बनाने की है जिसको वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ाकर 20,000 ब्लॉक्स प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक निर्माण में उच्च गुणवत्ता की फाइन फ्लाई ऐश सीमेंट का उपयोग किया जाएगा।

चंद्रशेखर आज़ाद व लोकमान्य तिलक को जयंती पर किया याद

सोनभद्र। शहीद स्थल प्रबंधन ट्रस्ट करारी पर मंगलवार को सुबह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर याद किया गया। इस मौके पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें एक से बढ़कर एक रचना कवियों ने सुनाई और वाहवाही लूटी। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि शिवदास चंदौली ने अमर सेनानियों को माल्यार्पण दीपदान कर विधिवत शुभारंभ किया।

कवियित्री कौशल्या कुमारी चौहान ने वाणी वंदना के पश्चात तीर हूं तलवार हूं अंगार हूं भारत की मिट्टी से मैं करती प्यार हूं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संचालन कर रहे युवा गीतकार दिलीप सिंह दीपक नें बुजुर्गो ने लहू देकर वतन की आबरू रक्खी, तुम सब कुछ बेच दो लेकिन हिंदुस्तान मत बेचो सुनाकर वाहवाही बटोरी। आयोजक प्रदुम्न त्रिपाठी एड ने सरहद के पहरेदारों को शत-शत मेरा प्रणाम जाये। देश खड़ा है साथ आपके ए मेरा पैगाम जाये। आजाद तिलक बिस्मिल हमीद बन देने कुर्बानी आयेंगे। जयहिंद अमर वंदेमातरम् स्वर तिरंगा नभ में लहराये सुनाकर देशप्रेम की अलख जगाया। इस अवसर पर शायर अशोक तिवारी राष्ट्रवाद के सजग प्रहरी प्रभात सिंह चंदेल हास्य व्यंग के दिवाकर मेघ, लोकभाषा भोजपुरी के दयानंद दयालू, सोन साहित्य संगम के सचिव राकेश शरण कवि धर्मेश चौहान एडवोकेट आदि साहित्यकारों ने कविता सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर विबस किया तो अध्यक्षता कर रहे कवि शिवदास ने लहर रहा है गगनांगन में गौरव का अभिमान जयति जै संविधान जयति जय हिंदुस्तान सुनाया और पूर्णता प्रदान किया। सामुहिक स्वर में बच्चों ने सोहर बधाई गीत प्रस्तुत कर सभीं का दिल जीत लिया।

लोकमान्य तिलक टर्मिनल दूरंतो के फेरे में वृद्धि की मांग

● प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी पर स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

संवाददाता। प्रयागराज

प्रयागराज जंक्शन के स्टेशन निदेशक वी के द्विवेदी की अध्यक्षता में स्टेशन सलाहकार समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की जानकारी ली गई। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। जिसमें सदस्यों ने तमाम सुझाव दिए।

बताया गया कि प्लेटफॉर्म संख्या छह पर शेड का विस्तार प्लेटफॉर्म संख्या सात और आठ एवं नौ और दस पर यात्रियों को बैठने हेतु व्यवस्था का विस्तार गाड़ी संख्या 12294/93 प्रयागराज जंक्शन लोकमान्य तिलक टर्मिनल दूरंतो के फेरे में वृद्धि की जाए।

बैठक में स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य उमेश कक्कड़ राहुल शर्मा उत्तम केशरवानी स्टेशन प्रबंधक दिलीप ठाकुर वाणिज्य निरीक्षक राम प्रसाद मीणा निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल एस के सिंह स्वास्थ्य निरीक्षक आर के रॉय उपस्थित थे। इसी प्रकार प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक कुमार राकेश एवं मुख्य वाणिज्य निरीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में स्टेशन सलाहकर समिति की बैठक आयोजित की गयी। स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों ने स्टेशन अधीक्षक एवं मुख्य वाणिज्य निरीक्षक के साथ स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

बैठक में स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा स्टेशन का भ्रमण कर स्टेशन के विकास के लिए निम्न सुझाव दिया गया। कहा गया कि प्लेटफार्मों पर बेंचों एवं पंखों की संख्या बढ़ायी जाए एवं वेटिंग हॉल का विस्तार किया जाए। गाड़ियों में ओवर क्राउडिंग को रोका जाए। वीआईपी पार्किंग को बेहतर बनाया जाए। प्लेटफार्म संख्या चार के बाहर वाली रोड को रोड ओवर ब्रिज तक पक्का किया जाए ताकि दूसरी तरफ के लोगों का आवागमन आसान हो सके। गेट संख्या तीन पर फुट ओवर ब्रिज एवं रैम्प बनाए जाए। साफ सफाई को और बेहतर बनाया जाए। सभी निर्माणाधीन कार्य कुम्भ मेला से पहले पूर्ण किए जाए।

दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को ठहराव दिया जाए। बैठक में स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य ज्ञान सिंह पटेल जय सिंह पटेल राजेश्वरी प्रसाद तिवारी वरिष्ठ खंड अभियंता आलोक रंजन वरिष्ठ खंड अभियंता मुल्कराज यादव स्वास्थ्य निरीक्षक संजय पांडेय कनिष्ठ अभियंता रुपेन्द्र प्रताप सिंह खानपान निरीक्षक शरद चौहान उपस्थित थे। यह जानकारी अमित कुमार सिंह जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज मण्डल उत्तर मध्य रेलवे ने दी।

क्विक न्यूज

बजट आम जनता के जीवन को समृद्ध और सुगम बनाने का प्रयास है: सुनील सिंह

गाजीपुर। भारतीय जनता पार्टी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पूर्ण बजट प्रस्तुत कर लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने आज की बजट में कृषि, युवाओं के रोजगार, उर्जा, शहरों के विकास, महिलाओं के समृद्धि सम्मान के लिए मजबूत सोच को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मध्यम श्रेणी के लोगों को बजट में लाभ देते हुए सरकार ने 7.75 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैंसर की दवा सहित जरूरत के सामानों पर से कस्टम ड्युटी कम करने से तथा युवाओं के लिए मुद्रा लोन को दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने से रोजगार व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा नये रोजगार सृजित होंगे। कहा कि सरकार ने आज की बजट में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया है, सरकार ने फेमिली पेंशन के टेक्स पर 15 हजार की छूट को बढाकर 25000 कर दिया है तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सरकार फ्री बिजली के लिए प्रयासरत हैं। यह बजट भारत के मजबुती आम जनता के जीवन को समृद्ध और सुगम बनाने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास है।

पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में शिव सेवा भक्त मंडल द्वारा कांवरियों को दी जा रही निशुल्क सुविधा

गाजीपुर। जनपद के गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में रविकांत पांडेय अभिषेक सिंह आशुतोष पांडेय के नेतृत्व में शिव सेवा भक्त मंडल गाजीपुर व मऊ द्वारा देवघर झारखंड में सावन महीने में कांवड़ यात्रियों के लिए निशुल्क सेवा शिविर का हर साल आयोजन किया जाता है। जिसमें इस साल तीसरा शिविर शिव सेवा भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा देवघर झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कांवरिया पथ पर घोरमारा नियर आधात्मिक भवन के पास शिव सेवा भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा सेवा शिविर का हर साल आयोजन किया जाता है। इस साल तीसरा भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक सिंह व महामंत्री रविकान्त पांडेय ने बताया कि हमारे ट्रस्ट द्वारा सभी भक्तों को निशुल्क सेवा दी जाती है। जिसमें ठंडा पानी गर्म पानी नीबू सरबत, चाय, फलाहारी, भोजन, दबाये व ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जाता है। जिससे कि आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इस ट्रस्ट के संरक्षक अजीत सिंह त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन के सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन चलता है। इसके मुख्य रूप से सहयोगी गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन, त्रिशक्ति कंस्ट्रक्शन, इस संस्था के कोषाध्यक्ष आशुतोष पांडेय ए के ट्रेडर्स मऊ, शहनाई मैरिज हॉल, अनिल कुमार पांडे, राजीव त्रिपाठी, अनिल उपाध्याय, दीप लाइटहाउस, नर्सिंग रेडियो, सत्येंद्र सिंह, आरआर ज्वैलर्स, व कोलकाता फ्लावर डेकोरेशन सहित सैकड़ो लोग हैं।

संकट मोचन मंदिर मे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया गया हवन पूजन

मीरज़ापुर। नगर में सावन का पवित्र माह प्रारंभ होने के बाद भी बरसात अपेक्षित नहीं होने के कारण मिर्जापुर जनपद में सूखा पड़ने की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी जनपद मिर्जापुर द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव काशी प्रांत सुनील कुमार पांडे एडवोकेट जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बी सिंह जिला महासचिव दिलीप सिंह गहरवार एडवोकेट द्वारा मिर्जापुर के ऐतिहासिक संकट मोचन मंदिर पर पूरे विधि विधान से हनुमान जी के दरबार में बैठकर मिर्जापुर के विद्वान पंडित आचार्य पंडित सुजीत कुमार पांडे जी के सानिध्य में मिर्जापुर में बारिश होने के लिए भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ किया गया और पूजन हवन करके भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने और मिर्जापुर में बरसात होने के लिए प्रार्थना किया गया आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव काशी प्रांत सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने कहा कि मिर्जापुर के किसानों एवं व्यापारियों और आम नागरिकों के हितार्थ और गर्मी से निजात के लिए भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शीघ्र वर्षा के लिए यह हवन यज्ञ किया गया।

शत प्रतिशत हिन्दी में किया जाए फाइलों में नोटिंग एवं मूल पत्राचार: जीएम कोर

संवाददाता। प्रयागराज

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज में महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि मुख्यालय सहित परियोजनाएं धारा 3 (3) का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि इसमें किसी भी कार्यालय को छूट प्राप्त नहीं है इसका अनुपालन हर हाल में शत प्रतिशत ही किया जाना है।

महाप्रबंधक श्री वर्मा ने कहा कि फाइलों में नोटिंग एवं मूल पत्राचार शत प्रतिशत हिन्दी में किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को हिंदी में अधिकांश काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए मुख्यालय सहित परियोजनाओं में हिंदी की विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठी कार्यशाला हिंदी प्रतियोगिताओं आदि का समय समय में आयोजन सुनिश्चित किया जाए। जिससे वहां के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रोत्साहित हों एवं हिंदी के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

महाप्रबंधक ने रेलवे बोर्ड द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए संजय सिंह नेगी मुख्य बिजली इंजीनियर एमपी को रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। इससे पहले मुख्य राजभाषा अधिकारी एस एस नेगी ने अध्यक्ष महाप्रबंधक सहित सभी उपस्थित अधिकारियों एवं मुख्य परियोजना निदेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि यद्यपि हमारे संगठन में राजभाषा का काफी प्रयोग हो रहा है। यह देखा गया है कि यहां अधिकतर काम हिंदी में होता है फिर भी सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है।

इसलिए कंप्यूटर ई मेल तथा वेबसाइट में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही मूल रूप से हिंदी में टिप्पणी लेखन तथा पत्राचार भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

बैठक में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष यतेन्द्र कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर एन सिंह प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर उपेन्द्र कुमार मुख्य बिजली इंजीनियर कार्य एवं परियोजनाओं के मुख्य परियोजना निदेशक तथा उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं कोर मुख्यालय के सभी विभागों के संपर्क अधिकारी राजभाषा भी शामिल हुए। बैठक का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य राजभाषा अधिकारी कल्याण सिंह ने किया।

25 से 29 जुलाई तक होगा कार्यक्रम का आयोजन

प्रयागराज। कार्यक्रम का आयोजन 25 से 29 जुलाई तक होगा। अमेजन ब्यूटी के साल के सबसे बहुप्रतीक्षित ब्यूटी इवेंट द ब्यूटी सेल वापस आ रहा है जो लोरियल प्रोफेशनल और लव ब्यूटी एंड प्लानेट के सहयोग से लोरियल पेरिस द्वारा समर्थित है। 25 से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाला इस सेल का चौथा संस्करण टॉप ब्रांड्स ट्रेंडिंग स्किनकेयर सामग्री नए उत्पाद लांच और अद्वितीय खोजों के विशेष रूप से तैयार चयन के साथ और अधिक रोमांच का वादा करता है। यह सभी आप अमेजन की त्वरित डिलीवरी और भरोसेमंद खरीदारी अनुभव की सुविधा के साथ किफायती मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। जेबा खान डायरेक्ट ब्यूटी पर्सनल केयल और लग्जरी ब्यूटी अमेजन इंडिया ने कहा अमेजन ब्यूटी में हम अपने ग्राहकों को टॉप ब्यूटी ब्रांड्स के विशेष चयन फास्ट डिलीवरी और व्यक्तिगत सुझाव प्रदान करके एक उन्नत ऑनलाइन ब्यूटी शॉपिंग अनुभव प्रदान करने को प्रतिबद्ध हैं।

आईपीएस जुगल किशोर को बहाल करने की उठाई मांग

गाजीपुर। जनपद में मंगलवार को ब्राह्मण रक्षा दल ने आई पी एस जुगल किशोर तिवारी का निलंबन वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी कासिमाबाद को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें उपमहानिरीक्षक को निर्दोष करार देते हुए निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगायी गई। ब्राह्मण रक्षा दल के संयोजक प्रेम शंकर मिश्र ने बताया कि जुगलकिशोर तिवारी, जो एक कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ व निर्भीक पुलिसअधिकारी रहे हैं, को संभवत: शासन ने इसलिए निलंबित किया क्योंकि वे मानवीय आधार पर हाथरस के ग्रामप्रधान स्व. योगेश उपाध्याय, जिनकी हत्या हिस्ट्रीशीटर जीतूसिंह ठाकुर व उसके साथियों ने की थी, के त्रियोदशाह में शामिल हुए थे। जुगलकिशोर तिवारी जी की छवि पीड़ितों के प्रति सदैव सहयता हेतु तत्पर रहने वाले व्यक्ति/अधिकारी के रूप में भी रही है। ये वही बहादुर पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने 2007 में दर्जनों मामलों में वांछित चल रहे माफिया व सांसद अतीक अहमद के इलाहाबाद में स्थित मकान के अंदर लगी नल की टोटी से लेकर चौखट बाजू तक उखड़वा कर सारा सामान जब्त करवा कर थाने में जमा करा उसके यहां बुलडोजर चलवा दिया था. विशेष बात यह है कि ये बुलडोजर तब चलवाया था जब अतीक की तूती बोलती थी। इन्होंने ही चित्रकूट जनपद में फैले पाठा के घने जंगलों में विगत 16 जून 2009 को तीन दिनों तक चली कार्रवाई में दुर्दांत डकैत घनश्याम केवट का लाइव इनकाउंटर किया था. आपने चित्रकूट के जंगलों से डकैतों का लगभग सफाया कर पूरे क्षेत्र में शांति बहाली का काम किया था। पत्रक देने वालों में विधानसभा अध्यक्ष तारकेश्वर पाण्डेय, गोपाल पाण्डेय, मृत्युंजय मिश्र, अन्नू पाण्डेय, अवनीश पाण्डेय, राकेश पाण्डेय, आदि शामिल रहे।

पॉवर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता की बर्खास्तगी का आदेश अदालत ने किया रद्द

● तीन माह में नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश

संवाददाता। प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता संजय शर्मा की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा की बर्खास्तगी का आदेश जारी करते समय जांच अधिकारी ने जांच के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने विभाग को तीन माह में नए सिरे से नियमानुसार जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अधिशासी अभियंता अपने पद पर काम करते रहेंगे तथा उनका नियमानुसार वेतन भुगतान का भी निर्देश दिया है।

गौतम बुद्ध नगर के संजय शर्मा को पांच अक्टूबर 2019 को शिकायत मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ नियमित जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के बाद तीन सदस्य जांच कमेटी गठित की गई। विभागीय जांच कमेटी ने याची को चार्जशीट जारी किया। जिस पर याची ने अपना प्रति उत्तर दाखिल किया। उसके जवाब से असंतुष्ट होते हुए जांच कमेटी ने याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि याची को जारी चार्जसीट को सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है जबकि नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ही चार्जशीट जारी की जा सकती है। इस प्रक्रिया के आभाव में की गई कार्रवाई अवैधानिक है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याची क मौखिक बयान दर्ज करने के सिवाय कोई अन्य जांच नहीं की गई। जांच अधिकारी ने विभागीय गवाहों के बयान नहीं लिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सत्यापित किए बिना जांच आगे बढ़ा दी। जो की अवैधानिक है। तथा बर्खास्त की आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

पॉवर कारपोरेशन के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एमडी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में अध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गई है। लिहाजा एमडी द्वारा जारी चार्जशीट स्वीकार करने योग्य है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने विभागीय जांच नियम अनुसार नहीं की है इसलिए विभागीय कार्रवाई और बर्खास्तगी का आदेश रद्द होने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि याची का निलंबन आदेश पहले ही हटाया जा चुका है। वह बर्खास्त होने से पूर्व अपने पद पर काम कर रहा था। उसे काम करने दिया जाए तथा नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जाए। इस दौरान तीन माह के भीतर नए सिरे से नियमानुसार विभागीय जांच पूरी की जाए।

सरकार ने बेरोजगारों के लिये कुछ नहीं किया: देवी चौधरी

मीरज़ापुर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने केन्द्र सरकार के आम बजट 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि इस बजट से उत्तरप्रदेश के लिये कुछ नही है जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिये क्या प्रावधान किये गये है ? इस सरकार ने बेरोजगारों के लिये कुछ नही किया है, अगर हम उत्तरप्रदेश को ही देख ले तो निवेश की हालत क्या रही होगी। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार और आन्धप्रदेश के लिये विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है अगर सरकार बचानी है तो अच्छी बात है लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता है क्या यहां के किसानों के लिये कोई बड़े फैसले किये गये है, किसानों के फसल की पैदावार की कीमत के लिये कोई इन्तजाम है। कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नही होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नही पहुंचेगा। इन्होने जो बेरोजगारी बढ़ाई है उसको कैसे कम करें वो भी आधी-अधूरी नौकरी से और बड़ा सवाल यह है कि क्या जो आधी-अधूरी नौकरी है उसमे आरक्षण होगा।

पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री डॉ एस कृष्ण कुमार ने निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और और पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ एस कृष्ण कुमार को हरी भरी समूह का निदेशक और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरी भरी वेस्ट वलोराइज़ेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया।

डॉ एस कृष्ण कुमार को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा सुधारों के लिए जाना जाता है क्योंकि अक्षय ऊर्जा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत के ऊर्जा पुरुष के रूप में सम्मानित किया गया था। देश के प्रतिष्ठित पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ एस कृष्ण कुमार वर्तमान में भाजपा में हैं।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके पास क्रांतिकारी अपशिष्ट से बिजली बनाने वाली नवीन तकनीक लाने की बड़ी योजना है। जो निश्चित रूप से देश को कम लागत वाली बिजली और सर्वोत्तम अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक प्रदान करेगी। जिसे हरि भरी निकट भविष्य में शुरू करेगी। वर्तमान में हरी भरी प्रयागराज मुरादाबाद और पटियाला में अपशिष्ट प्रबंधन का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है। निकट भविष्य में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। हरी भरी की नॉर्वे स्थित एनजीटी कंपनी के साथ इसकी नवीन अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक संयुक्त उद्यम है।

उसने विभिन्न स्थानों पर इसे विकसित करने के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले पांच वर्षों के लिए हरि भरी इन परियोजनाओं के लिए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धता एफडीआई सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर है। डॉ एस कृष्ण कुमार को निदेशक बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज तिवारी ने बधाई दी है।

भाट समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाट समुदाय के वर्ग के लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने अखिल भारतीय भाट समाज एकता और इसके अध्यक्ष पवनेंद्र कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी भाट समाज को विमुक्त जनजाति के रूप में रखा गया है। उन्हें एसटी वर्ग में शामिल करने के मामले को लटकाया गया है। यह भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार को रोजगार में भाट समुदाय को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि विमुक्त जनजाति भाट समुदाय को एक सरकारी आदेश (मई 1961) में विशेष दर्जा दिया गया था।

जिसमें विमुक्त जनजाति समुदाय की शिक्षा शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए यह प्रस्ताव दिया गया था कि उन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक रोजगार के लिए आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाय। याची का कहना है कि यूपी के विभिन्न जिलों में स्थायी जीवन जीने और राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभांवित होने के बावजूद उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि वह इसके हकदार हैं। कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी याची को विमुक्ति जनजातियों के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि वह प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थायी जीवन जी रहे हैं और राज्य के सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव
पीछे हटे बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन पीछे हट गए हैं और उन्होंने ट्रंप का मुकाबला करने के लिए कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य के बारे में आशंकाओं को देखते हुए अंतत: जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। उनके स्थान पर संभवत: अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होंगी। इस प्रकार अब मुकाबला कमला बनाम ट्रंप होगा जो पिछले चुनाव में राष्ट्रपति पद पर पुन: निर्वाचित होने के लिए चुनाव में जो बाइडेन से हार गए थे। चुनाव के समय 82 वर्ष की आयु वाले राष्ट्रपति बाइडेन ने व्यक्तिगत कारणों से नए नेतृत्व को स्थान देने की इच्छा प्रकट की है। व्हाइट हाउस से अपने संबोधन में उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस में उनके प्रशासन का एजेंडा आगे बढ़ाने तथा राष्ट्र को आगे ले जाने की नेतृत्व क्षमता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि 'काफी लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने व उनकी पत्नी ने सोचा कि यह नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का समय है।' उन्होंने उल्लेख किया कि उप-राष्ट्रपति हैरिस ने राष्ट्रपति कार्यकाल के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय में उनका साथ दिया और वे सुश्री हैरिस की प्रतिबद्धता, बुद्धि तथा अमेरिकन जनता के प्रति अडिग निष्ठा के गवाह रहे हैं। कमला हैरिस की उम्मीदवारी अनेक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है। चुने जाने पर वे पहली महिला राष्ट्रपति तथा इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत व दक्षिण एशियाई अमेरिकन होंगी। उप-राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुकी हैरिस, खासकर अपराध न्याय सुधार, आप्रवास व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रशासनिक क्षमता वाली हैं। लेकिन

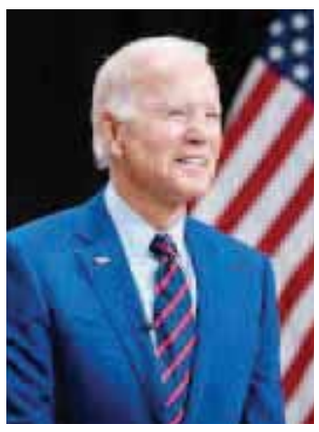

हैरिस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनको संभवत: 'प्राइमरी' की दौड़ के साथ ही आम चुनाव प्रचार अभियान में सफल होना होगा। उनको डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रगतिशील व मध्यमार्गी समूहों को संबोधित करते हुए भविष्य का एक आकर्षक दृष्टिकोण पेश करना होगा ताकि ढुलमुल मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो सके। उम्मीद है कि उनके अभियान में वर्तमान प्रशासन की उपलब्धियां रेखांकित की जाएंगी जिनमें आर्थिक सुधार प्रयास, कोविड-19 वैश्विक महामारी से मुकाबला तथा सामाजिक न्याय व समानता को प्रोत्साहित करने वाली पहलें शामिल हैं।

जो बाइडेन का निर्णय अभूतपूर्व है क्योंकि किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार ने इतने विलम्ब से निर्णय नहीं लिया है। उनके निर्णय के पीछे दो महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। पहला, 'राष्ट्रपति बहस' में उनके निस्तेज प्रदर्शन के कारण विपक्षी देश का नेतृत्व करने की उनकी पहचान पर सवाल उठाने लगे थे। दूसरा, हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप सुर्खियों में आ गए हैं और उनके प्रति व्यापक संवेदना उमड़ी है। हालांकि, दोनों घटनायें असंबद्ध हैं, पर इनके कारण डेमोक्रेटों को अन्य विकल्पों पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपब्लिकन पक्ष को इस घोषणा के बाद नीतियों का पुन: आंकलन करना पड़ेगा। बाइडेन के दौड़ से बाहर होने के बाद अब संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवारों को कमला हैरिस की नीतियों से मुकाबले पर ध्यान देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप व फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में हैं। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि कमला हैरिस अपने अभियान को क्या रूप देती हैं, देश के सामने उपस्थिति महत्वपूर्ण मुद्दों को कैसे संबोधित करती हैं तथा अपने समर्थन में एक व्यापक गठबंधन बनाती हैं। उनकी उम्मीदवारी अमेरिकन राजनीति में नया अध्याय खोल रही है जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी तथा देश का भविष्य निर्धारित हो सकता है।

ग्रामीण आर्थिक विकास की रूपरेखा

भारत का ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लघु व हरित उद्यमों से उसका परिवर्तन हो सकता है। उसमें भारत का 'विकास इंजन' बनने की संभावना है।

मोनिका बी. सूद
(लेखिका, विकास विशेषज्ञ हैं)

समावेशी व टिकाऊ विकास के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। यह बदलाव लघु एवं हरित उद्यमों के माध्यम से संभव है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, महिला सशक्तीकरण होगा तथा कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। पूंजीगत परियोजनाओं तथा खोजी योजनाओं में आरबीआई द्वारा प्राप्त अतिरिक्त एक लाख करोड़ डिविडेंट जैसी धनराशि का प्रयोग कर भारत ग्रामीण क्षेत्रामें में स्व-टिकाऊपन को प्रोत्साहन दे कर युवाओं से दबाव कम कर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से न केवल रोजगार की तत्कालीन आवश्यकतायें पूरी होंगी, बल्कि दीर्घकालीन पूंजी निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण की नीव भी पड़ेगी। लघु एवं हरित उद्योगों को 'विकास इंजन' के रूप में अवसर मिलना चाहिए। लघु उद्यम हमेशा से भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। इन श्रम-बहुल उद्यमों में कृषक समाज की अकुशल व अर्धकुशल श्रमशक्ति को समाहित कर रोजगार सृजन के साथ बिना ज्यादा प्रशिक्षण के वर्तमान जीवन मानकों में बदलाव लाया जा सकता है।

इन उद्योगों के विकास से अन्य बिजनेसों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा जो उनको तथा सामान्य अर्थव्यवस्था की सहायता करते हैं। इसमें हरित उद्योग परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, आर्गेनिक खेती तथा टिकाऊ विनिर्माण को शामिल करने वाले ये क्षेत्र अक्सर दुहरा लाभ देते हैं। इससे उत्पादन एवं पर्यावरण प्रबंधन में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हरित उद्योगों की स्थापना से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के कारण पैदा सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है तथा आजीविका के टिकाऊ साधन विकसित होते हैं। इसके लिए बायोगैस व बायोफ्यूल प्लांट, सौर ऊर्जा फार्म, आयुर्वेदिक व यूनानी दवा उद्योग तथा सहकारी आर्गेनिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन उपायों से रोजगार सृजन होगा, फासिल ऊर्जा पर निर्भरता घटेगी तथा पर्यावरण संरक्षण होगा।

भारत में कुल ग्रामीण जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत है जिसमें से अधिकांश का लाभ नहीं उठाया गया है। इन महिलाओं में रोजगार और उद्यमिता की वृद्धि से काफी सामाजिक-आर्थिक लाभ हो सकते हैं। सूक्ष्म एवं टिकाऊ उद्योग महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं क्योंकि वे महिलाओं को रोजगार देने, कौशल विकास तथा बिजनेस अवसर प्रदान करते हैं। स्वयंसहायता समूह, महिला-आधारित कोआपरेटिव तथा सूक्ष्म उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की उत्पादक सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पहलों का केन्द्र वे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं का प्रभुत्व है। इनमें हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल उत्पादन, वैकल्पिक व आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। महिलाओं को अपने बिजनेस स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए कर्ज, प्रशिक्षण तथा बाजार से संपर्क जरूरी हैं। इससे उनके परिवारों की आय बढ़ती है तथा सामुदायिक विकास होता है। ग्रामीण विकास में सार्वजनिक-निजी साझेदारी या पीपीपी को बढ़ावा देने से ग्रामीण विकास में कौशल व संसाधनों को एकत्र करने में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार पीपीपी माडल लघु एवं हरित उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने की पहल कर सकते हैं तथा सरकारी और निजी निवेशकों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इसके लिए नीतिगत समर्थन के साथ ही विकास एवं वित्तीय समर्थन का परिवेश तैयार कर सकती है, जबकि निजी पक्ष फंड, तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन कौशल में उनकी सहायता कर सकते हैं। इस माडल के आधार पर ग्रामीण विकास के लिए आरबीआई द्वारा मिले एक लाख करोड़ रुपये डिविडेंट के एक हिस्से का प्रयोग निजी उद्यमों के साथ सह-फाइनेंस के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्लस्टरों के निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में किया जा सकता है जहां सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन व जवाबदेही सुनिश्चित हो।

पूंजी का निर्माण तथा ग्रामीण विकास विकास की दो महत्वपूर्ण प्रक्रियायें हैं जिनको समझने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कुल मिला कर एक लाख करोड़ के आरबीआई डिविडेंट का प्रयोग टिकाऊ ग्रामीण विकास परियोजनाओं में पूंजीगत निवेश का मजबूत आधार बनाने के लिए हो सकता है। सड़कों, पुलों, नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं तथा इंडस्ट्रिल इस्टेटें बनाने के माध्यम से तत्काल रोजगार मिलेगा तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। लक्षित निवेश से हर साल लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे ग्रामीण बेरोजगारी और तनाव को काफी सीमा तक समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल और अर्धकुशल लोगों को रोजगार देना संभव होगा। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की भावी पीढ़ियों को बेरोजगारी से सुरक्षा मिलेगी, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों का पलायन थमेगा तथा शहरी-ग्रामीण असमानता घटेगी। स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में ग्रामीण नौजवानों को रोजगार मिलने से मानवशक्ति संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायता मिलेगी, सेवायें प्रदान करने में सुविधा होगी तथा जनसंख्या का कल्याण होगा।

रणनीतिक ग्रामीण विकास एजेंडे की फंडिंग के लिए लीक से हट कर सोचने की जरूरत है ताकि अनेक स्रोतों से फंडिंग जुटाई जा सके। एक लाख करोड़ रुपये के आरबीआई डिविडेंट की तरह सीएसआर के योगदान, पंचायतों और नगरपालिकाओं के अपने फंड तथा ईंधन, आयकर व जीएसटी पर खास सेस से प्राप्त धन को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनिवार्य रूप से सीएसआर फंड का 25 प्रतिशत योगदान कार्पोरेट धन के ग्रामीण विकास में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही लक्ज़री वस्तुओं, कारों, विमान किरायों तथा जीएसटी पर 0.5 प्रतिशत सेस लगाने से बहुत बड़ी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही कौशल विकास योजनाओं-एसकेएस तथा अस्पतालों के एसकेएस फंडों से आवश्यक क्षेत्रों में वेतन के लिए समुचित फंड प्राप्त किए जा सकते हैं। शेयर व्यापार पर थोड़ा सेस लगा कर ऐसी योजना के लिए काफी राजस्व जुटाया जा सकता है जिससे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए स्थाई फंडिंग संभव होगी।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को संबोधित करना जरूरी है। वर्तमान समय में भारत में बेरोजगारी 8 प्रतिशत का आंकड़ा छू चुकी है। देश में बेरोजगारों की कुल संख्या का 1 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। यदि प्रधानमंत्री बेरोजगारी की दर घटा कर 6 प्रतिशत करना चाहते हैं और यह विकसित देशों में बेरोजगारी दर के लगभग बराबर हो तो कम से कम एक करोड़ ग्रामीण नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना होगा। इस योजना को ग्रामीण नौजवान जनसंख्या में कम वेतन वाले रोजगारों पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे रोजगार के अवसर युवाओं को अपने समुदाय में रहने के लिए प्रेरित करें ताकि वे कुशल रोजगार अवसरों के मामले में प्रतियोगिता न करें। इस दृष्टिकोण से मजदूरी को 10,000 रुपये महीना निर्धारित कर कार्य का वितरण 80:20 के आधार पर ग्रामीण परिवारों में किया जाना चाहिए।

इससे संगठित श्रम रोजगार बाजारों में बाधा नहीं आएगी। ग्रामीण विकास के लिए रिजर्व बैंक के अतिरिक्त एक लाख करोड़ डिविडेंट के साथ ही फंडिंग के अन्य स्रोत खोले जाने चाहिए। इसका प्रयोग कर ग्रामीण पुनर्जीवन फंड का गठन तथा इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा सकता है। लघु उद्योग, हरित उद्योग, महिला तथा अकुशल ग्रामीण श्रमिक इस योजना को टिकाऊ बना सकते हैं। इससे बेरोजगारी घटेगी तथा पर्यावरण पर दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीपीपी तथा पूंजी निर्माण पर ध्यान देने से यह योजना टिकाऊ होगी, इसे विस्तार दिया जा सकेगा और यह ग्रामीण भारत की बेहतर तस्वीर पेश करेगी।

ओलम्पिक में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं

खेल मामलों की इस दयनीय स्थिति को लेकर बीओए और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।

ज्ञान भद्र
(लेखिका स्तम्भकार हैं)

बिहार एक बार फिर ओलंपिक में जगह बनाने से चूक गया। ज्ञान भद्र द्वारा इस महीने के आखिरी हफ्ते में पेरिस में 17 दिनों तक चलने वाले ओलंपिक खेलों का शानदार उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। इसके मद्देनजर भारत के खेल पंडित इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी देश के लिए कितने पदक जीतेंगे। हालांकि, इस लेख को लिखे जाने तक खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने 117 खिलाड़ियों और 140 सहायक कर्मचारियों की सूची पर अपनी मुहर लगा दी थी।

अब सवाल यह है कि क्या बिहार का कोई खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? इसका जवाब नहीं है। टोक्यो ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में भी बिहार के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला, जहां तक ??बिहार में खेल बुनियादी ढांचे की बात है तो यहां पर्याप्त संख्या में स्टेडियम, खेल से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र और कोचों के कुशल मार्गदर्शन का अभाव है। इसका कारण यह माना जा सकता है कि खेल क्षेत्र में सरकारी निवेश बहुत कम है। यहां तक कि बिहार सरकार को खेलो इंडिया योजना के तहत 50.83 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास या एथलीटों के कौशल को निखारने के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। खेल क्षेत्र को धन के आवंटन का पैटर्न निराशाजनक रूप से चिंताजनक है। यह देखा गया है कि खेल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निर्धारित धन राजनेताओं की मर्जी के अनुसार डायवर्ट किया जाता है।

इससे खेल उद्योग पर हमेशा बुरा असर पड़ता है, जो खुद को उलझन में पाता है और हमेशा संघर्ष करता रहता है।दूसरा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रमुख खेल निकायों के साथ राजनेताओं का जुड़ाव एक पुराना शगल है। हर योग्य राजनेता खेल निकायों का सदस्य

बनना चाहता है। चाहे वह बीसीसीआई हो या राज्य स्तर पर खेल निकाय, हर राजनीतिक नेता खेल निकायों में निवेश किए गए भारी धन का लाभ उठाना चाहता है, फिर बिहार कैसे पीछे रह सकता है? बिहार में खेलों के विकास के लिए काम करने वाले नायक बनने के बजाय, राजनेता, एक बार खेल निकायों में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के बाद, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का दोहन करते हैं। लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। लेकिन इतनी भी कम नहीं कि वे यह भूल जाएँ कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने बिहार की उभरती प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया था। क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लालू की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बीसीए के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, बिहार के किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं मिली थी; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े लीग मैचों की तो बात ही क्या करें। अब खेल पंडित यह तर्क दे सकते हैं कि बीसीए के अध्यक्ष के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान, बिहार के पास राज्य की रणजी टीम नहीं थी क्योंकि बिहार के विभाजन के कारण खेल सुविधाओं के मामले में बिहार को नुकसान हुआ था। झारखंड ने खेल सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा अपने पास ले लिया। हालांकि, खेल पंडितों द्वारा इस बहाने का सहारा लेना तब के कई युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बेकार था। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस समय राजद की अगुआई राबड़ी देवी कर रही थीं और लालू यादव राज्य की रणजी टीम बनाने और राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए योग्यतम कोच नियुक्त करने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे।

तीसरा, ओलंपिक खेलों के लिए एथलीटों को तैयार करने में बिहार ओलंपिक संघ (बीओए) की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार, बीओए के अधिकारी एथलीटों को विश्व स्तरीय ओलंपिक खेलों के स्तर पर तैयार करने के लिए कार्यक्रम और ट्रायल आयोजित करने की जहमत नहीं उठाते। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पेरिस ओलंपिक के लिए 117 एथलीट-सदस्यीय टीमों की सूची में बिहार का कोई भी एथलीट शामिल नहीं था। इससे भी बुरी बात यह है कि खेल मामलों की इस दयनीय स्थिति को लेकर बीओए और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बीओए बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कोचों की कमी के बारे में लापरवाही के लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि बीओए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित करने में खुद को असमर्थ पाता है। दूसरी ओर, राज्य सरकार यह कहकर बीओए के बारे में अपनी आवश्यक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है कि बीओए एक स्वतंत्र इकाई है और सरकार इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इस चल रहे संघर्ष में, उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हार रहे हैं। अंत में, यह कहा जा सकता है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना पहली नज़र में बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, बिहार में आवश्यक खेल संसाधनों की कमी के कारण, यह योजना कई युवा प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं कर पाएगी।

आप की बात

आरक्षण की सीमा

आजादी के बाद 10 वर्ष तक के लिए लागू आरक्षण अब राजनेताओं की चुनावी खेती बन गया है। इससे एक ओर तो जनता में आरक्षित व अनारक्षित के बीच खाई बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण के कारण आरक्षित्त जातियों में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो इसके लाभ को अपनी ही जातियों के गरीबों तक नहीं पहुंचने देता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाने का चुनावी वादा पूरे देश और समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए प्रबंधन क्षेत्र में 50 प्रतिशत और गैर प्रबंधन क्षेत्र में 70 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को देने हेतु कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर लिया था। लेकिन उद्योग जगत के भारी विरोध होने के कारण सरकार को इसे विधानसभा में लाने की हिम्मत नहीं पड़ी और इसे चौबीस घंटे में ही वापस ले लिया गया। लेकिन आशंका है कि कांग्रेस सरकार इसे किसी दूसरे तरीके से ला सकती है। सरकारी नौकरियों में मोटे वेतन, आरामतलबी तथा रिश्वतखोरी की प्रवृत्तियों के कारण अब अनेक समृद्ध जातियां भी आरक्षण की जिद पर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने लगी हैं। अत: आरक्षण की सीमा बढ़ाने के सारे विचार स्पष्ट रूप से खारिज होने चाहिए।

– **बी.एल. शर्मा,** उज्जैन

पर्यटन के प्रभाव

यात्रा और पर्यटन उद्योग का 2023 में वैश्विक जीडीपी में 9.1 प्रतिशत हिस्सा था। यह योगदान लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार अतिथि सत्कार एक तरह से अमेरिका, स्पेन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका आदि देशों के लिए उद्योग का काम करता है। सरकारें भी पूरा जोर लगाती हैं ताकि पर्यटकों को आकर्षित कर अधिकाधिक लाभ कमाया जाय। मगर आजकल दुनिया के अनेक हिस्सों में इसका विपरीत प्रवृति दिखाई दे रहा है। वहां स्थानीय निवासी बढ़ते पर्यटकों से न सिर्फ ऊब चुके हैं बल्कि उनके कारण उन्हें भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन के मैलोर्का में अति-पर्यटन का विरोध करते हुए पचास हज़ार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह शहर उन लोगों के लिए है जो इसमें रहते हैं। रैली में पर्यटन मॉडल में बदलाव की मांग की गई। पर्यटन के मौजूदा मॉडल ने सार्वजनिक सेवाओं व प्राकृतिक संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया तथा स्थानीय लोगों का किराये पर रहना मुश्किल कर दिया है क्योंकि पर्यटकों से मकान मालिकों को ज्यादा आमदनी होती है। भारत में भी अनेक पर्यटन स्थलों पर स्थानीय निवासियों को संकट तथा पर्यावरण विनाश जैसी हालत है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

इलाज का खर्च

सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एक आंख के लिए लगभग 10,000 रुपये तक खर्च आ सकता है, जबकि निजी अस्पताल में यह 30,000 से 1,40,000 रुपये तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को 14 साल पुराने कानून-क्लिनिकल स्थापना नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर महानगरों, शहरों व कस्बों में इलाज के लिए एक मानक दर तय की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार है और केंद्र सरकार इस आधार पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को मानक दर अधिसूचित करने के लिए राज्यों के अधिकारियों संग बैठक बुलाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक एनजीओ की जनहित याचिका पर दिया। इसमें मांग की गई थी कि न्यायालय लोगों को चिकित्सा के नाम पर की जाने वाली लूट से बचाए। उल्लेखनीय है कि आजकल दवा इलाज का खर्च बहुत लोगों की कमर तोड़ने वाला बन गया है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ निजी अस्पतालों की लूट जारी है। इस पर कठोरता से लगाम लगनी चाहिए।

– **गोपाल सोनी,** धार

शिक्षकों की छवि

स्कूल शिक्षकों के बारे में अनेक सकारात्मक व नकारात्मक खबरें सामने आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कोचिंगों के कारण अनेक शहर मशहूर हो गए हैं। लेकिन हाल ही में वहां के कुछ शिक्षक बच्चों को नकल कराते दिखे। शिक्षा विभाग के सतर्कता दल ने एक गांव में स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला डालकर अंदर शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर सामूहिक रूप से नकल कराते पाया। वैसे छात्रों को गलत ढंग से नंबर देने, या ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों का पक्षपात करने की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, पर शिक्षकों द्वारा सामूहिक नकल कराने की घटनायें विरल हैं। ऐसे शिक्षको की हरकतों से पूरा शिक्षक समाज शर्मिंदा होता है। राजस्थान के साथ ही अन्य प्रदेशों की सरकारों तथा भारत सरकार को स्कूली शिक्षा का स्तर उठाने के प्रयास करने चाहिए। अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के साथ ऐसे भ्रष्ट व अनैतिक शिक्षकों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना भी जरूरी है। स्वयं शिक्षकों को भी अच्छे वेतन के साथ अपनी छवि की चिन्ता भी करनी चाहिए।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

पायनियर
लखनऊ, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

मानक के अनुरूप ही स्कूली वाहन से स्कूल लाए जाएं बच्चे: जिलाधिकारी

● डीएम ने ली जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक

संवाददाता। अमेठी

जिलाधिकारी निशा अनंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने मानक विहीन स्कूली वाहनों के विरुद्ध यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग को अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल प्रबंधक अपने बसों का समय से फिटनेस नहीं करा रहे हैं उन स्कूल बसों के पंजीयन के निलंबन एवं निरस्त करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। सभी विद्यालयों में सड़क यातायात जागरूकता एवं यातायात व्यवस्था हेतु एक नोडल टीचर नामित किए जाने तथा वाहन में बालिका विद्यार्थी होने की दशा में ड्राइवर के अतिरिक्त परिचर के रूप में महिला टीचर/परिचर की उपस्थिति अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि स्कूली वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग से एवं चरित्र सत्यापन का कार्य पुलिस विभाग से अनिवार्य रूप से विद्यालय प्रबंधन पूर्ण कराएं, निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं का परिवहन स्कूली वाहन में कदापि ना किया जाए ऐसा पाए जाने पर उनके विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। स्कूल प्रबंधन प्रत्येक बस का एक रूट चार्ट बनाएं जिसमें बच्चों को बैठाने एवं उतारने का स्थान नियत किया जाए जिसकी जानकारी प्रबंधक द्वारा अनिवार्य रूप से अभिभावक को उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में उपस्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की स्कूल गेट के दोनों और सड़क पर रंबल स्ट्रिप व स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं जिससे कि विद्यालय से निकलने वाले छात्र-छात्राओं को तेज गति से आ रहे वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने सभी अभिभावकों से अपील की कि 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए किसी भी दशा में स्कूटी/बाइक ना प्रदान करें।

सूखी नहर में बाल्टी से पानी डाल कर सपाइयों ने जताया विरोध

अमेठी। मंगलवार को स्थानीय सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिले में सूखी पड़ी नहरों व अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सपाइयों ने भादर ब्लाक के बैधिकपुर मे सूखी नहरों में बाल्टी से पानी डाल कर अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया ह्व मंगलवार को सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अपने समर्थकों के साथ भादर ब्लॉक के बैधिकपुर के पास सूखी पड़ी नहर में जाकर बाल्टी से भर कर पानी छोड़ा। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने कहा कि एक तरफ जहां बरसात नही हों रही है वही जिले में नहरें सूखी पड़ी हुई है इसके साथ अघोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या से किसानों की समस्याएं बढ़ गई है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में सरकार बाजार पेश करके किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है लेकिन जब किसानों की फसल ही नहीं होगी तो आय कैसे दोगुना होगी। अगर जल्द नहरों मे पानी नहीं छोड़ा गया तो हम समाजवादी लोग किसानो के समर्थन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

घर में घुसकर बकरियां व आभूषण ले उड़े चोर

ऊंचाहार, रायबरेली। चार पहिया वाहन से आए चोरों ने एक घर में घुसकर आभूषण और चार बकरियां उठा ले गए है। मामले की जानकारी अगले दिन सुबह हुई है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। मामला ऊंचाहार कस्बे से जुड़े गांव खोजनपुर का है। गांव की महिला फूलकली का कहना है कि वह रात में अपने घर की छत पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे कुछ लोग चार पहिया वाहन से उसके गांव पहुंचे और वाहन को गांव से बाहर खड़ा कर दिया। इसके बाद चोर उसके घर में घुस गए और उसके घर में बंधी चार बकरियां और घर के एक कमरे में रखी संदूक को उठा ले गए। संदूक में महिला और उसकी बहू के सोने चांदी के आभूषण थे। मंगलवार की सुबह जब महिला सोकर उठी तो बकरियों और संदूक को गायब देखकर दंग रह गई। गांव के चोरी की घटना की जानकारी होते ही उसके घर पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बाद में उसके घर से थोड़ी दूरी पर पानी की टंकी के पास उसकी संदूक पड़ी मिली है।

श्रावण मेला व कांवड़ यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक सम्पन्न

श्रावस्ती। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में श्रावण मास में कावड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों द्वारा गाड़ियों के रूट डायवर्जन मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था विशेष कर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले रास्तों की साफ सफाई एवं मार्गों पर खुले में मांस मछली की बिक्री बंद करने बस एवं डीजे की छतों पर कांवरियों को चढ़ने से रोकने कावड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने मंदिर परिसरों के आसपास विशेष साफ सफाई करने जैसी अन्य मांगों से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ण करने हेतु आश्वस्त करते हुए पूरे श्रावण मास के दौरान पड़ने वाले समस्त सोमवार एवं त्योहार पर जिला प्रशासन की तरफ से सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया उन्होंने शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र पर कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सड़कों की साफ सफाई करने के निर्देश पंचायती राज विभाग को दिए। इसके अलावा जर्जर तारों को बदलने एवं अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को दिए गए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने तथा एंबुलेंस सेवा दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान मंदिरों के आसपास एवं मुख्य मार्गों पर विशेष साफ-सफाई के निर्देश दिए गए।

सामाजिक कार्यों में अपनी पहचान रखता है रोटरी क्लबः एडीएम

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी जय प्रकाश ने रोटरी क्लब के सत्र 2024-25 के पदाधिकारियों के पद ग्रहण समारोह में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब आपदा के समय बढ़ चढ़कर मानव सेवा को अपना कर्तव्य समझकर आगे कार्य करता है। वंचितों एवं अभावग्रस्त की सेवा करना वास्तव में बड़ा पुनीत कार्य है। ये सारे कार्य रोटी क्लब स्वत: इकट्ठा किये गये धन संग्रह से करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आये, क्यों कि आज इसने बड़ी आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र रोटरी क्लब का काम सराहनीय है। रक्तदान शिविर आयोजन से आप मानवता की रक्षा के लिए आपका योगदान सराहनीय है। सीएमओ ने सभी से आग्रह किया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में आप कार्य करते रहिए। विशिष्ट अतिथि जोनल सेक्रेटरी रोटेरियन लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने कहा कि रोटरी समाज को जोड़ने का कार्य करता है। आप से आग्रह है कि आप अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर एक पौधा अवश्य लगाये। इसके साथ ही इसकी संरक्षा भी करें।

पांचों युवतियां बरामद न हुईं तो हिन्दू संगठन करेंगे भूख हड़ताल

● हिन्दूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने सीओ को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता। जालौन, उरई

पिछड़े डेढ़ माह में एक सम्प्रदाय विशेष के युवकों द्वारा दूसरे सम्प्रदाय की पांच युवतियों को भगा ले जाने एवं अब तक एक भी युवती की बरामदगी न होने से हिंदू संगठनों के नेताओं ने सीओ को ज्ञापन देकर घोषणा की है कि यदि 26 जुलाई तक युवती की बरामदगी नहीं होती है तो हिंदू संगठनों के सदस्य 27 जुलाई से तहसील परिसर में क्रमिक भूख हड़ताल एवं अनशन करने को विवश होगें।

कोतवाली क्षेत्र में बीते डेढ़ माह में संप्रदाय विशेष के युवक अपने साथ पांच युवतियों को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। नगर व ग्रामीण में संप्रदाय विशेष के युवकों द्वारा दूसरे समुदाय की युवतियों को भगाने के बढ़ रहे मामलों को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं में नाराजगी पनप रही थी। बीती 14 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती की शादी थी। लेकिन शादी से पूर्व ही बीती तीन जुलाई को युवती घर से लापता हो गई। जिसके संबंध में पीड़ित भाई ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 13 जुलाई की रात में युवती के पिता की मृत्यु हो गई।

बढ़ रही घटनाओं को लेकर 15 जुलाई को हिंदू सगठनों के नेता द्वारिकाधीश मंदिर पर एकत्रित हुए और मौन जुलूस निकालकर तहसील परिसर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर युवतियों की बरामदगी की मांग की गई थी। ज्ञापन देने एक सप्ताह के बाद भी पुलिस किसी युवती को बरामद नहीं कर पाई है। इससे संगठन के लोगों में नाराजगी पनप रही है। मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजासिंह सेंगर, गोसंपदा संरक्षण शोध संस्थान के संस्थापक अनिल शिवहरे, मनोज गुप्ता, दिलीप सोनी, बलराम सोनी, हर्षित सोनी आदि ने सीओ रामसिंह को ज्ञापन सोंपकर बताया कि पुलिस इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखा रही है।

भाजपाईयों ने की बजट की सराहना

अयोध्या। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि बजट देश को विकसित करने की अहम कड़ी साबित होगा। यह समाज के हर वर्ग की आकांक्षा को पूरा करेगा। देश की अर्थव्यवस्था को इससे काफी सम्बल मिलेगा। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि यह बजट एक नये विजन के साथ विकास की अवधारणा को सम्बल प्रदान करेगा। सभी वर्गो के उत्थान के साथ गरीबों, किसानों, महिलाओं, वंचितों व युवाओं के सुन्दर भविष्य की रुपरेखा भी तय करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह देश के विकास व समाज के सभी वर्गो के कल्याण का ध्यान सरकार ने बजट में रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को दूर करने व युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के सभी बिन्दुओं पर बजट में फोकस किया गया है। महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि बजट पूरी तरह से लोककल्याणकारी है। जिसमें सर्वांगीण विकास की अवधारणा समाहित है।

बजट ने मध्यम वर्ग को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती की दिखाई उम्मीद

संवाददाता। उरई, जालौन

देश और प्रदेश के बजट से आम आदमी का कितना क्या जीवन प्रभावित होता है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जैसे ही आम बजट को पारित करने की प्रक्रिया शुरू होती है वैसे-वैसे आम और खास सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि इस बार सरकार का उनको लेकर क्या प्लान है वह कौन-कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें आर्थिक तौर पर प्रभावित कर सकती हैं मंगलवार को देश का आम बजट पारित हुआ और विभिन्न टीवी चौनल समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया पर बजट को लेकर आम और खास सभी को जानकारियां हुई। अब आम आदमी का मौजूदा बजट को लेकर क्या कहना है इसे लेकर जब लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली तो एक तस्वीर स्पष्ट होती है कि यह बजट इस बार मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के साथ-साथ आर्थिक मजबूती दिलाने वाला लोग मानकर चल रहे हैं।

बीए प्रथम वर्ष के छात्र सत्यम गुप्ता का कहना है कि देश की सरकार ने रोजगार को अहमियत देते हुए इस बजट में बड़े स्तर पर धन राशि आवंटित करने का जो घोषणा की है उससे बेरोजगार छात्रों को स्वावलंबन की दिशा में काफी मदद मिलेगी मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को बढ़ाया जाना भी छोटे-छोटे व्यवसाईयों के लिए मददगार साबित होंगे।

दुकानदार अभिनव भी इस बजट को लेकर पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह बजट छोटे व्यवसाईयों के लिए काफी सकारात्मक साबित होगा। घरेलू महिलाएं भी इस आम बजट को लेकर कहती है कि उनका वास्ता तो उन सब चीजों से रहता है जो घर के बजट को बनाती और बिगड़ती हैं फिलहाल तो सरकार ने इस बजट में महंगाई को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस बात का पूरा-पूरा प्रयास किया है कि घरेलू उपयोग की वस्तुओं के दामों में कोई बड़ा बदलाव न लाया जा सके श्रीमती सुशीला देवी राधा देवी कहती है कि बजट उनके लिए सकारात्मक ही है शिक्षक दुर्गेंद्र राधा रमन की अपनी राय में इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग की लोगों को रहता ही पहुंचाई है जो की एक अच्छे बजट का प्रतीक है देश की अधिकांश जनता जब आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी तो देश का भी सर्वांगीण विकास होगा कुल मिलाकर शिक्षक वर्ग भी आम बजट से मिली जुली अपनी राय रखता है फिलहाल जो भी हो लेकिन जिस तरह से आम आदमी की बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उनसे तो साफ जाहिर होता है कि यह आम बजट जनता के लिए हितकर ही है।

सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रीना त्रिपाठी ने बजट को नौकरी पेशा कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बेहद निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी कि बजट में पुरानी पेंशन बहाली की बात होगी, 8वें वेतन आयोग की बात होगी, कोरोना काल में जब्त किए गए 18 महीनों के मंहगाई भत्ते की बात होगी, केन्द्र सरकार में लाखों रिक्त पड़े पदों को भरने की बात होगी, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की बात होगी, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की बात होगी किन्तु बजट में इन बातों का उल्लेख भी न होना कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बेहद निराशाजनक है।

सिंचाई विभाग इंजीनियर संघ ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन

उरई, जालौन। मंगलवार को बेतवा नहर सिचाई संघ के जूनियर इंजीनियरों ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर कार्यालय के सामने काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया।

सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरों ने मंगलवार को अधिशाषी अभियंता कार्यालय बेतवा प्रखंड के सामने एकजुट होकर सरकार की विषमताओं को दूर करने और अपनी मांगों को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध काली पट्टी को बांध कर करते हुऐ बताया की हमारे साथ शासन की जो नीति है उसमें हमारी कुछ मांगें हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर के सभी सेवा संबधित प्रकरण की यथा पदोन्नती, स्थाई करण, ज्येष्ठता निर्धारण, पूर्व विभाग की सेवा जोड़ना, विकलांगता दर्ज कराना, चरित्र पंजिका पूर्ण कराना जैसी मांगो को पूर्ण कराने को लेकर विरोध जताया। साथ ही बताया की अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सभी इंजीनियर संघ के लोग सिंचाई मंत्री से लेकर विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय जाकर अनिश्चित कालीन धरना करने पर विवश होंगे।

बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह व बाल श्रम की रोकथाम पर हुई चर्चा

उरई, जालौन। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ अमरेंद्र कुमार पोत्सायन के निर्देश के क्रम में जनपद जालौन के डकोर ब्लॉक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गठित ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बाल विवाह एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया बैठक में ब्लॉक स्तर पर बच्चों के संरक्षण और भागीदारी के अधिकार एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंडे में निर्धारित बिंदुओं यथा बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बाल श्रम, की रोकथाम पर चर्चा की गई।

मिशन वात्सल्य योजना से संरक्षण अधिकारी जूली खातून के द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी गणों को महिला कल्याण विभाग के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओं जैसे पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप आदि के संबंध में जानकारी प्रदान कर ग्राम स्तर पर गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराकर गांव समुदाय में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को चिन्हित कराया जाने का अनुरोध किया गया। जिससे उनको उक्त कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।

बैठक में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी से कक्षा 5 कक्षा 8 के बाद ड्राफ्ट आउट हो रही बालिकाओं को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में प्रवेश कराए जाने तथा स्कूलों में बाल विवाह, गुड टच बेड टच के संबंध में बच्चों को जागरुक कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरांत अध्यक्ष के द्वारा सभी अधिकारी गणों से बाल हित के दृष्टिगत अपने क्षेत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश देकर बैठक का समापन किया गया।

आर्य कन्या कालेज में शिक्षण कार्य ताक पर, गिद्ध दृष्टि 70 लाख पर

● आर्य कन्या प्रबंध समिति विवाद में आया नया मोड़

● जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्यशैली संदेह के घेरे में

संवाददाता। कालपी, जालौन

आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर तथा कथित प्रबंध समिति को कार्य करने का अवसर देकर के शिक्षा अधिनियम तथा भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी के साथ इंटर कालेज में बर्चस्व को लेकर चल रहा विवाद नये मोड़ पर पहुंच गया है। सूत्रों की मानें तो कालेज में चल रहे विवाद के पीछे कालेज फंड में लगभग 60 से 70 लाख रुपये हैं उसी को लेकर विवाद दर विवाद चला आ रहा है।

आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी के पूर्व प्रबंधक नरेंद्र कुमार तिवारी ने संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद जालौन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर मनमानी पूर्ण ढंग से बिना वैधानिक ढंग से किए गए निर्वाचन के केवल प्रबंधक को मान्यता देकर के माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि तथा कथित प्रबंध समिति का चुनाव जून 2022 में फर्जी ढंग से कराया गया था इस चुनाव में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए जिला विधायक निरीक्षक जनपद जालौन ने चार-पांच बार संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी को पत्र लिखकर अवगत कराया की श्रीमती प्रीति जेटली द्वारा गठित प्रबंध समिति शिक्षा विभाग के नियमों के तथा प्रशासन योजना की विपरीत है। ऐसी स्थिति में आप मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए लगभग डेढ़ 2 साल के बाद अचानक संयुक्त शिक्षा निदेशक ने एक पत्र के जरिए जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेशित कर दिया की श्रीमती प्रीति जेटली को प्रबंधक मानते हुए उनके हस्ताक्षर प्रमाणित करें संयुक्त शिक्षा निदेशक केशिक्षा अधिनियम के विपरीत दिए गए आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री नरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा रिट संख्या 17 852 दायर करके फर्जी ढंग से कराए गए निर्वाचन तथा फर्जी ढंग से दी गई मान्यता को तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया गया कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है।

पूर्व प्रबंधक नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया की 2007 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मेरिट पर जिसका नंबर 33592 है में स्पष्ट आर्डर किया है कि जब तक न्यायालय यह तय न कर दे कि निर्वाचन कौन कराएगा तब तक सभी पक्षों को निर्वाचन की कार्रवाई से रोका जाता है यह आदेश आज भी प्रभावी है लेकिन शिक्षा विभाग को मेरी तरफ से भी लिखित रूप में सूचित करने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी में कोई बड़ा लाभ लेकर फर्जी ढंग से गठित प्रबंध समिति को मान्यता देने का दुरुपयोग किया है।

आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी में लगभग 15 लाख के वितीय घोटाले की जांच भी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा करने के उपरांत वर्तमान प्रबंधक के स्वर्गीयपति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा विद्यालय में कंट्रोलर नियुक्त करने की जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद जालौन में शासन को अनुशंसा भी कर रखी है इन सब के बाबजूद भी शिक्षा विभाग आंखें बंद करके इस प्रबंध समिति को कार्य करने के लिए अधिकृत कर रही है यह बड़ी ही विडंबना है।

जब कोई प्रबंध समिति ही नहीं है प्रबंधिका के अलावा अन्य कोई सदस्य डीआईओएस की तरफ से अधिकृत नहीं है इसके बावजूद नियमों को तक पर रखकर तानाशाही अपना कर विद्यालय की प्रधानाचार्य को निलंबन करके विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने तथा विद्यालय में जमा 60-70 लाख रुपया के धन को खत्म करने के चक्कर में यह कार्रवाई की गई है। कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज कालपी प्रधानाचार्य नुजहत जहां की देखरेख में उत्तम शिक्षा उत्तम व्यवस्था के साथ विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य चल रहा था लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग करने के चक्कर में चल रही सुंदर व्यवस्था को चौपट करने का तथा कथित प्रबंध समिति ने कार्य किया है जो निंदनीय है।

क्विक न्यूज

अलग-अलग घटनाओं में 7 बालिकाओं की मौत

संतकबीरनगर, सेमरियांवा, मेंहदावल। बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़गो निवासी अर्चना पुत्री रामनिवास, पायल पुत्री दिलीप, मीनाक्षी पुत्री मकसूदन और काजल पुत्री रमेश यह चारो सहेली थी, जो अक्सर बकरा झील के किनारे टहलने के लिए जाती थी, मंगलवार को गर्मी के चलते एक साथ घर से निकली चारो बच्चियां बखिरा झील में डूबने लगी, वहां आसपास कुछ लोगों ने देखा तो दौड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फएक को ही बचाने में सफल हो पाएं, जबकि तीन बच्चियों की मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी क्रम में खटियावां गांव निवासी उर्मिला 18 वर्ष व प्रमिला 15 वर्ष पुत्री राजेन्द्र कुमार गांव के पश्चिम दिशा में बड़ी बहन सुशीला के साथ धान की रोपाई करने गयी थी। खेत के बगल में बने गड्ढे और खेत का लेवल एक बराबर होने की वजह से रोपाई के दौरान उर्मिला का पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गयी जहां बड़ी बहन और उर्मिला को बचाने के लिए प्रमिला ने कोशिश की इस दौरान उसका भी पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गई इसकी सूचना बड़ी बहन सुशीला ने ग्रामीणों को दी मौके पर सैकड़ो की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गड्ढे में कूद कर दोनों बहनों की छानबीन करने लगे सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची जहां स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत के बाद उर्मिला को ढूंढ निकाला आनन-फानन में उसे सीएचसी सेमरियावां भेजा गया जांच चिकित्सको ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। फिर लगभग एक घंटे कड़ी मशक्कत के बाद जाल लगाकर छोटी बहन प्रमिला को निकाला गया और तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत्यु घोषित कर दिया। इसी क्रम में मेंहदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मैला में दो बहनों की सेब खाने के बाद तबियत अचानक बिगड़ गई। जिसमें छोटी बहन की मौत हो गई। जबकि बड़ी बहन का इलाज बीआरडी गोरखपुर चल रहा है।

भारतीय मजदूर संघ का 70 वां स्थापना दिवस मना

लालगंज, रायबरेली। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में भारतीय मजदूर संघ का 70 वा स्थापना दिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया गया। एमसीएफ मजदूर संघ के अध्यक्ष आदर्श सिंह बघेल ने बताया कि बीएमएस की स्थापना मात्र 15 श्रमिक बंधुओं को लेकर हुई थी लेकिन आज यह अब भारत ही नही विश्व का सबसे बड़ा मज़दूर संगठन बनकर संगठित व असंगठित मज़दूरो के हितों के लिये अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रेलकोच मज़दूर संघ के महामंत्री सुशील गुप्ता ने बताया कि बीएमएस की स्थापना श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 23 जुलाई 1955 को भोपाल में की थी। उन्होंने बताया कि बीएमएस ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो अपने स्थापना काल से लेकर आज तक 69 साल का कार्यकाल निर्विवाद अबाध गति से विकास करते हुए देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन बन कर भारत के श्रमिको का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर आईएलओ जेनेवा में भी कर रहा है।

पशुपालक की बीस हजार कीमत की बकरियां चोरी

लालगंज, रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र में बकरी चोरों का आतंक प्राप्त है। आए दिन बकरी चोर रात के अंधेरे में बकरियां कारों में भर ले जाते हैं। जिससे क्षेत्र के पशुपालकों में दहशत व्याप्त है। सोमवार की रात को अंबारा पश्चिम गांव निवासी राममनोहर पाल की दो बकरियां चोरी हो गई। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि रोज की तरह उसकी बकरियां दरवाजे बंधी थी। रात करीब दो बजे अज्ञात चोर दोनों बकरियां उठा कर ले गए। पीड़ित ने बताया उसका करीब बीस हजार रुपए का नुकसान हो गया। इससे पहले शनिवार की रात को भी कार सवार चोरों ने ओरी का पुरवा मजरे महाखेड़ा गांव में गोमती देवी की छः बकरियां कार में भरकर फरार हो गए। इस दौरान महिला ने उनमें से एक को दबोचने का प्रयास किया। लेकिन बदमाश उसके साथ हाथापाई कर भागने में सफल रहा। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। संभव है कि कोई गिरोह सक्रिय हो। क्षेत्र में पुलिस गस्त को और सघन किया जाएगा।

आर्थिक तंगी के चलते फंदे पर झूला मजदूर

नसीराबाद, रायबरेली। थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर एक मोहल्ला मौहरिया (लाला की बाजार) निवासी राजू 50 वर्ष का घर से लगभग पांच सौ मीटर महुआ के पेड़ की डाल में गमछे से फंदे से शव लटकता मिलने से समूचे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस फांसी का कारण आर्थिक तंगी बता रही हैं। मंगलवार को सुबह लगभग साढ़े छह बजे राजू घर से बोतल में पानी लेकर शौच के लिए निकला था।काफी देर बाद जब वह घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पास पड़ोस और नाते रिश्तेदारों के यहां भी पता लगाया पर कहीं भी कुछ पता नहीं चला। शाम को लगभग पांच बजे राजू का भाई राकेश ने देखा तो महुआ के पेड़ की डाल में राजू का शव लटकता दिखाई दिया।

सदर विधायक ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा

रायबरेली। सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक अदिति सिंह ने विधुत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर क्षेत्र में लो - वोल्टेज एवं अघोषित बिजली कटौती और नहरों में पानी की कमी से किसानों को आ रही समस्याओं के अतिशीघ्र समाधान कराने का कड़ा निर्देश दिया। बताते चलें कि वर्तमान समय में धान की रोपाई पूरे जोर - शोर से चल रही है और बारिश न होने की वजह से किसानों को खेतों में पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है लो - वोल्टेज और अघोषित कटौती एवं नहरों में पानी की कमी से उनकी समस्याऐं और अधिक जटिल हो गयी है। बैठक के दौरान अदिति सिंह ने उपस्थित बिजली विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग से कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए एक सप्ताह के अन्दर किसानों को अधिक से अधिक बिजली आपूर्ति एवं नहरों में पानी उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया।

व्यापारियों व ग्रामीणों ने पावर हाउस का किया घेराव

सलोन, रायबरेली। बिजली कटौती से नाराज सूची कस्बे के व्यापारियों व ग्रामीणों ने सवर्ण आर्मी के जिला महासचिव-योगेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में सूची पावर हाउस का घेराव कर पिछले एक माह से सूची कस्बे की विदियुत सप्लाई पूरी -पूरी रात गायब रहने पर विरोध प्रदर्शित करते हुए धरना दिया। जेई द्वारा फोन पर वार्ता कर जल्द ही समस्या का निराकरण कराया जाने का आश्वासन दिये जाने के पश्चात पावर हाउस इंचार्ज को ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौपकर धरना समाप्त किया।

विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन

मुसाफिरखाना, अमेठी । कांग्रेसियों ने तहसील मुख्यालय पहुंच कर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा की अगुवाई मे तहसीलदार राहुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि क्षेत्र के नहर में पानी न आने और विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण जन जीवन बेहाल हो गया है और गरीब किसानों को खेती किसानी करने में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी व बरसात का मौसम होने के कारण बिजली के आपूर्ति न होने से आए दिन समस्या बनी रहती है। वही क्षेत्र मे छुट्टा जानवरो कि उचित व्यवस्था कराई जाए जिससे किसान अपनी फसलों को बचा सके।

ऐतिहासिक तरीके से मनेगा राजीव गांधी का जन्मदिन

अमेठी। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय गौरीगंज में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अमेठी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले अमेठी के जन जन में बसे राजीव गांधी जी का 20 अगस्त को 80 वां जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ऐतिहासिक रूप से मनाने की तैयारी बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने सभी 17 ब्लॉक अध्यक्ष विधानसभा प्रभारी एवं कार्यक्रम आयोजकों के साथ बैठक कर वृहद चर्चा की एवं अमेठी के छात्रों, किसानों नौजवानों, महिलाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन की रूप रेखा तैयार की गई।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में की बैठक

● मुख्यमंत्री संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल व समाधान दिवस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयावधि में हो संतुष्टिपरक, गुणवत्तापूर्ण निस्तारणः जिलाधिकारी

डीएम कलेक्ट्रेट सभागार में पोर्टल पर प्राप्त शिकायातें के निस्तारण की समीक्षा करते हुये

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने संबंधित विभागों से आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भोंए निस्तारण की स्थिति, डिफाल्टर सन्दर्भ की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मुख्यमंत्री सन्दर्भ, सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस पोर्टल व समाधान दिवस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में संतुष्टिपरक, गुणवत्तापूर्ण रूप में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सन्दर्भित प्रकरणों के निस्तारण के लिए आवंटित समयावधि से आधे समय में सन्दर्भों का निस्तारण कराया जाये, जिससे कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच एवं पुनः जांच कराये जाने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री संदर्भ से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सात दिन व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सन्दर्भों का निस्तारण 15 दिन के भीतर किया जाये।

इसके अतिरिक्त डीएम ने सभी अधिकारियों को सीयूजी नम्बर उठाने व उस पर आने वाली शिकायतों का संवेदनशील होकर निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये। आईजीआरएस पोर्टल से संबंधित शिकायतें अथवा सीयूजी नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में यदि शिथिलता पायी जाती हैए तो सम्बन्धित अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। सीडीओ लक्ष्मी एन.ए एडीएम प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमित राठौर, परियोजना निदेशक वीरेंद्र कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी सुबोध कुमार, उपनिदेशक कृषि रामबचन राम, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, खाद्य एवं विपणन अधिकारी, उपयुक्त उद्योग, ईडीएम आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला ने फांसी लगाकर जान दी

मौदहा (हमीरपुर)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपसा में नव विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगा आत्महत्या कर ली। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की है। कपसा के मदाइन पुरवा निवासी धीरज सिंह की गर्भवती पत्नी सरोज (23) ने घर में कमरे के अंदर फंदा आत्महत्या कर ली। मृतक सरोज के ससुर चंद्रपाल सिंह ने बताया कि मेरे तीन पुत्र व दो पुत्री है जिसमे दोनों पुत्रियों की शादी कर दी है स वही मेरे दो पुत्र सूरत में रहते है व धीरज कानपुर में प्राइवेट कम्पनी में काम करता है और वही रहता है धीरज की शादी दो वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हरडोनी गाँव में बलराम सिंह की पुत्री के साथ हुआ था शादी बाद दोनों पति पत्नी कानपुर में ही रहने लगे हम कपसा में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे बहू सरोज गर्भवती थीं इस कारण धीरज ने दो माह पूर्व गाँव छोड़ गया था, किस कारण बहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया वह खुद नही समझ पा रहा है।

सड़क सुरक्षा के नियमों का अधिकारी कराए पालनः एडीएम

● अपर जिलाधिकारी ने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, दिए निर्देश

●एडीएम ने स्कूल वाहन के वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन, लाइसेंस की जांच कराये जाने के दिये निर्देश

एडीएम प्रशासन अमित कुमार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश देते हुये

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि एनएच पर अनधिकृत कट को बंद करने की कार्यवाही व रनियां में सर्विस रोड़ से विद्युत पोल हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही हैए जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी ने कराए जा रहे कार्यों की फेटोग्राफलोकेशन सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अपर जिलाधिकारी ने एनएचएआई के पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। ओवर स्पीडिंग रोकनेए स्वचालित चालान व्यवस्था लगाने, रोड पर रंबल स्ट्रिप बनाने, साइनेज बोर्ड आदि लगाने के निर्देश दिए। संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर ट्रैफिक नियमों का पालन कराएए जो ट्रैफिक नियमों का पालन नही कर रहे हैं उन पर प्रभावी कार्यवाही करें। नबीपुर में अण्डर पास बनाये जाने के संबंध में एडीएम को एनएचआई के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैए शीघ्र ही अण्डरपास का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 548 स्कूल वाहन पंजीकृत हैए जिसमें से 150 वाहनों का फिटनेस वर्तमान में फेल हैए इसमें से 42 के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 8 से 22 जुलाई के मध्य स्कूली वाहनों की सघन जांच की गयीए जिसमें 55 वाहन मानक के अनुरूप न पाये जाने पर सीजर की कार्यवाही की गयी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को सुनायी उम्रकैद व जुर्माना

हमीरपुर। मुस्करा थाना के एक गांव निवासी नाबालिग वर्ष 2015 में घर से सोते समय अचानक लापता हो जाने के मामले में पीड़ित मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद घर पहुंची नाबालिग ने उसके साथ गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित को दोषी मानते हुए उम्रकैद सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि थाना मुस्करा के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की की मां ने मुस्करा थाने में तहरीर दी थी कि 16 मई 2015 की रात 12 बजे घर में सोते समय उसकी पुत्री अचानक कहीं लापता हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नही मिली। जिस पर गांव निवासी सुरेश द्वारा बेटी को फोन किए जाने की बात पर उसने सुरेश के खिलाफ बेटी को बहला कर ले जाने समेत एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। वहीं बेटी की बरामदगी के बाद जब पुलिस ने कोर्ट में 164 के बयान कराएं तो उसमें बेटी ने सुरेश द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। जिस पर कोर्ट में हुए बयान के आधार पर आरोपित सुरेश के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पाक्सो एक्ट की धारा और बढ़ गई। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित सुरेश को दोषी मानते हुए एससी एसटी मामले में आजीवन कारावास सुनाया है। इसके साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सीआरपी और समिति पदाधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

फतेहपुर। ब्लाक इंडिया द्वारा संचालित अश्वकल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड तेलियानी में समिति पदाधिकारी और सीआरपी का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें परियोजना के अलग-अलग ब्लॉक से समिति के पदाधिकारी और सदस्य, सीआरपी आदि ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत विकास खंड अधिकारी राहुल द्वारा की गई, जिन्होंने विकासखंड स्तर पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, समूह केडर निर्माण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जीवन ज्योति अश्वकल्याण समिति द्वारा किए गए अश्वकल्याण कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में श्रम विभाग से अधिकारी इजहार अहमद उपस्थित रहे। सभी को लेबर कार्ड की योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से समझाया और लेबर कार्ड की योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में समझाया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जिला मिशन मैनेजर रणजीत सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने एनआरएलएम द्वारा चलने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं को विस्तृत समिति और सीआरपी को समझाया और समिति को मजबूत करने हेतु क्लस्टर स्तर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके अलग-अलग प्रोजेक्ट को काम करने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एडीओ एग्रीकल्चर दिनेश उपस्थित रहे, जिन्होंने कृषि विभाग और होर्टीकल्चर विभाग की योजनाएं जो समूह और समिति के लिए चलाई जा रही है, उनकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि ग्रामीण स्तर पर विकासखंड से समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वयन हो रही है, जिसमे समिति और समूह लाभ ले सकते है। मैनेजर शिवम साहू ने ब्रुक इंडिया के उद्देश्यों, अश्वकल्याण संबंधी मुद्दों पर समझाया गया। इस कार्यक्रम में बृजेश कुमार, उषा अवस्थी, मानसिंह तथा समिति से पदाधिकारी और सीआरपी रीता, सुनैना, पिंकी, पुष्पा, कमला सुनैना, मो. रफी, मो. अनीस, विनोद, संतोष, राजाराम, नीतू उपस्थित रहे।

अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम ने ली बैठक

फतेहपुर। लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित होने वाली राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन हेतु विद्यालय व संस्थान को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम सी. इन्दुमती की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। शासन की मंशानुरूप राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय जो आयोग के दिशा निर्देशानुसार सभी मानकों को पूरा करते हो और जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र बनाए जा रहे है, कि एलआईयू रिपोर्ट प्राप्त कर ले साथ ही विद्यालय के प्राचार्य/ प्रधानाचार्यों से सहमति पत्र अवश्य ले लिया जाये। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र बनाए जाने की कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अविनाश त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्रा, एसडीएम सदर, एएसडीओ, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्नीक, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे।

क्विक न्यूज

जमीनी विवाद में दो पक्ष भिड़े, कई जख्मी

फतेहपुर, खागा। नगर के जोकीपर मुहल्ले में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जिसमे कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफपुलिस को लिखित तहरीर देकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने व लाइसेंसी असलहों से फायरिंग कर दहशत फैलाने समेत जानमाल की धमकी देने की तहरीर दी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। नगर पंचायत क्षेत्र के जोकीपर मुहल्ले निवासी पीड़ित अश्वनी मौर्य पुत्र लाला उर्फरामेश्वर मौर्य सोमवार की रात अपने खेत में पानी लगाए था। तभी पारिवार के राजकुमार, अरविंद पुत्रगण देशराज, शिवम पुत्र रविशंकर, अंकित पुत्र राजकुमार व लल्लू पुत्र अरविंद ने एकराय होकर खेत की बल्लियों व तार को हटाना शुरू कर दिया। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने अश्वनी को लाठी डंडो व लाइसेंसी असलहों से पीटना शुरू कर दिया। चीखपुकार सुनकर पीड़ित के बीच बचाव के लिए दौड़े आरोपी मौके से फरार हो गये। मारपीट के दौरान दोनों पक्षो से कई लोग चोटहिल हो गये। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित अश्वनी ने आरोपियों के खिलाफनामजद तहरीर दी है।

फांसी पर लटकी मिली महिला, हत्या का आरोप

फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र के ग्राम बरौरा में मंगलवार की सुबह 23 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी लगा ली। जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार बरौरा गांव निवासी अखिलेश कुमार की पत्नी प्रियंका ने मंगलवार की सुबह संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर फांसी लगा लिया। परिजनों की नजर पड़ी तो तत्काल उसे फंदे से छुड़ा सरकारी एंबुलेंस से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाए। जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर आए पति अखिलेश ने बताया कि पंद्रह दिनों से उसकी पत्नी बीमार चल रही थी। दवा खाने के लिए कहा तो मना कर दिया जिस पर उसे डांट-डपट दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता उमाशंकर निवासी मुतौर थाना लल्लौली ने बताया कि उसकी पुत्री ने फांसी नहीं बल्कि ससुरालीजनों ने हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया है।

करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

फतेहपुर। ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा बहुआ में सोमवार की रात करंट की चपेट में आ जाने से लगभग 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को विच्छेदन के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार गागीपुर थाना क्षेत्र के लिलरा गांव निवासी रामस्वरूप का पुत्र विनय कुमार साथी अतुल के साथ बहुआ कस्बा एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। तभी अर्द्धरात्रि करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सालय के मार्च्युरी हाउस में मृतक के परिजनों ने बताया कि बहुआ में कथा का कार्यक्रम हो रहा था। जिस पर मृतक आर्गेन बजाता था। स्टेज के पास लगे टेंट के पोल में उतर रहे करंट की चपेट में आ गया। इसी बीच बगल में खड़े व्यक्ति ने उसे प्लास्टिक की कुर्सी से धक्का दिया तो नहर में गिर गया। साथ में गए अतुल ने नहर में कूदकर उसे बाहर निकाला और सदर अस्पताल लाए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

गंगा में डूबे किशोर का शव बरामद

फतेहपुर। कानपुर नगर के थाना पनकी मुहल्ला गंगागंज निवासी महेंद्र सिंह भदौरिया का पुत्र नैतिक अपने मामा अनिल सिंह निवासी तेलियानी के यहां आया था। बताते हैं कि सोमवार की सुबह दस बजे वह मामा के परिवार सहित स्नान करने के लिए गया था। तभी वह गंगा में डूब गया। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस टीम व गोताखोर किशोर को खोजने के लिए जुट गए लेकिन कोई सुराग न मिला। मंगलवार की शाम किशोर का शव सुखरूपुर घाट से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।

फर्जी फंसाने का लगाया आरोप

राठ (हमीरपुर)। कोतवाली के बिलरखा गांव निवासी रोहित कुमार पुत्र कढ़ोरी लाल ने बताया कि गांव के कालीचरन पुत्र शिवनाथ व उसकी पत्नी रचना ने पुत्री को नाबालिग दिखाते हुए उसके ऊपर छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज कराया था। जिसमें वह जेल भी गया था। उस समय कालीचरन ने अपनी नाबालिग पुत्री की शादी 11 मई 23 को औड़ेरा गांव निवासी सुरेंद्र पुत्र शिवनाथ के साथ नरसिंह मंदिर कछवां की पहाड़ियां से हिंदू रीति.रिवाज के साथ संपन्न कराई थी। जो कानूनन अपराध है। पीड़ित ने उसे फर्जी फंसाने पर उक्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

उप चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 4 पदों पर पांच नामांकन

फर्रुखाबाद। राजेपुर विकास खंड क्षेत्र के तीन ग्राम पंचायतों में चार ग्राम पंचायत पदों के लिए 5 नामांकन दाखिल किये गये स एक सदस्य निर्धारित समय से 12 मिनट लेट आने के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं हो सका स ग्राम पंचायत रतनपुर पमारान के बार्ड संख्या चार अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित सरस्वती पत्नी राजेश ने नामांकन पत्र दाखिल किया, ग्राम पंचायत सबासी के वार्ड संख्या 6 से ओबीसी महिला हेतु आरक्षित शिल्पी देवी पत्नी प्रदीप कुमार ने तथा भाग संख्या 10 से अनारक्षित लज्जाराम पुत्र नत्थू ने पर्चा भरा सजबकि ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर बार्ड संख्या पांच अनारक्षित में सुभद्रा पत्नी हरदेव सिंह, तथा मीना सिंह पत्नी अमर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि इसी वार्ड में 4रू12 बजे पर पर्चा जमा करने आयी मीना देवी पत्नी देवेंद्र कुमार का समय समाप्त होने के बाद पर्चा जमा नहीं हो सकास सहायक निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया

परिवहन ज्वाइंट टीम को रोडवेज बस में मिले 14 बिना टिकिट यात्री

● परिचालक पर गिरी गाज, दर्ज हुई एफआईआर

निरीक्षण करती टीम

सुमेरपुर (हमीरपुर)। प्रवर्तन दल ने बीती रात इंगोहटा के पास बिना टिकट यात्रियों को लेकर महोबा से लखनऊ के लिए जा रही परिवहन निगम की बस को पकड़ा। प्रवर्तन दल के बीच रास्ते में बस को रुकवाने पर कंडक्टर ने जल्दबाजी में टिकट मशीन से टिकट निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक टीम ने उसे दबोच लिया। यात्रियों से पूछताछ की गयी तो बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री मिले जो कंडक्टर को किराये के पैसे दे चुके थे। प्रवर्तन दल ने बस को हमीरपुर डिपो में खड़ा कराकर टिकट मशीन सहित बैग को डिपो में जमा कराया है। हमीरपुर प्रवर्तन दल द्वारा महोबा डिपो की बस पर मौदहा सुमेरपुर के मध्य इंगोहटा में औचक निरीक्षण किया गया था। टीम ने मशीन और बैग को अपने कब्जे में लेते हुए जब यात्रियों से टिकट माँगा तो 14 यात्रियों के पास टिकट नहीं मिला जो कंडक्टर को पैसे दे चुके थे। चेकिंग टीम ने फिलहाल बस को हमीरपुर डिपो में खड़ा कराकर बैग सहित मशीन को डिपो में जमा कराया है। टीम के सदस्य सत्येन्द्र सिंह सहायक यातायात निरीक्षक ने बताया कि महोबा डिपो की बस में 14 यात्री बिना टिकट मिले थे। 14 यात्रियों के किराए का दस गुना कंडक्टर से वसूला जाएगा। फिलहाल बस को डिपो में खड़ा करा लिया गया है। बैग और टिकट मशीन को डिपो में जमा कराया गया। डिपो के एआरएम राम प्रताप साहू ने बताया कि महोबा डिपो के कंडक्टर लक्ष्मण दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी है।

आमबजट में मध्यवर्गीय, युवाओं, महिलाओं पर विशेष फोकसः मुकेश गुप्ता

फर्रुखाबाद। स्टेट बैंक अधिकारी एवम् अर्थशास्त्री मुकेश गुप्ता ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश देश के आम बजट 2024-25 में इस बार मध्यम वर्गीय लोगों को काफी फायदा होते दिखाई पड़ रहा है । इस बार के बजट में आयकर के नए टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने के साथ-साथ 3 लाख से 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को टैक्स रेट के बदलाव के कारण लगभग 17500 रुपयो तक की बचत होगी । इस प्रकार जब मध्यम वर्गीय लोगों की बचत होगी तो उनकी बचत में वृद्धि होगी जिसके साथ-साथ उनकी पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ने से वह बाजार में उपलब्ध उत्पादों की ज्यादा खरीद करेंगे इस प्रकार माल की ज्यादा खपत होने के कारण कारखानो को अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। अंततः देश में औद्योगिक विकास होगा।

अपराध और अपराधियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर

मोहम्मदी खीरी। चन्द्र शेखर सिह की जगह आऐ नवागंतुक प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह मीडिया से हुए रूबरू एपहली प्रेस वार्ता मे उन्होंने बताया कि मैं मूल रूप से फ्तेहपुर हसवा का रहने वाला हूं, 2001 में सब इंस्पेक्टर के रूप में मेरी भर्ती हुईए 2016 में इंस्पेक्टर बन इंस्पेक्टर के रूप में जनपद इटावा, बलरामपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, आगरा और जनपद लखीमपुर खीरी के पसगवां, गोला एभीरा के बाद मोहम्मदी कोतवाली का दायित्व मिला, प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हमारी प्राथमिकताएं जो फरियादी कोतवाली आऐ उसकी समस्या को सुनना और उसका निराकरण कराना रहेगाए वही अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करना, महिलाओं पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगानाए यातायात को और सुधार करना जिससे दुर्घटना में कमी आए, कावड़ यात्रा के संबंध में उन्होंने बताया यह माह सावन का महीना है जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त गोला गोकर्णनाथ शिव के मंदिर पर कावड़ यात्रा के रूप में जाते हैं जिसमें उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगह.जगह पर पुलिस पिकेटए खाने पीने सहित स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है एवही उनकी सुरक्षा का पूरा खयाल रखा जाऐगाएतथा किसी भी कावड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त को किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना नही करना पड़ेगा, इसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे जो बंद है पुलिस प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों से वार्ता कर इसको चालू कराया जाएगा। वहीं सामाजिक अपराध गौकशीए सट्टा एस्मैक जैसे सामाजिक अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगाए वहीं उन्होंने मीडिया से सकारात्मक रूप से सहयोग की अपेक्षा की है।

मण्डलीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न

बाँदा। आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों को तेज गति के साथ गुणवत्तायुक्त तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने मासिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य में तेजी लाते हुए सम्पादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय से कार्यालय में उपस्थित रहने तथा अधिकारियों को जन समस्याओं को प्राथमिकता पर गम्भीरता से लेते हुए गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सड़कों का निर्माण एवं सड़कों की मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ किये जाने तथा निर्माण की गयी सड़कों की सूची भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने सेतुओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के साथ

निर्माणाधीन पुलों के सभी कार्य एप्रोच रोड सहित पूर्ण किये जायें। उहोंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारियों को अवशेष अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा कराये जाने के निर्देश दिये तथा जिन लाभार्थियों द्वारा अभी तक आवास पूर्ण नही किये गये हैंए उनसे संम्पर्क कर शीर्घ्र पूर्ण करायें।

बैठक में जल निगम के अधिशाषी अभियंता एवं नेडा के मण्डलीय अधिकारी के उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मण्डल के जनपदों की जीडीपी को बढाये जाने के सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा दिये गये प्रजेन्टेशन के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

उन्होंने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए लाइनलास को कम किये जाने तथा खराब ट्रान्सफार्मर को समय से बदलने एवं विद्युत बिलों में समय से बिलों का सुधार कराये जाने एवं सभी अधिकारियों को नियमित रूप से टेलिफोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिये। जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना के अन्तर्गत जिन गाँवों में कनेक्शन दिये गये हैंए वहां पर जलापूर्ति समय के अनुसार कराये जाने तथा जल निगम द्वारा टूटी सड़कों को मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने बाढ प्रभावित ग्रामों को चिन्हित करते हुए बाढ चैकी की स्थापनाए बाढ से बचाव हेतु समस्त तैयारी किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर न घूमने पायें, उन्हें गौशालाओं में सुरक्षित रखने के साथ उनके चारे, पेयजल, छाया आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाए। जिन किसानों के द्वारा सहभागिता योजना के अन्तर्गत गायों को दिये जाने तथा लभार्थियों का भुगतान समय से कराया जाए। उन्होंने वृक्षारोपण में रोपित किये गये विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों की जीओ टैगिंग कराये जाने तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उपाय किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जल संरक्षण हेतु मेडबन्दीएखेत.तालाब के अन्तर्गत जल संरक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें कराये जाने की निर्देश दिए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने वाले कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश अपर निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग को दिए।

टीम ने उर्वरक दुकान व गोदाम का किया निरीक्षण

फतेहपुर। जिला कृषि अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कि विकास खंड हसवा के ग्राम थरियांव स्थित राजकुमार पुत्र बनवारी लाल के उर्वरक दुकान व गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इफ्को की नकली व मिलावटी प्रतीत हो रही खुली 65 बोरियां, आईपीएल डीएपी की 700 बोरी, जिप्सम की 45 बोरी, किसान बेन्टोनाइट सल्फर की 02 बोरी, जिंक 25 पैकेट, भारत एनपीके 20-20-00-13 की 200 बोरी तथा खैतान एसएसपी की 20 बोरी बरामद हुई जिसका संबंधित के पास कोई अभिलेख नहीं पाया गया। संदिग्ध उर्वरकों के नमूने ग्रहीत कर विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं व संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही भी की जा रही है। डीएम ने निर्देशित किया कि किसी भी दशा में जनपद के कृषकों को नकली व मिलावटी खाद वितरित नहीं की जानी चाहिए, प्रत्येक दशा में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक प्राप्त कराये जाने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।

सीडीओ ने की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश

संवाददाता। लखीमपुर खीरी

सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित माह जून 2024 की प्रगति आख्या के आधार पर कम रैंक प्राप्त कार्यक्रमों की सीडीओ अभिषेक कुमार ने सोमवार शाम को विकास भवन सभागार में समीक्षा की संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को महीने की अंतिम तिथि तक शत.प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। कोई भी आवेदन समय सीमा के बाद लंबित ना रहे। फसल बीमा योजना में किसानों के फसल नुकसान के दावों को समय के अंदर भुगतान कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त स्वत: रोजगार द्वारा सभी ठडड को लक्ष्य निर्धारित कर उनके कार्यों साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के शत.प्रतिशत बैंक खाते खुलवाकर उन्हें सशक्त, क्रियाशील बनाने के लिए निर्देशित किया।

सीडीओ ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की स्थिति के बेहतर करते हुए रैंकिंग में उज्वल से उत्कृष्ट तक लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देशित किया। गांव को उज्वल से उत्कृष्ट में लाकर मॉडल बनाए। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित निरीक्षण करनेए विद्यालयों में कालाकल्प के पैरामीटर शत.प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। ओडीओपी योजना के अन्तर्गत एजेन्सी न चुने जाने पर रोष जताते हुए एजेन्सी का जल्द से जल्द चुनकर इसके लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देशित किया। सभी विभाग माह जुलाई की ऑनलाइन प्रगति 30 जुलाई तक डीएसटीओ को उपलब्ध कराएं। बैठक में डीडीओ, उपायुक्त स्वत: रोजगार, डीएसटीओ, डीपीआरओ के अलावा अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारी उपस्थित हुए।

पायनियर
लखनऊ, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

● शोध, टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन देगी सरकार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अनुसंधान, टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाने और कृषि परिदृश्य में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान ढांचे की गहन समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा करेगी। शोध निधि चुनौती-आधारित होगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुली होगी, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञ शोध के संचालन की देखरेख करेंगे। सीतारमण ने घोषणा की कि किसानों की जल्द ही 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज वाली, जलवायु-सहिष्णु किस्मों तक पहुंच होगी।

महत्वपूर्ण फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, मंत्री ने दलहन और तिलहन पर केंद्रित मिशन की योजनाओं का खुलासा किया, जिसका उद्देश्य उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सीतारमण ने कहा, अंतरिम बजट में घोषित की गई रणनीति के अनुसार, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। अनुसंधान और फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आता है।

सीतारमण ने अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने की पहल की घोषणा की, जिसे प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रयासों द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करते हुए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इस पहल में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान और भूमि रजिस्ट्री का निर्माण शामिल है।

सीतारमण ने कहा, चालू वित्त वर्ष में सरकार 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ मौसम के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण करेगी। छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला में किसान-उत्पादक संगठनों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीतारमण ने झींगा मछली उत्पादन और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली चारे पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर पांच प्रतिशत करने तथा झींगा एवं मछली चारे के निर्माण के लिए विभिन्न आदानों पर सीमा शुल्क में छूट देने का भी प्रस्ताव रखा। सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति की योजनाओं का खुलासा किया। पांच राज्यों में जन समर्थ-आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम किया जाएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन ग्रामीण आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान ने खुदकुशी की

मथुरा (उप्र)। मथुरा जनपद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा में तैनात प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 15वीं बटालियन के एक जवान ने अपनी बैरक में कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) अरविंद कुमार ने बताया कि सोमवार रात पीएसी के प्लाटून कमाण्डर ने सूचना दी थी कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा ड्यूटी कर रहे जवान सुधीर मलिक (25) ने हाईवे थानाक्षेत्र में स्थित पीएसी बैरक में सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुधीर गौतमबुद्ध नगर के निवासी थे। कुमार ने बताया कि वैसे तो यह साधारण खुदकुशी का मामला लग रहा है, परंतु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने तथा परिजनों द्वारा कोई तहरीर दिए जाने के बाद अन्य पहलुओं से भी जांच कराई जा सकती है। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव को लेकर संसद में विरोध जताएंगे इंडी गठबंधन के घटक

भाषा। नई दिल्ली

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के घटक दलों ने मंगलवार को फैसला किया कि वे केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव और अन्याय के खिलाफ बुधवार को संसद के बाहर और भीतर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर इंडी गठबंधन के घटक दलों के सदन में नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस बैठक में खरगे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता टी आर बालू, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन एवं कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एवं राघव चड्ढा और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे।

बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। बजट में हिंदुस्तान के तीन चौथाई राज्यों खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। हम संसद के बाहर और भीतर अपनी आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा, यह अन्याय है। यह संघीय ढांचे के खिलाफ बजट है। तिवारी ने दावा किया, यह भारतीय जनता पार्टी का बजट नहीं है, भारत सरकार का बजट है। लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया कि मानो यह भाजपा का बजट हो।

वेणुगोपाल ने कहा, इस सरकार ने बजट की अवधारणा को पहले ही नष्ट कर दिया है। अधिकतर राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए इसका विरोध कैसे किया जाए, इस पर इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से अनैतिक है। इससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी।

2024 में जनगणना की संभावना नहीं, बजट में केवल 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित

भाषा। नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मंगलवार को जनगणना के लिए 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 की तुलना में काफी कम है। उस समय दशक में एक बार होने वाले इस कार्य के लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपए की लागत से भारत की 2021 की जनगणना कराने और 3,941.35 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

जनगणना के तहत मकान सूचीकरण चरण और एनपीआर को अद्यतन करने का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। जनगणना कार्य अब भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक इसके लिए नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस वर्ष आम चुनाव हो चुके हैं, इसलिए 2024 में जनगणना का कार्य नहीं हो सकेगा। बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में 578.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। यह कार्य जब भी होगा, तो यह पहली डिजिटल जनगणना होगी जो नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर प्रदान करेगी।

बजट में 10 लाख रुपए तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा, यूजीसी के आवंटन में कटौती

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि उच्च शिक्षा नियामक विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए अनुदान 60 प्रतिशत से अधिक घटा दिया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के लिए आवंटन में भी लगातार दूसरे वर्ष कटौती की गई है। स्कूल शिक्षा के लिए बजट 535 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाया गया है लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अनुदान पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9,600 करोड़ रुपए से अधिक कम हो गया।

शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती की गई है। केंद्र ने 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय को 1.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 1.29 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रहे हमारे युवाओं की मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे दिए जाएंगे, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यापक और ठोस उपाय छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग-सभी हितधारकों के लिए लाभकारी हैं। प्रधान ने कहा, इससे हमारे युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी, लोगों को अधिक आजीविका के अवसर मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल तक पहुंच बढ़ेगी और अगले पांच वर्षों में 4.1 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे।

शैक्षणिक संस्थानों में शोध और नवाचार के लिए बजट में 161 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह, विश्व स्तरीय संस्थानों के लिए आवंटन 1,300 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से बढ़ाकर 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए वित्त पोषण को पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 6,409 करोड़ रुपए से घटाकर 2,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 60.99 प्रतिशत कम हुआ है। सरकार द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में भी इसमें कटौती की गई थी।

प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों आईआईएम को लगातार दूसरे साल बजट में कटौती का सामना करना पड़ा है। पिछले साल आईआईएम के बजट को 608.23 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) से घटाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस साल इसे 331 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से घटाकर 212 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के लिए बजट में भी पिछले साल के संशोधित अनुमान से मामूली कमी देखी गई है। पिछले साल का संशोधित अनुमान 10,384.21 करोड़ रुपए था और चालू वित्त वर्ष के लिए 10,324.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है।

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में 6,21,940 करोड़ रुपए का प्रावधान

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को 2024-25 में रक्षा व्यय के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के साथ-साथ रणनीतिक जलमार्गों में उभरती सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच अंतरिम बजट में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर ही है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 6,21,540 करोड़ रुपए था। रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन 2023-24 में किए गए बजटीय प्रावधान की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के लिए सेना को 1,72,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जिसमें मुख्य रूप से नए आयुध, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है। दैनिक परिचालन लागत और वेतन के लिए राजस्व व्यय 2.82 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि रक्षा पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए चिह्नित किए गए हैं, जो 2023-24 में किए गए आवंटन से 2.17 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र का कुल बजट भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। पूंजीगत परिव्यय पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवंटन का उद्देश्य मौजूदा और बाद के वित्त वर्षों में बड़े अधिग्रहणों के जरिए बड़े क्षमता अंतराल को पाटना है। उसने कहा, ए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित वायु यान, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से होने वाले पूंजी अधिग्रहणों पर वार्षिक नकद व्यय की जरूरत को पूरा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिकीकरण बजट का 75 प्रतिशत यानी 1,05,518.43 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू उद्योगों के जरिए खरीद के लिए तय किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वास्तविक अर्थों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बलों को पूंजीगत मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 प्रतिशत ज्यादा और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 प्रतिशत ज्यादा है। उसने कहा, परिचालन तत्परता के लिए निरंतर उंचा आवंटन सशस्त्र बलों का मनोबल उंचा करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें हर समय युद्ध के लिए तैयार रखना है। सरकार ने इस मद में चालू वित्त वर्ष के दौरान 92,088 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू पूंजी खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपए का आवंटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा। सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जहां तक रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन की बात है, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6,21,940.85 करोड़ रुपए के सर्वाधिक आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूं जो 2024-25 के लिए सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 1,72,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देगा। सिंह ने कहा, मुझे खुशी है कि सीमा सड़क संगठन के लिए पूंजीगत मद में पिछले बजट की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक आवंटन किया गया है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपए का यह आवंटन हमारे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को और गति देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी और तेज गति वाले विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, यह बजट देश के आर्थिक बदलाव को गति देगा। उन्होंने कहा कि यह 2027 तक भारत को 5 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

त्रिपुरा में 70 प्रतिशत पंचायत सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते

अगरतला। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में लगभग 70 प्रतिशत सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पंचायत प्रणाली में कुल 6,889 सीट हैं, जिनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं और भाजपा को 4,805 सीट पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। ग्राम पंचायतों में भाजपा को कुल 6,370 सीट में से 4,550 पर निर्विरोध जीत हासिल हुई है। इस वजह से 71 प्रतिशत सीट पर मतदान नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के सचिव असित कुमार दास ने बताया कि जिन 1,819 ग्राम पंचायत सीट पर मतदान होगा।

पुंछ में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम एक जवान बलिदान

जम्मू। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया, जिस दौरान एक जवान बलिदान हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। कोर ने कहा, भारी गोलीबारी के दौरान एक वीर जवान घायल हो गया। अभियान जारी है। सैनिकों को कृष्णाघाटी के बट्टल अग्रिम क्षेत्र में आतंकवादियों के समूह की गतिविधियों का पता चला और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लांस नायक सुभाष कुमार भीषण मुठभेड़ में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों को भी नुकसान पहुंचा है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 574 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 3183.24 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में 574.31 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का पहला बजट है। सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मंत्रालय के लिए 3097.60 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था, हालांकि संशोधित बजट में यह राशि 2608.93 करोड़ रुपए हो गई थी।

सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3183.24 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए इस बार 326.16 करोड़ रुपए तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए सरकार ने बजट में कुल 1575.72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मंत्रालय की प्रमुख योजनाओंपरियोजनाओं के लिए कुल 2120.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए इस बार 910.90 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

आईआरपीएस अधिकारी व लोस अध्यक्ष की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं : अदालत

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक्स कॉर्प और गूगल इंक को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंतरिम आदेश में अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा, और यदि वादी को समान तरह की किसी अन्य पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेंगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स , गूगल , केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा।

अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी बन गईं। अंजलि के वकील ने बताया कि वह यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थीं और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वह आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं।

सुनवाई के दौरान अंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा, तीन साल बाद, यह सोशल मीडिया अभियान फिर से शुरू हो गया है जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी बदनाम करता है, जिसमें उनके पिता भी शामिल हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ संवैधानिक पद पर आसीन हैं।

अधिवक्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल 2021 में एक अधिकारी बनी, लेकिन अब नीट और यूपीएससी परीक्षा विवाद के कारण अचानक ए चीजें फिर से सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब इसका हिस्सा हैं। अधिवक्ता ने कहा कि अंजलि (वादी) की निजी तस्वीरें यह कहते हुए ऑनलाइन पोस्ट की जा रही हैं कि वह एक मॉडल हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि साइबर अपराध विभाग में भी इसकी शिकायत की गई है।

पेज 1 का शेष

मध्यम वर्ग...

15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुई है। सीतारमण ने कहा, ऐसे समय जब दुनिया में अनिश्चिततताएं हैं, भारत की आर्थिक वृद्धि एक अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग और पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं और उपायों के लिए पांच साल की अवधि में दो लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर 75,000 रुपए करने के साथ नई आयकर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव किया। मानक कटौती के तहत आयकर की गणना करने से पहले वर्ष में अर्जित कुल वेतन में से निश्चित राशि घाटा दी जाती है। उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं को नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 17,500 रुपए तक की बचत होगी।

युवाओं के...

के वेतन का भुगतान, दोनों कर्मचारियों को निर्दिष्ट बिक्री पर प्रोत्साहन और रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके सेवानिवृत्ति निधि योगदान के संबंध में सशक्तिकरण और नियोक्ताओं को रुपये तक की प्रतिपूर्ति शामिल है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल के लिए 3,000 प्रति माह। चूंकि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव का सामना करने के लिए तैयारी कर रही है, इसलिए भी यह तत्परता महसूस की जा रही है, जहां पार्टी को लोकसभा चुनावों में झटका लगा था। मोदी 3.0 का बजट इस बात का भी संकेत है कि सरकार रोजगार सृजन पर अधिक गंभीरता से विचार करेगी, यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि बेरोजगारी और बेरोजगार विकास अभियान के दौरान और उसके दौरान विपक्ष के कथन का प्रमुख विषय रहा है। सीतारमण ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए तीन योजनाएं पेश कीं, पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान को लक्षित करना और पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना, रोजगार सृजन पर स्पष्ट जोर है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अगले पांच वर्षों में नौकरियां पैदा करने के लिए 2 ट्रिलियन रुपये आवंटित करेगा। सीतारमण ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, कौशल में सुधार और उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के कार्यक्रमों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र सहित कंपनियों के लिए प्रोत्साहन शुरू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भारत की आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत है, लेकिन निजी एजेंसी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसे 8.4 प्रतिशत से अधिक बताती है। फर्स्ट टाइमर्स योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी। रोजगार के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। तीसरी योजना नियोक्ता केंद्रित होगी जो सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। प्रति माह एक लाख रुपये के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है। चूंकि भाजपा पिछले कुछ वर्षों से एमएसपी के मुद्दे पर किसानों के विरोध का सामना कर रही थी और हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अपनी लोकसभा सीटों में गिरावट को देखते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों के लिए नए 109 उच्च उपज वाले, जलवायु लचीले बीज जारी करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभोग केंद्रों के करीब विकसित किए जाएंगे। हम संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे। 6 करोड़ किसानों और उनके बारे में वित्त मंत्री ने कहा, भूमि को किसान और भूमि रजिस्ट्रियों में लाया जाएगा, इसके अलावा, जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने को सक्षम बनाया जाएगा।

सुनहरे...

आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने और उस पूरी प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इससे नया मध्यम वर्ग बना है, यह उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का भी बजट है। उन्होंने कहा, यह नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है।

बिहार...

वहीं जेडी (यू) के लोकसभा में 12 सदस्य हैं, जो इसे सत्तारूढ़ गठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा घटक बनाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश को समर्थन देने के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय बजट ने बिहार के लिए बड़े उपायों की घोषणा की, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय का प्रस्ताव किया गया, जिसमें तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारे और नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण शामिल है। सीतारमण ने तीन सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं - पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा स्पर और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के समर्थन की घोषणा की। बजटीय घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, आंध्र प्रदेश टीडीपी सुप्रीमो और सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जरूरतों को पहचानने और केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और एपी में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी और सीतारमण को धन्यवाद दिया। अपनी प्रतिक्रिया में, केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने विपक्ष के इस दावे की आलोचना की कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट के उपायों का उद्देश्य अस्तित्व के लिए राज्यों के क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता के कारण सरकार को बचाना है। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी ने या तो दर्जा या विशेष वित्तीय पैकेज मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई विकास उपायों की सीतारमण की घोषणाओं को अपनी सरकार को 'बचाने' के लिए भाजपा की राजनीतिक मजबूरी से जोड़ा और पूछा कि क्या भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए कुछ है।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, अन्य उपायों की घोषणा

भाषा। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी गारंटी या तीसरे पक्ष की गारंटी से सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी।अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीतारमण ने कहा, हमने एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, नियामकीय बदलाव और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए एक पैकेज तैयार किया है, ताकि उन्हें बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना ऐसी संस्थाओं के ऋण जोखिमों को एकत्रित करके संचालित होगी। वित्त मंत्री ने कहा, अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्एक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर प्रदान करेगी, जबकि कर्ज राशि इससे अधिक हो सकती है। उधारकर्ता को अग्रिम गारंटी शुल्क तथा कम किए गए ऋण शेष पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा। उन्होंने संकट काल में एमएसएमई को बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की भी घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को अपने नियंत्रण से परे कारणों से विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) चरण में होने के बावजूद अपना कारोबार जारी रखने और एनपीए चरण में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, ऋण उपलब्धता को सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने एमएसएमई को ऋण देने के लिए एक नए मूल्यांकन मॉडल की भी घोषणा की।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ए केंद्र निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक ढांचे के तहत एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करेगी। टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ शहरी गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की तथा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी देने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा, ...बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ कुशल तथा पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए सक्षम नीतियां व नियम भी लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तरह किराए के आवास की सुविधा प्रदान करेगी। यह कार्य वीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड में किया जाएगा। कर प्रस्तावों पर सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि मकान या मकान के किसी हिस्से को मालिक द्वारा किराए पर देने से होने वाली आय को व्यापार या पेशे से होने वाले लाभ व प्राप्ति शीर्षक के तहत नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस पर केवल गृह संपत्ति से आय शीर्षक के तहत कर लगाया जाएगा। अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक हस्तांतरक या हस्तांतरिती हैं, तो अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए ऐसा प्रतिफल, सभी हस्तांतरितियों द्वारा हस्तांतरक को या सभी हस्तांतरकों द्वारा ऐसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान की गई या देय राशि का योग होगा। सीतारमण ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, पूर्ण और सत्य खुलासा करने पर बेनामीदार को दंड तथा अभियोजन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। संपत्ति की कुर्की और न्याय निर्णय प्राधिकरण को संदर्भित करने के लिए समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है।

महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में कटौती पर विचार: सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करप्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते है ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा`गी। उन्होने अपने बजट भाषण मे कहा,`हम उन राज्यो को प्रोत्साहित करेगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते है ताकि वे सभी के लिए दरो को कम कर सकें और महिलाओ द्वारा खरीदी गई संपतियो के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सके। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओ का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कराधान उद्देश्यो के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान का उल्लेख बंद करने का भी प्रस्ताव रखा।

शेयर पुनर्खरीद पर चुकाई गई राशि को लाभांश माना जाएगा, शेयरधारकों पर लगेगा कर: सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि एक अक्टूबर से शेयरों की पुनर्खरीद पर शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश के समान कर लगाया जाएगा। यह एक ऐसा कदम जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, इन शेयरों को हासिल करने के लिए शेयरधारक जिस राशि का भुगतान करेंगे, उसे उनके पूंजीगत लाभ या हानि की गणना में जोड़ा जाएगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, इक्विटी के लिए मैं प्राप्तकर्ता के हाथों में शेयरों की पुनर्खरीद से हुई आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। यह प्रस्ताव है कि कंपनियों के शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय को प्राप्तकर्ता निवेशक को मिले लाभांश के रूप में मानकर कर लिया जाए। वर्तमान व्यवस्था के तहत इसे कंपनियों को हुई अतिरिक्त आमदनी मानकर इस पर आयकर लगाया जाता है।

दूरसंचार मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ आवंटित

बीएसएनएल को 82,916 करोड़ रुपए मिले

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसमें से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है।कुल प्रस्तावित आवंटन में से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए हैं, जिसमें बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। बजट के अनुसार, बजट अनुमान 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपए (1,11,915.43 करोड़ रुपए और 17,000 करोड़ रुपए) है। 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा किया जाता है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। बजट में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 17,510 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए 3,668.97 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। बजट में प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 34.46 करोड़ रुपए, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए 70 करोड़ रुपए तथा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए 1,806.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवंटन के अलावा, सरकार ने घरेलू दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में मदरबोर्ड (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मैं निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली) पर बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।ूरसंचार पीसीबी निर्माण के लिए मूल सीमा शुल्क में वृद्धि, संचार उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों को छूट के साथ आती है।वित्त मंत्री ने 25 खनिजों जैसे लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है। ए खनिज परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क कम किया जाएगा।सीतारमण ने कहा, इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा तथा इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र ने भविष्यदर्शी बजट की सराहना की

टिकैत ने खाली हाथ बताया

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर कृषि क्षेत्र से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। उद्योग विशेषज्ञों ने शोध और आत्मनिर्भरता पर इसके ध्यान बिन्दु (फोकस) की प्रशंसा की है, जबकि कुछ किसान नेताओं ने बजट पर निराशा जताई है। कृषि उद्योग के विशेषज्ञों ने बजट को भविष्यदर्शी बताते हुए इसकी सराहना की है, जिसमें कृषि-अनुसंधान और दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हालांकि, भारत किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट ने किसानों को खाली हाथ छोड़ दिया क्योंकि यह प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रहा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन का स्वागत करते हुए कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयात निर्भरता को कम करने में परिवर्तनकारी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण मिशन को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

टिकैत ने जलवायु परिवर्तन के नाम पर कृषि अनुसंधान में निजी क्षेत्र को धन मुहैया कराने, विदेशी लॉबी समूहों और बड़ी कंपनियों को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने देने पर चिंता व्यक्त की। गुड फूड इंस्टिट्यूट इंडिया की कार्यवाहक प्रबंध निदेशक स्नेहा सिंह ने कहा, हम आयात पर निर्भरता कम करने और प्लांट प्रोटीन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अधिक रास्ते बनाने के लिए दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर विशेष ध्यान देने की सराहना करते हैं। धानुका समूह के अध्यक्ष आर जी अग्रवाल ने कहा, बजट ने अनुसंधान और विकास में कम निवेश और कम फसल पैदावार की दोहरी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूआरएमएस) के सह-संस्थापक और सीटीओ, आशीष अग्रवाल ने कहा, इस प्रगति का पूरा लाभ उठाने के लिए, आईओटी, एआई और डेटा एनालिटिक्स में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

बजट घोषणाओं से शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव

सेंसेक्स, निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद

मुंबई (भाषा) वायदा एवं विकल्प सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मंगलवार को बजट में प्रावधान किए जाने से घरेलू शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव रहा। हालांकि, मानक सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आखिर में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स एक समय।,200 अंक से ज्यादा गोता लगा गया था। लेकिन बजट भाषण खत्म होने के बाद इसने धीरे-धीरे अपने नुकसान की काफी हद तक भरपाई कर ली। कारोबार के अंत में यह 73.04 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 80,429.04 अंक पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले कर एसटीटी में बढ़ोतरी और इक्विटी निवेश पर दीर्घकालिक अवधि में होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर को बढ़ाने की घोषणा की। बजट में इन कदमों की घोषणा होते ही शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर गिरावट देखी जाने लगी। उस समय सेंसेक्स।,277.76 अंक यानी 1.58 प्रतिशत तक टूटकर 79,224.32 अंक के निचले स्तर पर आ गया था। हालांकि, कर रियायतों और सीमा शुल्क में कटौती ने टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों और दैनिक उपभोग वाले सामान बनाने वाली कंपनियों (एफएमसीजी) के शेयरों को बढ़ावा देने में मदद की, जिससे शेयर दिन के निचले स्तर से उबरने में सफल रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 30.20 अंक यानी 0.12 प्रतिशत गिरकर 24,479.05 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 435.05 अंक यानी 1.77 प्रतिशत फिसलकर 24,074.20 पर आ गया था। सेंसेक्स के समूह में शामिल टाइटन ने छह प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई जबकि आईटीसी में पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़त रही।

इनके अलावा अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और सन फार्मा के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए।

संक्षिप्त समाचार

कई खरीदारों के 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर लगेगा एक प्रतिशत टीडीएस

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 50 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगेगा, भले ही लेनदेन में कई खरीदार और विक्रेता शामिल हों। कर प्रावधानों की गलत व्याख्या के मामलों के बीच सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। सरकार ने कहा कि कई विक्रेताओं या खरीदारों से जुड़ी 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू होगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस के प्रावधान का उल्लेख किया। बजट दस्तावेज के मुताबिक, अधिनियम की धारा 194-आईए में कृषि भूमि से इतर अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए जाने वाले के भुगतान पर कर कटौती का प्रावधान है। इसे स्पष्ट करने के लिए इस धारा में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में किए गए संशोधन एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। सीतारमण ने कहा, यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में एक से अधिक विक्रेता या खरीदार होने की स्थिति में भुगतान सभी विक्रेताओं को चुकाई गई राशि का योग होगा। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, एक खरीदार अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विक्रेता को भुगतान की गई राशि पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है। बजट दस्तावेज में सरकार ने धारा 194-आईए की उप-धारा (2) में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी अचल संपत्ति का एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए चुकाई गई कुल राशि को इसका मूल्य माना जाएगा।

सरकार राज्यों को संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क घटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संपत्तियों की खरीद पर अधिक स्टाम्प शुल्क लगाने वाले राज्यों को दरें कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुधार शहरी विकास योजनाओं का एक प्रमुख हिस्सा होगा।उन्होंने राज्यों से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प शुल्क को और कम करने पर विचार करने को भी कहा। सीतारमण ने कहा, हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं, ताकि सभी के लिए दरों में कमी की जा सके और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार किया जा सके। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य तत्व बनाया जाएगा। स्टाम्प शुल्क एक ऐसा कर है जो राज्य सरकारों द्वारा संपत्तिसंपत्ति स्वामित्व की बिक्री पर लगाया जाता है। यह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा तीन के तहत देय है। राज्यों के लिए स्टाम्प शुल्क विकास कार्यों के लिए धन जुटाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

रेलवे का बड़ा ध्यान सुरक्षा संबंधी कार्यों, कवच लगाने पर: वैष्णव

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा रेल सुरक्षा संबंधी गतिविधियों और स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली कवच पर खर्च करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आम बजट 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए यह बात कही। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो पूंजी निवेश के लिए एक रिकॉर्ड आवंटन है। वैष्णव ने कहा, इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा -।,08,795 करोड़ रुपए - सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए है, जैसे पुरानी पटरियों को नए से बदलना, सिग्नल प्रणाली में सुधार और फ्लाईओवर तथा अंडरपास का निर्माण, और कवच लगाना। उन्होंने कहा कि इन सभी सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में कवच लगाना रेलवे की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।

मंत्री के अनुसार स्वचालित ट्रेन-सुरक्षा प्रणाली के उन्नत संस्करण कवच 4.0 को हाल में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन से मंजूरी मिली है। अब इसे तेजी से रेलगाड़ियों में लगाया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि कवच के घटकों में शामिल ऑप्टिकल फाइबर केबल 4,275 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिछाई गई है और अन्य घटक- जैसे दूरसंचार टावर, ट्रैक आरएफआईडी उपकरण, स्टेशन कवच और लोको कवच भी तेजी से लगाए जा रहे हैं। संप्रग शासन के दौरान रेलवे के लिए बजटीय आवंटन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 के आसपास रेलवे के लिए बजटीय आवंटन केवल लगभग 35,000 करोड़ रुपए हुआ करता था और आज यह 2.62 लाख करोड़ रुपए के नए स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के शासन की कड़ी मेहनत और लक्ष्य केंद्रित नजरिए को आगे बढ़ाता है।

अर्थशास्त्रियों ने कहा, बजट में रोजगार मुद्रास्फीति पर ध्यान देना अच्छा संकेत

नई दिल्ली (भाषा) प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने मंगलवार को बजट 2024-25 को रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति प्रबंधन और राजकोषीय विवेक पर केंद्रित बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत बताया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि सरकार ने रोजगार और कौशल विकास को पहली प्राथमिकता दी है। कुमार ने कहा, इससे पता चलता है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और वह कुछ अर्थशास्त्रियों की तरह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के झूठे दावों से प्रभावित नहीं हो रही है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती ने पीटीआई-भाषा से कहा कि केंद्र सरकार के ऋण और घाटे को राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप स्तर तक कम करने के लिए राजकोषीय विवेक के एक स्थिर मार्ग पर चलना जारी रखना होगा। उन्होंने कहा, बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। एनआईपीएफपी के प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने पीटीआई-भाषा से कहा, केंद्रीय बजट 2024-25 मोटे तौर पर अंतरिम बजट की ही निरंतरता है जिसमें कुछ बेहतर राजकोषीय गुंजाइश के साथ-साथ नौकरियों की ओर भी ध्यान दिया गया है। औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) के निदेशक नागेश कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि वित्त मंत्री का बजट व्यापक क्षेत्र को अपने दायरे में लेने वाला है। प्रमुख विषयों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था की स्थिरता और गतिशीलता को बढ़ाना शामिल है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी है तो उसके आवंटन को काफी हद तक बढ़ाना होगा, न कि मामूली रूप से। उन्होंने कहा, रोजगार सृजन के लिए पूंजी गहन क्षेत्रों के बजाय श्रम प्रधान क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

हमास और फतह ने मतभेद खत्म करने के लिए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए

भाषा। बीजिंग

गाजा में युद्ध के बीच एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फतह और हमास सहित 14 फलस्तीनी समूहों ने मंगलवार को चीन की मध्यस्थता में हुई एक बैठक में, आपसी मतभेदों को खत्म करने और फलस्तीनी एकजुटता को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से संकल्प लिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पिछले तीन दिन प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बातचीत का समन्वय किया। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह घोषणा इजराइली हमलों से त्रस्त गाजा पट्टी में व्यापक, टिकाऊ और सतत युद्धविराम को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम है। चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने इन गुटों के नेताओं से मुलाकात की और कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर फलस्तीन मुद्दे के लिए एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक क्षण है।

उन्होंने कहा कि समझौते के तहत प्रतिद्वंद्वी समूह युद्ध के बाद गाजा पर शासन करने के लिए एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार बनाने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य इजराइल के साथ संघर्ष में फलस्तीनियों को एकजुट करना है। इजराइल ने पिछले साल अक्टूबर में 200 से अधिक इजराइली बंधकों के अपहरण के बाद गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। हस्ताक्षरकर्ताओं में हमास के वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजूक और फतह के दूत महमूद अल-अलौल के साथ-साथ 12 अन्य फलस्तीनी समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार है जब 14 प्रतिद्वंद्वी समूह सुलह वार्ता के लिए बीजिंग में एकत्र हुए। वांग ने कहा, सुलह फलस्तीनी गुटों का आंतरिक मामला है, लेकिन साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। वांग ने कहा, मुख्य परिणाम यह है कि पीएलओ (फलस्तीन मुक्ति संगठन) सभी फलस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि गाजा युद्ध के बाद शासन और एक अंतरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार के गठन पर समझौता हुआ है। हालांकि, वांग की टिप्पणियों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमास, जो पीएलओ का हिस्सा नहीं है, ऐसी व्यवस्था में क्या भूमिका निभाएगा, या किसी भी समझौते का तत्काल प्रभाव क्या होगा। हमास गाजा पट्टी पर शासन करता है, जबकि फतह फलस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रित करता है, जिसका वेस्ट बैंक पर आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण है। इजराइल ने गाजा में युद्ध समाप्त होने से पहले हमास को नष्ट करने का संकल्प लिया है। इजराइल ने बीजिंग घोषणा को तुरंत खारिज कर दिया। इजराइल के विदेश मंत्री आई. काट्ज ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, आतंकवाद को खारिज करने के बजाय, महमूद अब्बास हमास के हत्यारों और बलात्कारियों को गले लगाते हैं, जिससे उनका असली चेहरा सामने आया है। इस घोषणापत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं, जब इजराइल और हमास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नौ महीने से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है और हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइली नागरिकों की आजादी की राह तैयार कर सकता है।

हालांकि, समझौते पर सहमति बनने के बावजूद युद्ध के बाद गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल इस क्षेत्र के शासन में हमास की किसी भी भूमिका के खिलाफ है। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी के मुताबिक, फलस्तीन के दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों ने मतभेद खत्म करने और फलस्तीनी एकता को मजबूत करने के संबंध में बीजिंग घोषणापत्र पर दस्तखत किए। हमास ने वर्ष 2007 में हिंसक संघर्ष के दौरान फलस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास के वफादार फतह लड़ाकों को गाजा पट्टी से खदेड़कर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों समूह एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।

साल 2023 में करीब चार करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रह रहे थेः संयुक्त राष्ट्र

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल करीब चार करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रह रहे थे और 90 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था जिसके चलते हर मिनट एड्स संबंधी कारण से किसी न किसी संक्रमित की मौत हुई है। एचआईवी संक्रमण आगे जाकर एड्स बन जाता है। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए प्रगति तो हो रही है, लेकिन इसकी गति धीमी हो गई है, वित्तपोषण कम हो रहा है तथा नए क्षेत्रों -पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तथा लैटिन अमेरिका में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनएड्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में 6.30 लाख लोगों की एड्स से संबंधित बीमारियों के कारण मौत हो गई। इस तादाद में 2004 की तुलना में खासी कमी आई है जब 21 लाख लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा एड्स से संबंधित मौतों की संख्या को 2025 तक ढाई लाख से कम कम करने के लक्ष्य का दोगुना से ज्यादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंगिक असमानता लड़कियों और महिलाओं के लिए जोखिम बढ़ा रही है तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों में किशोरों और युवतियों में एचआईवी के मामले अत्यधिक बढ़ रहे हैं।

यूएनएड्स की कार्यकारी निदेशक विनी ब्यानईमा ने कहा, वैश्विक नेताओं ने संकल्प लिया है कि 2030 तक एड्स महामारी को लोक स्वास्थ्य के लिए खतरे के तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा और वे अपना वादा निभा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे यह सुनिश्चित करें कि एचआईवी संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, और सभी के मानवाधिकारों की रक्षा हो। रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 3.99 करोड़ लोग एचआईवी संक्रमण के साथ रहे थे जिनमें से 86 फीसदी को पता था कि वे संक्रमित हैं जबकि 77 प्रतिशत संक्रमित इलाज करा रहे थे।

ब्रिटेन की संसद में सुनक दो नवंबर तक अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे

लंदन। ब्रिटेन की संसद में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दो नवंबर तक अंतरिम नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की समय सारिणी के अनुसार नवंबर तक उनके उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। टोरी (कंजर्वेटिव पार्टी) का नेतृत्व कौन करेगा, यह तय करने के लिए संसद के बैकबेंच सदस्यों की 1922 समिति ने सोमवार शाम को दो चरण की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके तहत दो नवंबर को नए नेता की नियुक्ति की जाएगी।

ब्रिटिश भारतीय नेता ऋषि सुनक (44) ने आम चुनाव में पार्टी की सबसे बुरी हार के बाद पांच जुलाई को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता तब तक वह टोरी के अंतरिम नेता की जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे।

सुनक ने कहा, पार्टी का नेतृत्व हासिल करने के उम्मीदवारों या इससे जुड़े अभियान के बारे में कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। मुझे विश्वास है कि पार्टी बोर्ड और 1922 समिति द्वारा तय की गई यह समय सारिणी एक विचारशील, पेशेवर और सम्मानजनक मुकाबले की अनुमति देगी। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख नेताओं में भारतीय मूल की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल और सुएला ब्रेवरमैन, शैडो मंत्री जेम्स क्लेवरली, केमी बेडेनोच, टॉम तुगेंदट, मेल स्ट्राइड और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनरिक शामिल हैं।

ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं : कमला हैरिस

वाशिंगटन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले के साथ की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। डेलावेयर के विलमिंगटन में सोमवार को अपनी प्रचार टीम को संबोधित करते हुए कमला (59) ने कहा कि ट्रंप का विवादित प्रोजेक्ट 2025 मध्यम वर्ग को कमजोर करेगा और हमें एक बार फिर उन विफल नीतियों की ओर ले जाएगा, जिनके तहत अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को करों में भारी छूट दी गई और कामकाजी लोगों से इसकी भरपाई करवाई गई।

राष्ट्रपति जो बाइडन (81) के गत रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला (59) के नाम की सिफारिश की थी। इसके अगले दिन बाइडन की प्रचार अभियान टीम का नाम बदलकर हैरिस कैंपेन कर दिया गया था। कमला ने प्रचार टीम के सदस्यों से कहा कि वह बाइडन-हैरिस कैंपेन टीम को बरकरार रख रही हैं।

ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को उस दौर में ले जाना चाहते हैं, जब कई अमेरिकियों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार हासिल नहीं थे। लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य में यकीन करते हैं, जिसमें सभी अमेरिकियों के लिए जगह है। हम एक ऐसे भविष्य में यकीन करते हैं, जहां हर व्यक्ति के पास न केवल आजीविका जुटाने का, बल्कि आगे बढ़ने का भी मौका हो।

कमला ने कहा, हम ऐसे भविष्य में यकीन करते हैं, जहां किसी भी बच्चे को गरीबी में न पलना-बढ़ना पड़े, जहां हर व्यक्ति घर खरीद सके, परिवार बढ़ा सके और धन अर्जित कर सके, जहां हर व्यक्ति को सवैतनिक पारिवारिक अवकाश और बच्चों की किफायती देखभाल की सुविधा मिले। हम ऐसा ही भविष्य चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम साथ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को किफायती स्वास्थ्य देखभाल मिले, जहां हर कर्मचारी को उचित वेतन मिले, और जहां हर वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो सके। ए सब मेरे राष्ट्रपति कार्यकाल के अहम लक्ष्य होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मध्यम वर्ग मजबूत होगा, तो अमेरिका मजबूत होगा।

कमला ने आरोप लगाया कि यह वह भविष्य नहीं है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप और उनका विवादित प्रोजेक्ट-2025 मध्यम वर्ग को कमजोर कर देगा। यह हमें उन विफल नीतियों की ओर वापस ले जाएगा, जिनके तहत अरबपतियों और बड़ी कंपनियों को भारी कर छूट दी गई और कामकाजी वर्ग से इसकी भरपाई करवाई गई। कमला ने याद दिलाया कि उपराष्ट्रपति बनने या सीनेट के लिए चुने जाने से पहले वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थीं। उन्होंने लंबे समय तक वकालत भी की।

इथियोपिया में भूस्खलन में बच्चों समेत कम से कम 157 लोगों की मौत

अदीस अबाबा। इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्राधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। स्थानीय प्रशासक दागमावी आएले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। गोफा जोन के संचार कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अबेयनेह ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 157 हो गई। सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी। गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है। ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए। उस समय बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। आएले ने बताया कि मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया। गोफा में एक अन्य अधिकारी मार्कोस मेलीसे ने बताया कि अन्य लोगों को बचाने की कोशिश करते वक्त भूस्खलन की चपेट में आए लोगों में से कई लापता हैं। गोफा जोन में आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी के निदेशक मेलीसे ने बताया, हम अब भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया, कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट कर रो रहे हैं। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

वेंस ने अपनी शुरुआती चुनावी रैलियों में कमला हैरिस पर तीखे हमले किए

रेडफोर्ड (अमेरिका)। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जे डी वेंस ने सोमवार को अपनी शुरुआती चुनावी रैलियों में मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर तीखे हमले किए। इससे एक दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से हटने की घोषणा की और इस पद के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था। ओहायो के सीनेटर ने वर्जीनिया के रेडफोर्ड में शाम को एक रैली को संबोधित करने से पहले मिडलटाउन में अपने पूर्व हाई स्कूल में प्रचार किया। वेंस ने वर्जीनिया में कहा, इतिहास जो बाइडन को मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ ही अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में याद रखेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, कमला हैरिस उनसे भी लाख गुना बदतर हैं और यह बात हर कोई जानता है। उन्होंने जो बाइडन की हर विफलता पर मुहर लगाई है और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम करने की उनकी (बाइडन) मानसिक क्षमता के बारे में झूठ बोला है। वेंस (39) ने अपनी और हैरिस की जीवनशैली की भी तुलना की। उन्होंने कहा कि वह मरीन कोर में सेवा दे रहे थे और छोटा-सा कारोबार चला रहे थे जबकि हैरिस पिछले 20 साल से सरकारी तनख्वाह पा रही हैं। ट्रंप और वेंस ने शनिवार को फॉक्स न्यूज को संयुक्त साक्षात्कार दिया था जिसका प्रसारण वेंस की रैलियों के बाद सोमवार शाम को किया गया।

ब्रिटिश-पाकिस्तानी कट्टरपंथी उपदेशक आतंकी संगठन को दिशा-निर्देश देने के लिए दोषी करार

लंदन। ब्रिटिश-पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामवादी उपदेशक अंजम चौधरी को एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को दिशा-निर्देश देने का दोषी पाया गया और संयुक्त अंतरराष्ट्रीय जांच के बाद ब्रिटेन में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। चौधरी (57) को अल-मुहाजिर (एएलएम) में कार्यवाहक की भूमिका निभाते पाया गया था और लंदन के वूलविच क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उसने 2014 के बाद एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए आतंकवादी समूह को दिशा-निर्देश दिए थे और ऑनलाइन माध्यम से की गई बैठकों को संबोधित करके संगठन के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया था। 30 जुलाई को उसे सजा सुनाई जाएगी, माना जा रहा है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की ओर से की गई जांच के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो पाई।

श्रीलंका ने नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया

कोलंबो। श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कथित तौर पर अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी नौकाएं जब्त कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस वर्ष श्रीलंका द्वारा ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 261 हो गई है। नौसेना ने कहा कि उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के डेल्फ्ट द्वीप पर नौ मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनकी दो नौकाएं जब्त की गई। नौसेना ने 11 जुलाई को कहा था कि इस साल अवैध शिकार करने को लेकर 252 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और 35 नौकाएं जब्त की गई है। इस माह के आरंभ में श्रीलंका ने भारत के समक्ष एक नौसैनिक की मौत के मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। नौसैनिक की द्वीपीय राष्ट्र के जलक्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से मछली पकड़ने में लगी एक भारतीय नौका को जब्त करने के अभियान के दौरान मौत हो गई थी।

कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर को विरूपित किया गया

ओटावा। कनाडा के एडमॉन्टन शहर में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवार पर कथित तौर पर घृणास्पद और भारत विरोधी बातें लिखकर उसे विरूपित किए जाने का मामला सामने आया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हम एडमॉन्टन में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर को भारत विरोधी नारे लिखकर विरूपित किए जाने की निंदा करते हैं। हमने कनाडाई अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्वाई करने का अनुरोध किया है।

मंदिर संचालन संस्था बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण (बीएपीएस) ने इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एडमॉन्टन सेंटर से सांसदाप्रतिनिधि रैंडी बोइसोनॉल्ट ने कहा, एडमॉन्टन मंदिर को पेंट से विरूपित किया गया, उस स्थान की दीवारों पर घृणित बयानबाजी लिखी गई, जो शरणस्थली होना चाहिए था। कनाडा में घृणा का कोई स्थान नहीं है - पूजा और प्रार्थना के स्थानों पर तो कतई नहीं। यह घटना निंदनीय है और हमारे शहर के मूल्यों के विरुद्ध है।

कनाडा में हिंदू व्यापारिक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीएचसीसी) के एक बयान में कहा गया, यह घटना न केवल एक भौतिक संरचना पर हमला है, बल्कि हिंदू समुदाय की भावनाओं और हमारे समाज के सम्मान एवं सहिष्णुता के सिद्धांतों का भी अपमान है। उसने घृणा के इस मूर्खतापूर्ण कृत्य और कनाडा में हिंदूफोबिया (हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रह) की बढ़ती लहर की निंदा की और कहा, ए घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं और हमारे बहुसांस्कृतिक एवं समावेशी समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। पिछले साल मंदिरों को विरूपित किए जाने की कम से कम तीन घटनाएं हुई थीं।

मध्य माली में हिंसक हमले में कम से कम 26 ग्रामीणों की मौत

बमाको। बुर्किना फासो की सीमा के समीप माली के मध्य क्षेत्र के एक गांव पर एक सशस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बैंकोस कस्बे के मेयर मौलाए गुइंडो ने बताया कि डेंबो गांव में हमलावरों ने रविवार शाम को ग्रामीणों पर उस समय हमला कर दिया, जब उनमें से अधिकतर लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। देश की सैन्य सरकार उत्तरी क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। मध्य माली में ऐसे हमले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार के हुए हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे अल-कायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन जेएनआईएम का हाथ माना जा रहा है जो क्षेत्र के ग्रामीणों को अक्सर निशाना बनाता है। विद्रोहियों ने जुलाई में भी इसी तरह एक विवाह समारोह पर हमला किया था और कम से कम 21 लोगों की हत्या कर दी थी।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा आतंकवाद जैसा खतरा : ब्रिटेन की पुलिस ने दी चेतावनी

भाषा। लंदन

ब्रिटेन के पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक बढ़ गई है और पुलिस इससे आतंकवाद के खतरे के तौर पर निपट रही है। नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल और कॉलेज ऑफ पुलिसिंग द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की पुलिस ने 2022 से 2023 के बीच महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज किए हैं जो इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए कुल मामलों का पांचवां हिस्सा है।

इसी अवधि में हर छह में से एक हत्या घरेलू हिंसा से संबंधित थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हर साल 12 में से एक महिला यौन अपराध, बलात्कार, पीछा करने, उत्पीड़न या ऑनलाइन यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों का शिकार होती है। हालांकि, यह संख्या बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि इस तरह के अपराध के कई मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं।

उप प्रमुख कांस्टेबल मैगी ब्लिथ ने एक बयान में कहा, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक राष्ट्रीय आपात स्थिति है। उन्होंने कहा, हमें बदलाव लाने के लिए एक समाज के रूप में आगे बढ़ना होगा और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को अपरिहार्य मानना बंद करना होगा। ब्रिटेन की सरकार ने पिछले वर्ष, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खतरा माना था, तथा पुलिस से कहा गया था कि उसे इस मुद्दे को आतंकवाद और गंभीर संगठित अपराध के समान प्राथमिकता देना चाहिए।

कोविड-19 पीड़ितों के जबरन दाह संस्कार पर मुसलमानो से माफी मांगेगी श्रीलंकाई सरकार

भाषा। कोलंबो

श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह कोविड-19 से जान गंवाने वाले मुस्लिम व्यक्तियों के जबरन दाह संस्कार के लिए देश के मुस्लिम समुदाय से औपचारिक रूप से माफी मांगेगी। श्रीलंकाई सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कोरोना महामारी के दौरान विवादित शवदाह नीति लागू की थी। वर्ष 2020 में कोविड-19 पीड़ितों के दाह संस्कार का अनिवार्य आदेश जारी किया गया था जिससे मुसलमानों सहित कई अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। हालांकि, बढ़ती अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बीच फरवरी 2021 में इस आदेश को रद्द कर दिया गया था।

एक कैबिनेट नोट के अनुसार, श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने सोमवार को एक बैठक में मार्च 2020 में थोपे गए आदेश के लिए मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से सभी समुदायों से माफी मांगने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने ऐसे विवादास्पद कदमों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कानून लाने का भी निर्णय लिया। बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने धर्म के आधार पर शवों को दफनाने या दाह संस्कार पर एक प्रस्तावित कानून को भी मंजूरी दे दी है। इसमें एक कानून लाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो किसी खास व्यक्ति या रिश्तेदारों को मृत व्यक्ति को दफनाने या उसका दाह संस्कार के चयन की अनुमति देगा।

मुस्लिम समुदाय ने जबरन दाह संस्कार नीति का विरोध किया था और कुछ ने तो अपने प्रियजनों के शवों को अस्पताल के मुर्दाघरों में छोड़ दिया था। समुदाय के सदस्यों ने कहा था कि या तो उन्हें शव जलाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया गया था या उनकी जानकारी के बिना ऐसा किया गया था। इस्लाम में शव दाह वर्जित है।

फरवरी 2021 में आदेश के रद्द किए जाने से पहले श्रीलंका में 276 मुस्लिमों का दाह संस्कार किया गया। श्रीलंका की सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देकर दफनाने की अनुमति देने की मांग का विरोध किया था। तब सरकार ने कुछ विशेषज्ञों की राय का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने से जल स्तर प्रदूषित हो जाएगा जिससे महामारी और फैलेगी।

कमला के लिए प्रचार करेंगे बाइडन, राष्ट्रपति पद की दौड़ से पीछे हटने के फैसले को सही कदम बताया

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटने के अपने फैसले को सोमवार को सही कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते वह अभी लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वह जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।

बाइडन (81) ने गत रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस (59) के नाम की सिफारिश की थी। अपनी पूर्व प्रचार टीम को फोन पर संबोधित करते हुए बाइडन ने इसके सदस्यों से उपराष्ट्रपति कमला को दिल से अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभियान टीम का नाम बदलकर भले ही हैरिस कैंपेन कर दिया गया है, लेकिन इसका मिशन वही है-डोनाल्ड ट्रंप को हराना। बाइडन जून में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से ही राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के दबाव का सामना कर रहे थे। उनकी सेहत को लेकर जारी अटकलों के कारण भी डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी जगह किसी और को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी सौंपने की मांग जोर पकड़ने लगी थी।

राष्ट्रपति अभी कोविड-19 संक्रमण की चपेट में होने के कारण पृथकवास में हैं। उन्होंने अपनी पूर्व प्रचार टीम से कहा, अगर मुझे कोविड नहीं हुआ होता, तो मैं वहां आपके साथ बैठा होता, आपके साथ खड़ा होता। कोविड अगले तीन-चार दिन तक मुझे लोगों से दूर रखेगा, लेकिन मैं जल्द मैदान में उतरने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बाइडन ने कहा, कोविड ने मुझे अभी कुछ दूर रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग याद रखें कि हमने जो किया है, वह अविश्वसनीय है और हम आगे भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं।

उन्होंने अपनी पूर्व प्रचार टीम से कमला को दिल से अपनाने, एकजुट होकर काम करने और ट्रंप को हराने का आग्रह किया। बाइडन ने कहा, मैं टीम से कहना चाहूंगा कि उन्हें (कमला हैरिस) दिल से अपनाएं। वह शानदार हैं। मैं सभी के प्रयासों के लिए उनका आभार जताना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि कल का घटनाक्रम चौंकाने वाला है और इसे स्वीकार करना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यह सही कदम था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि इसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि आपने मुझे इस दौड़ में जिताने के लिए, उम्मीदवारी हासिल करने के लिए, और फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजई बनाने के लिए अपना तन-मन और आत्मा झोंक दी थी। बाइडन ने स्पष्ट किया कि प्रचार टीम का नाम बदल गया है, लेकिन मकसद नहीं। उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कमला के साथ चुनाव प्रचार करूंगा। मैं निवर्तमान राष्ट्रपति के रूप में, कानून पारित कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में कड़ी मेहनत करूंगा।

बाइडन ने कहा, हमें अभी भी लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ट्रंप अभी भी समुदाय के लिए खतरा हैं। वह देश के लिए खतरा हैं। मेरे विदेश नीति सहयोगियों, मेरे समकक्षों और देश-दुनिया के लोगों से पूछें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह कमला का भी पूरे दिल और आत्मा से सहयोग करेंगे।

बाइडन कोविड-19 से लगभग उबरे, जनता से दूरी कायम

रेहोबोथ बीच (अमेरिका)। अमेरिका के राष्ट्रपति के चिकित्सक ने बताया कि जो बाइडन कोविड-19 से लगभग उबर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने सोमवार को लगातार पांचवें दिन जनता से दूरी बनाए रखी। बाइडन ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पत्र पोस्ट कर, अगले राष्ट्रपति की दौड़ से हटने की घोषणा की थी। उन्होंने इस पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन करने की भी घोषणा की थी। राष्ट्रपति को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद बुधवार देर रात को डेलावेयर में अमेरिकी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था। इसके बाद वह कार में बैठकर डेलावेयर के रेहोबोथ बीच स्थित अपने घर चले गए थे। बाइडन के चिकित्सक डॉ. केविन ओ कोनोर ने कहा, राष्ट्रपति संक्रमण से लगभग उबर चुके हैं। उनकी धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर और तापमान पूरी तरह सामान्य बना हुआ है।

नेपाल को हराकर भारत महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में

भाषा। दाम्बुला

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की 48 गेंद में 81 रन की ताबड़तोड़ पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत ने तीन विकेट पर 178 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को नौ विकेट पर 96 रन पर रोक दिया।

भारत ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई जबकि नेपाल का सफर तीन मैचों में एक जीत से दो अंक के साथ खत्म हो गया। इस ग्रुप से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के तीन मैचों में चार अंक है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 13 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि राधा यादव और अरुंधति रेड्डी को दो-दो सफलता मिली। रेणुका सिंह को एक विकेट मिला।नेपाल के लिए सीता राणा मागर ने 18 जबकि बिंदु रावल ने नाबाद 17 रन बनाए। रुबीना छेत्री (15) और कप्तान इंदु वर्मा (14) भी दहाई में रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल रही। शेफाली ने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाने के अलावा डी हेमलता के साथ पहले विकेट के लिए 84 गेंद में 122 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरूआत दिलाई। हेमलता ने 42 गेंद की पारी में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 47 रन का योगदान दिया।

आखिरी ओवरों में जेमिमा रोड्रिग्स ने 15 गेंद में पांच चौके की मदद से नाबाद 28 रन की पारी खेलीनेपाल के लिए सीता राणा मागर ने दो और कविता जोशी ने एक विकेट लिया।लक्ष्य का बचाव करते हुए अरुंधति ने दूसरे ओवर में समझना खड़का (सात) को बोल्ड कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। कविता कुंवर और सीता राण ने इस गेंदबाज के अगले ओवर में एक-एक चौके के साथ आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश की। रेणुका ने पांचवें ओवर में कविता (छह) को पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं राधा ने इंदु को चलता किया।नेपाल को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को 10.2 ओवर में जीतना था लेकिन टीम 10 ओवर में तीन विकेट पर 48 रन ही बना सकी थी।सीता राणा ने 11वें ओवर में अरुंधति के दूसरे स्पैल का स्वागत चौके से किया लेकिन इस गेंदबाज ने अगली गेंद पर उन्हें बोल्ड कर दिया। रुबिना ने दीप्ति के गेंद पर पारी का पहला छक्का जड़ा लेकिन इस ऑफ स्पिनर की अगली गेंद पर बोल्ड हो गई।इसी ओवर में कविता जोशी खाता खोले बगैर पगबाधा हो गई।दीप्ति ने इसके बाद शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए पूजा महतो (दो) को रन आउट किया तो वही राधा ने 17वें ओवर में डॉली भट्टा को विकेट के पीछे लपकवाया। बिंदु ने अरुंधति के खिलाफ चौका जड़कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की लेकिन वह टीम के रनों का शतक पूरा करने में सफल नहीं रही। भारतीय टीम ने इस मैच में नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरफनमौला पूजा वस्त्राकर को विश्राम दिया। शेफाली वर्मा के साथ मैच में टीम की अगुवाई कर रही स्मृति मंधाना की जगह हेमलता ने भारतीय पारी का आगाज किया।शेफाली ने पहले ओवर में कविता कुंवर और चौथे ओवर में शबनम राय के खिलाफ दो-दो चौके जड़कर एक बार फिर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। दूसरे छोर से संभल कर खेल रही हेमलता ने पूजा के खिलाफ दर्शनीय चौका जड़ आत्मविश्वास हासिल किया। भारतीय टीम ने छठे ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया। शेफाली ने अगले ओवर में रुबीना के खिलाफ छक्का और चौका लगाया तो वहीं हेमलता ने आठवें ओवर में कविता जोशी के खिलाफ ऐसा किया। शेफाली ने इसी ओवर में चौका जड़ने के बाद एक रन के साथ 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

शेफाली जहां नेपाल की गेंदबाजों के खिलाफ मन मुताबिक रन जुटा रही थी तो वहीं हेमलता को गैप ढूंढने में परेशानी हो रही थी।सीता राणा ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हेमलता को आउट कर नेपाल को पहली सफलता दिलाई। उनके अगले ओवर में आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शेफाली भी स्टंप हो गई। वस्त्राकर की जगह टीम में आई संजीवन सजना कुछ खास नहीं कर सकी और 12 गेंद में 10 रन बनाकर कविता जोशी का शिकार बन गई।

पीसीबी ने भारत को पाकिस्तान आने के लिए मनाने का काम आईसीसी पर छोड़ा

भाषा। कराची

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अगले साल की शुरुआत में होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए मनाने का काम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पर छोड़ दिया है। पीसीबी के एक सूत्र के अनुसार कोलंबो में हाल ही में हुई आईसीसी की बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को मंजूरी दी गई थी लेकिन कार्यक्रम और प्रारूप पर चर्चा नहीं हुई। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा, पीसीबी ने अब वह कर दिया है जो चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में उससे अपेक्षित था। उसने प्रतियोगिता का मसौदा कार्यक्रम और प्रारूप सौंप दिया है तथा प्रतियोगिता के लिए बजट भी सौंप दिया है। उन्होंने कहा, अब यह आईसीसी पर निर्भर है कि वे चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को कितनी जल्दी प्रसारित, चर्चा और अंतिम रूप देते हैं। पीसीबी ने मसौदा कार्यक्रम में भारत के सभी मैचों की मेजबानी लाहौर में करने का सुझाव दिया है जिसमें सेमीफाइनल (अगर भारत क्वालीफाई करता है) और फाइनल भी शामिल है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान के रूप में आईसीसी के साथ अपनी रुचि के दस्तावेज में सभी विवरण पहले ही सौंप दिए हैं।

उन्होंने कहा, पीसीबी ने अपनी ओर से आईसीसी को कर से जुड़े नियमों, स्थल चयन और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम की मेजबानी के लिए अपनी सरकार से मंजूरी के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी है। सूत्र ने खुलासा किया कि पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने आईसीसी बैठकों के इतर बीसीसीआई सचिव जय शाह या किसी अन्य बीसीसीआई अधिकारी के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं की लेकिन बैठकों के दौरान नकवी और शाह के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण रही। पीसीबी ने अब टूर्नामेंट के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और घोषित करने तथा बीसीसीआई से यह पुष्टि प्राप्त करने का काम आईसीसी पर छोड़ दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा करेगी या नहीं। आईसीसी ने अपने टूर्नामेंट बजट में सप्लीमेंटरी (पूरक) खर्चे को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रखा है जिसमें भारतीय टीम के पाकिस्तान के बाहर अपने मैच खेलने की संभावना भी शामिल है।

बीसीसीआई ने हमेशा से कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से सरकार का फैसला है और यहां तक कि पीसीबी की मेजबानी में हुए 2023 एकदिवसीय एशिया कप में भारत ने हाइब्रिड मॉडल के आधार पर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। मसौदा कार्यक्रम के अनुसार संभावित सेमीफाइनल और फाइनल सहित भारत के सभी मैच लाहौर में निर्धारित किए गए हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच एक मार्च को निर्धारित किया गया है। इस बीच अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में खेलने का आश्वासन दे दिया है। आईसीसी की वार्षिक बोर्ड बैठक में भाग लेने कोलंबो गए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मीरवाइज अशरफ और सीईओ नसीब खान ने नकवी से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। पीसीबी ने कहा, उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि अफगानिस्तान अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए उत्सुक है क्योंकि वे पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, बीसीसीआई के टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजने का फैसला करने पर कुछ देशों के भारत की राह पर चलने की अटकलों के बीच उन्होंने यह आश्वासन दिया।

महिला टी20 रैंकिंग : हरमनप्रीत, शेफाली संयुक्त 11वें और मंधाना पांचवे स्थान पर

दुबई। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में पांचवां स्थान बनाए रखा है जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा संयुक्त 11वें स्थान पर हैं। हरमनप्रीत को एक पायदान का फायदा मिला जबकि शेफाली बल्लेबाजों की सूची में चार पायदान ऊपर आ गई। शीर्ष 20 में भारत के चार खिलाड़ी हैं। जेमिमा रौड्रिग्स 19वें स्थान पर हैं। रिचा घोष 24वें स्थान पर है। बेथ मूनी 769 अंक लेकर शीर्ष पर है। गेंदबाजों की सूची में आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर है जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह नौवे स्थान पर है। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव 20वें स्थान पर है। इंग्लैंड की सोफी एस्सेलेटोन शीर्ष पर हैं।

भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में असालांका होंगे श्रीलंका के कप्तान

पाल्लेकल। चरित असालांका भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में श्रीलंका के कप्तान होंगे। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है।हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असालांका ने इस साल की शुरूआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी जब हसरंगा निलंबन झेल रहे थे। श्रीलंका के पूर्व अंडर 19 कप्तान असालांका ने इस साल एलपीएल में जाफना किंग्स को अपनी कप्तानी में खिताब दिलाया था। भारतीय टीम सोमवार की रात को यहां पहुंच गई।

श्रीलंका टीम : चरित असालांका (कप्तान), पाथुम निसांका, कुसल जनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीष तीक्षणा, चामिंदु विक्रमसिंघे, मथीसा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंता चामीरा, बिनुरा फर्नांडो।

पाकिस्तान ने यूएई को 10 विकेट से रौंदा, सेमीफाइनल का दावा मजबूत

दाम्बुला(भाषा)। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा के नाबाद अर्धशतक से पाकिस्तान ने महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में यूएई को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। यूएई के 104 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुल की 55 गेंद में आठ चौकों से नाबाद 62 रन की पारी और मुनीबा अली (नाबाद 37) के साथ उनकी पहले विकेट की अटूट शतकीय साझेदारी से पाकिस्तान ने 14.1 ओवर में बिना विकेट खोए 107 रन बनाकर बेहद आसान जीत दर्ज की।

यूएई की टीम इससे पहले सादिया (11 रन पर दो विकेट), तुबा हसन (17 रन पर दो विकेट) और नासरा संधू (22 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने आठ विकेट पर 103 रन ही बना सकी। यूएई की ओर से सलामी बल्लेबाज तीर्था सतीश ने 36 गेंद में पांच चौकों की मदद से सर्वाधिक 40 रन बनाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज और कप्तान ईशा ओझा (16) और खुशी शर्मा (12) ही दोहरे अंक तक पहुंच पाए। इस जीत से पाकिस्तान के तीन मैच में दो जीत से चार अंक हो गए हैं और टीम का सेमीफाइनल में जगह बनाने का दावा मजबूत हो गया है। यूएई की टीम तीनों मैच हारकर बाहर हो चुकी है।शाम को दूसरा मैच गत चैंपियन भारत और नेपाल के बीच होगा। भारत दो मैच में दो जीत से चार अंक के साथ शीर्ष पर है जबकि नेपाल दो अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

आईओए ने बीपीसीएल को चार साल के लिए मुख्य प्रायोजक बनाया: नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को पेरिस ओलंपिक से 2028 लॉस एंजिल्स खेलों तक चार साल के लिए अपना आधिकारिक मुख्य प्रायोजक नामित किया। महारत्न कंपनी बीपीसीएल और आईओए के बीच सहयोग में राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, युवा ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन युवा ओलंपिक भी शामिल होंगे। इस सहयोग के तहत बीपीसीएल पेरिस जाने वाले भारतीय दल का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए अभियानों की श्रृंखला शुरू करेगा। इन पहलों का उद्देश्य राष्ट्र को प्रेरित करना, खिलाड़ियों के लिए समर्थन जुटाना और वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता के लिए उनकी निरंतर खोज का जश्न मनाना है।

एमसीए चुनाव: संजय नाईक को हराकर अजिंक्य अध्यक्ष बने

मुंबई। अजिंक्य नाईक मंगलवार को यहां अपने प्रतिद्वंद्वी संजय नाईक को 107 मतों से हराकर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के नए अध्यक्ष बन गए। एमसीए के निवर्तमान सचिव अजिंक्य ने 221-114 के अंतर से एकतरफा जीत दर्ज की। सैंतीस साल के अजिंक्य को अनुभवी राजनेता और बीसीसीआई के साथ-साथ आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार का समर्थन प्राप्त था। वह एमसीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी संजय एमसीए के मौजूदा उपाध्यक्ष हैं। उन्हें आशीष शेलार समूह का समर्थन प्राप्त था। भाजपा नेता शेलार बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी हैं। टी20 विश्व कप के दौरान न्यूयॉर्क में अमोल काले के असामयिक निधन के बाद चुनाव प्रक्रिया चार जुलाई को शुरू हुई थी। अजिंक्य ने यहां जारी बयान में कहा, यह जीत अमोल काले की अनुकरणीय उपलब्धि का प्रमाण है। मेरा प्रयास मुंबई क्रिकेट की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को दोहराना और उनकी विरासत को आगे ले जाना होगा। चुनावों में कुल 335 मत डाले गए। मतदान करने वालों में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता एवं राष्ट्रीय और मुंबई के पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर, जहीर खान, संजय मांजरेकर, बलविंदर सिंह संधू और पारस म्हाम्ब्रे भी शामिल थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े दो मौजूदा सहित आठ खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

भाषा। नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय की मौजूदा छात्र निशानेबाज रमिता जिंदल और रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक के लिए चुने गए भारतीय खिलाड़ियों के 117 सदस्यीय दल में शामिल हैं। रमिता और रिदम के अलावा विश्वविद्यालय के छह पूर्व छात्र भी पेरिस में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। हंसराज कॉलेज की बी. कॉम अंतिम वर्ष की छात्रा रमिता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाज रिदम लेडी श्रीराम कॉलेज में अंग्रेजी (ऑनर्स) की पढ़ाई कर रही है। रिदम के कॉलेज की सीनियर पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। बिहार विधानसभा में भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह (महिला ट्रैप निशानेबाजी) ने 2012 में हंसराज कॉलेज से बीए प्रोग्राम किया था। स्कीट निशानेबाज महेश्वरी चौहान और ट्रैप निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी भी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हैं। महेश्वरी ने 2017 में लेडी श्री राम कॉलेज से फिलॉसफी (ऑनर्स) की पढ़ाई की, जबकि राजेश्वरी 2010 में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज की बीए प्रोग्राम की छात्रा थीं। राजेश्वरी एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) की कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह की बेटी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल निदेशक अनिल कुमार कलकल ने बताया कि एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जीसस एंड मैरी कॉलेज से समाजशास्त्र (ऑनर्स) की पढ़ाई की है। ट्रैक एवं फील्ड में 400 मीटर के धावक अमोज जैकब ने 2016 से 2019 के बीच श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बी.कॉम किया है। वह चार गुणा 400 मीटर पुरुष रिले टीम का अभिन्न अंग हैं। कलकल ने बताया कि इन खिलाड़ियों के अलावा मनु के व्यक्तिगत कोच जसपाल राणा भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे है। उन्होंने अरविंदो कॉलेज से पढाई की है। कुलपति योगेश सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सराहनीय प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पदक जीतेंगे।

विश्वास, टीम भावना पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम की सफलता की कुंजी : फुल्टोन

नई दिल्ली। पिछले साल भारतीय पुरुष हॉकी टीम से जुड़े कोच क्रेग फुल्टोन का लक्ष्य आपसी विश्वास मजबूत करना था और उन्हे यकीन है कि उनके प्रयासो का नतीजा पेरिस ओलंपिक मे पदक के बेहतर रंग के रूप मे मिलेगा। चौदह महीने पहले पदभार संभालने वाले फुल्टोन ने पीटीआई से कहा , मुझे नही पता कि तोक्यो ओलंपिक से पहले क्या तैयारियां थी लेकिन 14 महीने पहले मेरे आने के बाद से फोकस खिलाड़ियों मे आपसी विश्वास बेहतर करने पर रहा है। उन्होने बेहतर नतीजो के लिए दक्षिण अफ्रीका के मानसिक अनुकूलन कोच पैडी उपटन की सेवाएं ली जो 2011 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके है। उपटन टीम के साथ पेरिस मे है। मानसिक दृढता के लिए उन्होने इस महीने की शुरूआत मे स्विटजरलैंड के माइक हेर्नस बेस मे तीन दिन का शिविर लगाया। फुल्टोन ने कहा , मैने अल्पकालिन और दीर्घकालिन रणनीति बनाई और उसके हिसाब से काम किया। उन्होने कहा , हमारी तैयारियां अच्छी रही और स्विटजरलैंड मे तीन दिन का शिविर बहुत अच्छा साबित हुआ। हमने आपसी विश्वास, टीम भावना और एकजुटता बढाने पर काम किया। इसके बाद नीदरलैंड मे नौ दिन अभ्यास किया और कुछ अभ्यास मैच भी खेले। तोक्यो ओलंपिक मे 41 साल बाद कांस्य पदक विजेता से अपेक्षाओ के बारे मे उन्होने कहा , मुझे अपेक्षाओ का पता है और मै इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। भारत का हॉकी का गौरवमई इतिहास रहा है और हम उस विरासत को आगे बढाना चाहते है। उन्होने कहा , मै पोडियम पर रहने के बारे मे कयास नही लगा सकता क्योकि ओलंपिक मे 12 टीमो के बीच ज्यादा अंतर नही है। पहले तीन मैच अहम है जिन पर फोकस रहेगा।

असम के मुख्यमंत्री ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आर्डर मिलने पर बधाई दी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट मे उनके असाधारण योगदान के लिए ओलंपिक आर्डर मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा , उम्मीद है कि वह आने वाली पीढियो को खेलो मे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने बिंद्रा को बताया कि उन्हे ओलंपिक आर्डर दिया गया है और पुरस्कार समारोह 10 अगस्त को पेरिस मे आईओसी के 142वे सत्र के दौरान होगा। असम सरकार ने गुवाहाटी और जोरहट मे दो हाई परफार्मेंस खेल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने के लिए असम सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 250 सरकारी और गुवाहाटी के निजी स्कूलो मे ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (ओवीईपी) लागू करने के लिए भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए है। इसका मकसद बदलती जीवन शैली, एकाग्रता के अभाव और स्कूल से बच्चो का नाम वापिस लेने जैसी समस्याओ से निपटना है।

पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेंगे एंडी मेर्रे

पेरिस। दो बार ओलंपिक पुरुष एकल चैंपियन एंडी मेर्रे ने मंगलवार को पुष्टि की कि पेरिस ओलंपिक के बाद वह खेल से संन्यास लेंगे। सैंतीस वर्ष के मेर्रे ने एक्स पर पोस्ट किया , अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया हूं। पेरिस ओलंपिक मे टेनिस स्पर्धा रोलां गैरो पर शनिवार से शुरू होगी। मेर्रे ने पहला स्वर्ण पदक 2012 लंदन ओलंपिक मे ग्रासकोर्ट पर जीता था जिसमे उन्होने रोजर फेडरर को तीन सेटो मे हराया था। इसके बाद 2016 मे रियो दि जिनेरियो मे हार्डकोर्ट पर जुआन मार्टिन देल पोत्रो को हराकर खिताब जीता था। मेर्रे ने 2019 मे कूल्हे की प्रत्यारोपण सर्जरी कराई थी।

पेरिस ओलंपिक से पहले असम के लोगों ने लवलीना को शुभकामनाएं दी

गुवाहाटी। पेरिस खेलो मे अपने दूसरे ओलंपिक पदक की तैयारी कर रही स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को उनके गृह राज्य असम से गमोसा (अंग वस्त्र), चॉकलेट और दिल के छूने वाले संदेशो के रूप मे शुभकामनाएं दी गईं। मंगलवार को यहां एक समारोह के दौरान शुभचिंतको के साथ उभरते खिलाड़ियों से लेकर सीनियर खिलाड़ियों ने एक बड़े बोर्ड पर लवलीना के लिए संदेश लिखे जबकि उनकी बहन की सास ने एक गमोसा और चॉकलेट पैक करके भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) के महासचिव हेमंत कलिता को सौपी। अगले हफ्ते पेरिस जाने वाले कलिता ने समझाया कि चॉकलेट पिघल सकती है और गमोसा पर दाग लग सकता है जिसके बाद महिला ने अनिच्छा से चॉकलेट वापस ले ली। लवलीना की बहन लीमा ने अपनी सास और बेटे के साथ हस्ताक्षर अभियान मे भाग लेते हुए कहा, यह उनके प्रति हमारे स्नेह की गहराई को दर्शाता है। हमे विश्वास है कि वह अपनी पिछली उपलब्धियो से बेहतर करेगी।

भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू किया अभ्यास

पाल्लेकल (श्रीलंका)। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की देख रेख में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला से पहले यहां अपने शुरूआती अभ्यास सत्र में मैदान पर उतरी। दिग्गज राहुल द्रविड़ की जगह कोच बने गंभीर ने मैदान पर टीम का नेतृत्व किया और अभ्यास सत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान खिलाड़ियों ने हलका अभ्यास किया जिसमें क्षेत्ररक्षण अभ्यास, दौड़ने और गेंद को पकड़ने का अभ्यास शामिल था। इस दौरान टीम के खिलाड़ी टी 20 अंतरराष्ट्रीय टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ बातचीत करते देखे गए। गंभीर ने बल्लेबाजी अभ्यास कर रहे संजू सैमसन के साथ बातचीत करने के बाद मैदान पर हरफनमौला शिवम दुबे के साथ समय बिताया। भारत के पूर्व हरफनमौला अभिषेक नायर और नीदरलैंड के बल्लेबाज रयान टेन डोशेट श्रीलंका दौरे के लिए गंभीर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। इन तीनों ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को आईपीएल 2024 खिताब दिलाने के लिए सहयोग किया था। राष्ट्रीय टीम के साथ उनका पहला कार्य 27 जुलाई को टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के साथ शुरू होगा जिसके बाद तीन वनडे मैच होंगे। द्रविड़ के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप टीम के साथ बने हुए है। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से जुड़े साईराज बहुतुले इस दौरे में अंतरिम गेंदबाजी कोच के रूप में काम करेंगे।

एसीटी से पहले हॉकी इंडिया ने ओलंपिक टीम से इतर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शिविर में बुलाया

नई दिल्ली,। हॉकी इंडिया ने सितंबर में चीन में होने वाली एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरू में सीनियर पुरूष टीम के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में उन खिलाड़ियों को बुलाया है जो पेरिस ओलंपिक की टीम का हिस्सा नहीं हैं। इसमें विकास ग्रुप और जूनियर पुरूष हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं। ओलंपिक टीम में शामिल खिलाड़ी छोटे ब्रेक के बाद 24 अगस्त से राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे जो चार सितंबर तक चलेगा।मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने हॉकी इंडिया द्वारा यहां जारी विज्ञप्ति में कहा , सीनियर टीम पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरूआत की तैयारी में जुटी है लेकिन हमारे पास उससे इतर भी खिलाड़ियों का मजबूत पूल है जो भारत के लिए फिर खेलने के मौके के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा , एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी ओलंपिक के कुछ सप्ताह बाद ही है लिहाजा इसके लिए बेंगलुरू के साइ केंद्र में शिविर लगाया जा रहा है। ए खिलाड़ी उसके लिए तैयारी करेंगे।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।